



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] शही विल्सनी, शनिवार, 27 सितम्बर, 1975/ग्राहितन 5, 1897

NO. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में चिन्ह पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—भाग 3—उप-भाग (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(एक संघातम की छोड़कर) भारत सरकार के संघातमों और (संघ राष्ट्र क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सार्विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazette of India Extraordinary were published up to the 31st March 1975 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
107.	का० शा० 146(ए) विनाक 19 मार्च, 1975	उत्तोग संथा नागरिक पूर्ति संबंधालय	मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी (वैगन्ज डिवीजन) मोकाया, विहार द्वारा 15 फरवरी, 1974 से पूर्ण किये गये या दिये गये और इस आदेश के निकाले जाने के दिनाक से ठीक पूर्व प्रबूत सभी सविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, घ्यवस्थाओं पत्रों, स्थायी प्राविष्टों या अन्य लिखतों के प्रवर्तन तथा उक्त विनाक से पूर्व उनके अधीन प्रोत्तृत या उद्धृत होने वाले सभी अधिकारों, विधेयाधिकारों, वाध्यताओं संथा दायित्वों का नियमित करना।

S.O. 146(E) dated the 19th March, Ministry of Industry and
1975. and Civil Supplies.

Suspending operation of Contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into given or made by Messrs Britannia Engineering Works (Wagons Division) Mokameh, Bihar before the 15th February, 1974 and inforce before the date of issue of the order, along with all the rights, obligations, privileges and liabilities accruing or arising thereunder before the said date.

1	2	3	4
108. का० आ० 147(ग) दिनांक 20 मार्च, 1975	उच्चोग ग्रोद नागरिक पूर्ति मंत्रालय	रिचर्ड्सन एण्ड कूडारा लिमिटेड (उपक्रम अर्जन घोर प्रन्तरण अधिनियम, 1972 (1972 का 78) के अधीन नियमों का बनाना।	
S.O. 147(E) dated the 20th March, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Making rules under the Richardson and Cruddaa Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972 (78 of 1972).	
109. का० आ० 148(ग) दिनांक 20 मार्च, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	सम्मिश्र बोर्ड (सम्मिश्र आसाम राज्य के लिए आसाम राज्य विद्युत बोर्ड) के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 61) की आरा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करना।	
S.O. 148(E) dated the 20th March, 1975	Ministry of Energy	Making order in exercise of the powers conferred by Section 87 of the North-Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 (81 of 1971) in regard to the Composite Board (Assam State Electricity Board, constituted for the Composite State of Assam).	
का० आ० 149 (ग)	ऊर्जा मंत्रालय	यह नियम करने के लिए आदेश करना कि आसाम राज्य विद्युत बोर्ड तथा मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सम्मिश्र आसाम राज्य के लिए गठित आसाम राज्य विद्युत बोर्ड के उपक्रम, आस्तिथां, अधिकार, दायित्व और कर्मचारी तथा विनियिष्ट प्रहण कर लिये जायेंगे।	
S.O. 149(E) dated the 20th March, 1975	Ministry of Energy	Making order to direct that the undertakings, assets, rights, liabilities and employees of the Assam State Electricity Board constituted for the composite State of Assam shall be taken over by the Assam State Electricity Board and Meghalaya State Electricity Board as specified.	
110. का० आ० 150(ग), दिनांक 21 मार्च, 1975	पेट्रोलियम ग्रोद रसायन मंत्रालय	भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन, आम और ज्ञात संतालय के आदेश सं० का० आ० 1873, 18 मई, 1970 में संशोधन।	
S.O. 150(E), dated the 21st March, 1975.	Ministry of Petroleum and Chemicals.	Amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals No. S.O. 1873, dated 18th May, 1970.	
111. का० आ० 151(ग)। 18 चब/आई० डी० ग्राह० ए०/७५ दिनांक 21 मार्च, 1975	उच्चोग ग्रोद नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मैसर्स एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर के संबंध में इस आदेश के निकाले जाने के दिनांक से पूर्व प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों करारों, पंचाटों, स्थानी आदेशों या अन्य लिखतों और उक्त दिनांक से पूर्व उनके अधीन प्रोद्धृत या उद्धृत होने वाले भक्षिकारों, विशेषाधिकारों, आधिकारों तथा दायित्वों का निलिखित करना।	
S.O. 151(E)/18 FB/IDRA/75, dated the 21st March, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Suspending operation of contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in regard to M/s. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur in force before the date of issue of this order and rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date.	
112. का० आ० 152(ग), दिनांक 25 मार्च, 1975	भारत परिसीमन आयोग	विहार राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमित के लिए भारत परिसीमन आयोग की प्रस्थापनाएं सहयुक्त सदस्यों की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित और 22 अप्रैल, 1975 वह विसांक है जिसको या जिसके बाद उक्त प्रस्थापनाओं पर विचार करता है।	

1	2	3	4
		S.O. 152(E), dated the 25th March, Delimitation Commission, India.	Proposals of the Delimitation Commission, India for delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Bihar with the dissenting proposals of Associate members and 22nd April, 1975 is the date on or after which the proposals are to be considered.
113.	का० आ० 153 (अ), दिनांक 25 मार्च, 1975 वित्त मंत्रालय		प्रधिसूचना सं० का० आ० 225(अ), दिनांक 30 मार्च, 1974 को अतिकाल करते हुए सात सात प्रतिशत दर के रूप में नियत करना जो आयकर प्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की वसुर्य ग्रन्तियों के भाग-क के नियम 6 के अन्दर (ब) में संवधित की गई है।
	S.O. 153(E), dated the 25th March, Ministry of Finance 1975.		In supersession of notification No. S.O. 225(E), dated the 30th March, 1974 fixing seven and a half per cent as the rate referred to in clause (b) of Rule 6 of Part A of the Fourth Schedule to the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
114.	का० आ० 154 (अ), दिनांक 26 मार्च, 1975 उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		ट्रैक्टर (वितरण और वितरण) नियमण आदेश, 1971 में संशोधन करने के लिये आदेश।
	S.O. 154(E), dated the 26th March, Ministry of Industry and Civil Supplies.		Order to amend the Tractors (Distribution and State) Control Order, 1971.
115.	का० आ० 155(अ), दिनांक 26 मार्च, 1975 उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		आदेश सं० का० आ० 322(अ), दिनांक 24 मई, 1974 का शुद्धि-पत्र।
	S.O. 155(E), dated the 26th March, Ministry of Industry and Civil Supplies.		Corrigendum to Order No. S.O. 322(E), dated the 24th May, 1974.
116.	का० आ० 156(अ) / 18ए/आई० डी० आर० उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ए०/75, दिनांक 26 मार्च, 1975		भूसंपूर्य औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725 (अ) / 18ए/आई० डी० आर० ए०/72 दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में संशोधन।
	S.O. 156(E)/18A/IDRA/75, dated the Ministry of Industry and Civil Supplies, 26th March, 1975.		Amendment in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)18A/IDRA 72, dated the 25th November, 1972.
117.	का० आ० 157(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975 श्रम मंत्रालय		कोटा स्थित राजस्थान परमाणु भौतिक प्रायोजना में किसी औद्योगिक विद्युत से संबंधित हड्डताल की प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 157(E), dated the 29th March, Ministry of Labour 1975.		Prohibiting any strike in connection with any dispute in the Rajasthan Atomic Power Project Kotah.
118.	का० आ० 158(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975 श्रम मंत्रालय		कलकत्ता के नियम के प्रतिष्ठानों में किसी भी विद्युत से संबंधित किसी भी हड्डताल की प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 158(E), dated the 29th March, Ministry of Labour 1975.		Prohibiting any strike in connection with any industrial dispute in the establishments of the Corporation of Calcutta.
119.	का० आ० 159(अ), दिनांक 29 मार्च, 1975 ऊर्जा मंत्रालय		भूतदूर्ब इस्पात, छान और धातु मंत्रालय की प्रधिसूचना सं० का० आ० 3616, दिनांक 10 अक्टूबर, 1968 का अतिकरण करते हुए वरों को, जो कोयले और कोक पर उत्पादन शुल्क के रूप में लागू होनी, नियत करना।
	S.O. 159(E), dated the 29th March, Ministry of Energy 1975.		In supersession of the late Ministry of Steel, Mines and Metals notification No. S.O. 3616 dated the 10th October, 1968 fixation of rates at which the duty of excise shall be levied on coal and coke.
120.	S.O. 160(E), dated the 31st March, Delimitation Commission, India.		Publishing the dissenting proposals received from the Associate Members for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Punjab in addition to those published by Notification No. 282/PB/75 dated the 10th March, 1975.

1

2

3

4

121. का० आ० 161(ग), दिनांक 31 मार्च, 1975 कृषि प्रीर सिवाई मंत्रालय

निवेद देना कि 24 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० का० आ० 52(ग) 31 जुलाई, 1975 तक प्रवृत्त रहेगी।

S.O. 161(E), dated the 31st March, Ministry of Agriculture & Irrigation

& Directing that the Notification No. S.O. 52(E) dated the 24th January, 1975 shall remain in force upto the 31st July, 1975.

122. का० आ० 162(ग), दिनांक 31 मार्च, 1975 श्रम मंत्रालय

नियोजकों को भविष्य निधि के मासिक अभियाय को न्यासी बोर्ड को अन्तरित करने के लिए तथा न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि संचयनों को यथा निविष्ट विनिहित करने के लिए निर्देश देना।

S.O. 162(E), dated the 31st March, Ministry of Labour

Directing the employers to transfer the monthly provident fund contributions to the Board of Trustees and Board of Trustees to invest the provided fund accumulations in the specified manner.

का० आ० 163(ग), दिनांक 31 मार्च, 1975 श्रम मंत्रालय

मविष्य निधि अभियायों के संचयनों, न्यास और अन्य प्राप्तियों को बाध्यकर निर्गमों को कम करके यथा निविष्ट नमूने के प्रनुसार विनिहित करने के लिए निर्देश देना।

S.O. 163(E), dated the 31st March, Ministry of Labour

Directing to invest in accordance with the specified pattern the accumulations out of the provident fund contributions interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings.

123. का० आ० 164(ग), दिनांक 31 मार्च, 1975 वाणिज्य मंत्रालय

दक्षिण अफ्रीका/विश्व परिषद अफ्रीका संघ, रोडेशिया, पाकिस्तान तथा चीन के तिब्बत प्रदेश को छोड़कर किसी भी देश से भारत में निविष्ट अंदरूनी के माल के आयात के लिए सामान्य अनुमति देना।

S.O. 164(E), dated the 31st March, 1975 Ministry of Commerce

Giving general permission to import into India from any country in the world except the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Pakistan and Tibet region of China, any goods of the description specified.

भारत निर्वाचन आयोग

आवेदन

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० आ० 4128.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 116-रामपुर खास निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम शक्तर, शाम किठावा, पोस्ट थरही, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन अधिकारों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

अतः यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्भक्ष सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम शक्तर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है।

[स० उ० प०-वि० स०/116/74(58)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th August, 1975

S.O. 4128.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Shanker, Village Kithwan, P.O. Tharaee, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Shanker to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(58)]

प्रावेश

का० प्रा० 4129.—यतः, निर्बाचिन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचिन के लिए 116-रामपुर बास निर्बाचिन-जेल से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम राज सिंह, ग्राम नरई पुर, काथो, पोस्ट दख्नपुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचिन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

प्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचिन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्बाचिन आयोग एतद्वारा उक्त श्री श्याम राज सिंहको संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/116/74(59)]

ORDER

S.O. 4129.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Raj Singh, Village Naree Pur Kagho, P.O. Dakhwapur, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Raj Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(59)]

प्रावेश

का० प्रा० 4130.—यतः, निर्बाचिन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचिन के लिए 116-रामपुर बास निर्बाचिन-जेल से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामकिशोर, ग्राम हिमातपुर, पोस्ट भुदरहा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचिन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

प्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचिन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

प्रतः अब, उक्त उम्मीदवार को, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचिन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

प्रतः अब, उक्त उम्मीदवार को धारा 10क के अनुसरण में निर्बाचिन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम किशोर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/116/74(60)]

ORDER

S.O. 4130.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Kishor, Village Himayupur, P.O. Bhudaha, District Pratapgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 116-Rampur Khas assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Kishor to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/116/74(60)]

प्रावेश

नहीं विली, 18 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4131.—यतः, निर्बाचिन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचिन के लिए 320-नरईनी निर्बाचिन-जेल से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्र शेखर आश्रम, रामराज परिषद् कुटीर, बोही, चित्रकूट, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचिन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

प्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचिन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

प्रतः अब, उक्त उम्मीदवार एतद्वारा उक्त श्री चन्द्र शेखर आश्रम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/320/74(92)]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4131.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Shekhar Ashram, Ram Raj Parishad Kutir, Khohi Chitrakoot, District Bandan, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Shekhar Ashram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(92)]

आदेश

का० आ० 4132.—यतः निर्बाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचन के लिए 320-नरैनी निर्बाचन-सेवा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महायादीन, गाम व पोस्ट गोक्खिया, जिला बांदा उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायाचित्य नहीं है;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेवा लाल को समद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने प्रौढ होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/320/74(93)]

ORDER

S.O. 4132.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maiya Din, Village and Post Gokhiya, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maiya Din to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(93)]

आदेश

का० आ० 4133.—यतः निर्बाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचन के लिए 320-नरैनी निर्बाचन-सेवा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेवा लाल, मोहल्ला गांधी गंज, अतरा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायाचित्य नहीं है;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेवा लाल को समद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने प्रौढ होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/320/74(94)]

ORDER

S.O. 4133.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mewa Lal, Mohalla Gandhiganj, Atarra, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 320-Naraini assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 16A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mewa Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/320/74(94)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का० आ० 4134.—यतः निर्विचिन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचन के लिए 92-बांगरमऊ निर्बाचन-सेवा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अम्बुल सत्तार, मुहल्ला राहतगंज, पो० सफीपुर, जिला उत्तरा, उत्तर प्रदेश सोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्बाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के प्रभावेवत पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायाचित्य नहीं है;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अम्बुल सत्तार को समद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने प्रौढ होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/92/74(104)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4134.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Sattar, Mohalla Rahatganj, Post Safipur, District Unnao, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 92-Bangarman assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Sattar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/92/74(104)]

आवेदन

का० आ० 4135.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरीशंकर, मुहला 27-दुर्गा प्रसाद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः उक्त उम्मीदवार के अस्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं हैं;

अतः अब, उक्त उम्मीदवार के अस्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए निर्वाचन आयोग की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आवेदन से,

[सं० उ० प्र-वि० स०/57/74(105)]

ORDER

S.O. 4135.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Shanker, Mohalla 27-Durga Prasad, Pilibhit, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 57-Pilibhit assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Shanker to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order,

[No. UP-LA/57/74(105)]

आवेदन

का० आ० 4136.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अध्यतर हुसैन अम्नसारी, मुहला शेखबाद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 10के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अध्यतर हुसैन अम्नसारी को संपद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/57/74(106)]

ORDER

S.O. 4136.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Akhtar Husain Ansari, Mohalla Shekhchand, Pilibhit, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 57-Pilibhit assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Akhtar Husain Ansari to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/57/74(106)]

आवेदन

नईदिल्ली, 25 अगस्त, 1975

का० आ० 4137.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल वारिस खाँ, ग्राम बरहेपुर, पोस्ट अहियापुर, जिला राय बरेली उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 10के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अब्दुल वारिस खाँ को संपद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आवेदन से

[सं० उ० प्र०-वि० स०/109/74(113)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1975

S.O. 4137.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Waris Khan, Village Baraipur, P.O. Ahiyapur, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareli assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Waris Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(113)]

प्रादेश

कांग्रेस 4138.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रम आसरे, ग्राम व पोस्ट नाकुलाहा, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेका दाखिल करने में असफल रहे हैं;

प्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

प्रतः अब, उक्त उम्मीदवार श्री रम आसरे 109 के ग्रन्तुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रमेश चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद् के सभस्य चुने जाने श्रीर होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्दित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/109/74(114)]

ORDER

S.O. 4138.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh Chandra, Tar Talla, Chhoti Bazar, Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rai Bareli assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh Chandra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(114)]

प्रादेश

कांग्रेस 4131.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 109-राय बरेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम आसरे, ग्राम व पोस्ट नाकुलाहा, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेका दाखिल करने में असफल रहे हैं;

प्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, प्रौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

प्रतः अब, उक्त उम्मीदवार 109 के ग्रन्तुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम आसरे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद् के सभस्य चुने जाने श्रीर होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्दित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/109/74(115)]

ORDER

S.O. 4139.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Asrey, Village & P.O. Nakphulaha, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareli assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Asrey to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(115)]

प्रादेश

कांग्रेस 4140.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 105-सरोजीनी नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ईशा मिह, ग्राम रायपुर राजा, डॉ. ईटीन्जा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेका दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री लेवा सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

प्रादेश से

[सं.उ.प्र.वि.स. 10/5/74(117)]

ORDER

S.O. 4140.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chheda Singh, Village Raipur Raja, P.O. Itaunja, District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 105-Sarojini-nagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chheda Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,

[No. UP-LA/105/74(117)]

प्रादेश

का० आ० 4141.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 105-सरोजिनी नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरसिंह यादव, याम कुल्ले लेशा, डा० अर्जुन गंज, जिला सखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी सेवा दाखिल करने में असफल रहे हैं-

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नरसिंह यादव को संसद के किसी भी सदन के लिये किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं.उ.प्र.वि.स. 10/5/74(117)]

ORDER

S.O. 4141.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nar Singh Yadav, Village Kulli Khera, P.O. Arjun-ganj, District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate

for election to the U.P. Legislative Assembly from 105-Sarojini-nagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nar Singh Yadav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/105/74(118)]

का० आ० 4142.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफ़ज़लगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री करन सिंह, ग्राम रत्नपुरा, डा० हरगनपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी सेवा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री करन सिंह को संसद के किसी भी सदन के लिये किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं.उ.प्र.वि.स. 19/74(122)]

ORDER

S.O. 4142.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karan Singh, Village Ratupura, P.O. Harganpur, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(122)]

प्रादेश

का० आ० 4143.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफ़ज़लगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किशन सिंह, मुहुल्ला चाहशीरी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी सेवा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यह: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीक्रिया नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एवं द्वारा उक्त श्री किशन सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं.उ.प्र.वि.स. 19/74(123)]

ORDER

S.O. 4143.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishan Singh, Mohalla Chahserin, Bijnor Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kishan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. UP-LA/19/74(123)]

आवेदन

का० आ० 4144.—यह, निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचित के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचित-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कृष्ण देवी, मोहल्ला कायस्थ सराय, नगिना, जिला विजनीर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यह: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीक्रिया नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एवं द्वारा उक्त श्री नर्सूर सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं.उ.प्र.वि.स. 19/74(124)]

ORDER

S.O. 4144.—Whereas the election Commission is satisfied that Shri Nathu Singh, Village Ghauspur Sadat, P.O. Kotwali, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for

election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathu Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(124)]

आवेदन

का० आ० 4145.—यह, निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचित के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचित-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कृष्ण देवी, मोहल्ला कायस्थ सराय, नगिना, जिला विजनीर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यह: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीक्रिया नहीं है;

अतः अब, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं.उ.प्र.वि.स. 19/74(125)]

ORDER

S.O. 4145.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Kripo Devi, Mohalla Kaysth Sarai, Nagina, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Kripo Devi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74(125)]

प्रावेश

का० प्रा० 4146.—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 10-अल्मोड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरीश चन्द्र मेल्कानी, ग्राम नीनू पहाड़ी (जलना), आकर्णा पहाड़पानी, जिला नैनीताप, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रयोक्ता प्रपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अप्पावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोक्तित नहीं हैं;

यतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री गिरीश चन्द्र मेल्कानी जी संघद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथमा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन बर्ष की कालावधि के लिये निर्वाचित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/373/74(128)]

ORDER

S.O. 4146.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girish Chandra Melkani, Village Neelpahri (Jalna), P.O. Paharpuri, District Nainital, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 10-Almora assembly constituency, has failed to lodge an account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girish Chandra Melkani to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/10/74(126)]

प्रावेश

का० प्रा० 4147.—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 373-अल्मोड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल मतीन, मकान नं. 576, मुहूला कनवरीगंज, अलोग उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रयोक्ता प्रपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथमा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोक्तित नहीं हैं—

यतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री अब्दुल मतीन को संसद् के किसी भी सदन के विस्तीर्ण का विधान सभा प्रथमा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन बर्ष की कालावधि के लिये निर्वाचित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/373/74(128)]

ORDER

S.O. 4147.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Matin, House No. 576, Mohalla Kanwariganj, District Aligarh Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 373-Aligarh assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Matin to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/373/74(128)]

प्रावेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4148.—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि फरवरी 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन के लिए बिका सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दत्तिया मेहर ग्राम फुलमठी, आकर्ण, सकारी, जिला-बोलनगर (उड़ीसा), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रयोक्ता प्रपने निर्वाचन व्ययों का भी कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथमा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोक्तित नहीं हैं—

यतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री दत्तिया मेहर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथमा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन बर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित घोषित करता है।

[सं० उड़ीसा-वि० स०/113/74(1)]

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1975

S.O. 4148.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dutia Meher, Village Phulmuthi, P.O. Sankara, District Bolangir (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Binka constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dutia Meher to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/113/74(1)]

आदेश

का० आ० 4149.—यतः निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए उडीसा विधान सभा के निर्वाचित के लिए बिका सभा निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बासुदेव पाधान, ग्राम बंकीपाली, डाकघर बंडूलमल, जिला बोलनगर (उडीसा), धपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एतद्वारा उक्त श्री बासुदेव पाधान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अधिकार विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वित घोषित करता है ।

[सं० उडीसा-वि०सा०/113/74 (2)]

ORDER

S.O. 4149.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Basudeb Padhan, Village Bankipali, P.O. Beheramal District Bolangir (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Binka constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Basudeb Padhan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/113/74 (2)]

आदेश

मई दिल्ली, 28 प्रगत 1975

का० आ० 4150.—यतः निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचित के लिए 203-देवरिया निर्वाचित-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विजय बहादुर, ग्राम कोल्हवा, पो० १० तथा जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदनीन बनाए गए नियमों द्वारा घोषित धपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये-जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एतद्वारा उक्त श्री विजय बहादुर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अधिकार विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/203/74(131)]

ORDER

New Delhi, the 28th August, 1975

S.O. 4150.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vijay Bahadur, Village Kolhua, Post & District Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 203-Deoria assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vijay Bahadur to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/203/74(131)]

S.O. 4151.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 116C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission of India hereby publishes the order of the Supreme Court of India pronounced on 7 August 1975 on an appeal from the judgment and order dated 23 April 1974, of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in Election Petition No. 9 of 1972.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1159 OF 1974

Vadrevu Bhadri Raju ... Appellant

v.

Kalania Ibrahimbhai Kasambhai & Ors. ... Respondents

ORDER

Appeal not pressed. Dismissed. No costs.

Sd/-
(A. ALAGIRISWAMI) J.

Sd/-

(P. K. GOSWAMI) J.

Sd/-

(N. L. UNTWALIA) J.

NEW DELHI,
August 7, 1975.

[No. 82/GJ/9/72]

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1975

का० आ० 4132.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-इसाली निर्वाचन-भेद से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कमला देवी हरिजन आम बेनीपुर पोस्टमार्ग जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्रीमती कमला देवी हरिजन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सबसे चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/124/74(132)]

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4152.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Kamla Devi Harijan, Village Benipur, Post Mayang, District Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 124-Issauli assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Kamla Devi Harijan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/124/74(132)]

आदेश

का० आ० 4153.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 296-राजपुर निर्वाचन-भेद से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामेश्वर, आम बोस्ट ग्राफिस गौरीकरण, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रामेश्वर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सबसे चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/296/74(133)]

ORDER

S.O. 4153.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rameshwar, Village and P.O. Gauri Karan, District Kanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 296-Rajpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rameshwar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/296/74(133)]

आदेश

का० आ० 4154.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 125-सुल्तानपुर निर्वाचन-भेद से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनोहर लाल जायसवाल, पार्कीस गंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मनोहर लाल जायसवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सबसे चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/125/74(134)]

ORDER

S.O. 4154.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manohar Lal Jaiswal, Parikingsanji, Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 125-Sultanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manoharlal Jaiswal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/125/74(134)]

प्रावेश

का० आ० 4155.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 125-सुलतानपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम उदित, ग्राम प्रतापपुर, जिला सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्भव सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकारण नहीं है;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम उदित को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अधिकार स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

[सं० उ० प्र०-वि० स०/125/74(135)]

ORDER

S.O. 4155.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Udit, Village Pratappur, District Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 125-Sultanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Udit to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/125/74(135)]

प्रावेश

का० आ० 4156.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-चांदा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम ग्रौतार मोहल्ला नवीपुर मुलतानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्भव सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकारण नहीं है;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम ग्रौतार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अधिकार स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/127/74(136)]

ORDER

S.O. 4156.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Avtar, Mohalla Nabipur, Sultanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 127, Chanda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Avtar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years for the date of this order.

[No. UP-LA/127/74(136)]

प्रावेश

का० आ० 4157.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 140-सिंधपौर (ग्र० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इन्द्रपति ग्राम सलेमपुर शाक धमोली जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम 1951 तथा तदीशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्भव सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकारण नहीं है;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री इन्द्रपति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अधिकार स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/140/74(137)]

ORDER

S.O. 4157.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Indrapati, Village Salempur, Post Dhanauli, District Bara Banki, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 140, Sidhaura (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Indrapati to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years for the date of this order.

[No. UP-LA/140/74(137)]

आवेदन

नई, दिल्ली 1 सितम्बर, 1975

का० आ० 4158—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि भाजे 1972 में हुए मणिपुर विधान सभा के निर्वाचन के लिए 36-हीरोक निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मायबम निभाई लैरीरोंगयेल यैरीपोक बी० पी० ओ० यैरीपोक उप खण्ड आष्टवाल, मणिपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदर्थीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वालिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असपतता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उक्त निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकित्य नहीं हैं;

प्रतः यतः उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एसदारा उक्त श्री मायबम निभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[मं० मणि-वि० स०/36/72]

New Delhi, the 1st September, 1975

S.O. 4158.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maibam Nimai, Leirongthel Yairipok, B.P.O. Yairipok, Thoubal Sub-Division, Manipur, a contesting candidate for General Election to the Manipur Legislative Assembly, held in March, 1972 from 36-Heirok constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri Maibam Nimai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MR-LA/36/72]

आवेदन

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1975

का०आ० 4159—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 218-सुधारकुरु निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल सिंह भाल्दे, 192-कुर्मी टोला, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदर्थीन बनाये

गये नियमों द्वारा अनेक अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वालिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकित्य नहीं है;

प्रतः यतः उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एसदारा उक्त श्री गोपाल सिंह भाल्दे को संसद के किसी भी सदन के साथ किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

आवेदन से,

[सं० उ०प्र०-वि०स०/218/74(139)]

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4159.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Singh Aldc, 192, Kurmi Tola, Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 218, Mubarakpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Singh Adle to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/218/74(139)]

आवेदन

का०आ० 4160—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 219-मुद्दमवाबाद गोहाना(भ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महावली प्राम चक्रवर्ज, दाकखाना सुल्तानपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदर्थीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेखा वालिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकित्य नहीं है;

प्रतः यतः उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एसदारा उक्त श्री महावली को संसद के किसी भी सदन के साथ किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/219/74/140]

ORDER

S.O. 4160.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahabali, Village Chaksahja, P.O. Sultanpur, District Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 219. Moham-mabad Gohna (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said act, the Election Commission hereby declares that the said Shri Mahabali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/219/74(140)]

ग्रादेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1975

का० आ० 4161.—यह, निवाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निवाचन के लिये 48-प्रावंत्र सिविल सेवा सेवक सुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोती चन्द्र, पक्का कटरा, तहसील श्रावला, ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 का लिये जानकारी के लिये आयोग का कोई भी लेखा वालिल करने में असफल रहे हैं;

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सद्यक भूचाला दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अधिक साधिकरण नहीं नहीं दिया है, और, निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोचित्य नहीं है;

यह, उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निवाचन आयोग एवं द्वारा उक्त श्री मोती चन्द्र को संसद के किसी भी सरकार के या किसी राज्य की विधान सभा अधिकारी विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस ग्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

ग्रादेश से,

[सं० उ०प्र०-वि०स०/48/74(141)]

ए० एन० सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1975

S.O. 4161.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Moti Chandra, Pucca Katra, Tahsil Aonla, District Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 48, Aonla Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said act, the Election Commission hereby declares the said and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,
[No. UP-LA/48/74(141)]
A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1975

ग्राम-कर

का०आ० 4162.—सर्वेसाधारण की जानकारी के लिये प्रधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, आय-कर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ीदा,

यह प्रधिसूचिता 1-4-1975 से प्रभावी है।

[सं० 1014 (का०सं० 203/37/75-आ०क० प्र०II)]

टी०पी० शुनझुनधाला, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 2nd August, 1975

INCOME TAX

S.O. 4162.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA.

The notification takes effect from 1-4-1975.

[No. 1014 (F. No. 203/37/75-ITA.II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का०आ० 4163.—केन्द्रीय सरकार आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43), की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेश्वी एस० चावला, पी०सी० शर्मा, एस० रामचन्द्रानी, गोर्खन दास और एच०पी०सी० सुंजल को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित प्राधिकारी हैं उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर वसूली प्रधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

प्रधिसूचिता सं० 722 (का०सं० 404/221/74-आई०टी०सी०सी०) तारीख 24 सितम्बर, 1974, 448 (का० सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 27 अगस्त, 1973, 385 (का०सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 18 जून, 1973 और 448 (का०सं० 404/177/73-आई०टी०सी०सी०) तारीख 27 अगस्त, 1973 के प्रधीन की गई क्रमांक: सर्वेश्वी एस० एम० भटनागर, एन० एन० सेठ, जगदेव सिंह यादव, सी० आर० स्लाल और वी० पी० मेहदीरत्ना की नियुक्तियां उस तारीख से रद्द की जाती हैं जिस तारीख को सर्वेश्वी एस० के चावला, श्री पी०सी० शर्मा J, श्री एस० रामचन्द्रानी, श्री गोर्खन दास और श्री एच०पी०सी० सुंजल कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

यह प्रधिसूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को सर्वश्री एस० के० चावला, पी० सी० शर्मा, श्री एस० रामचन्द्रामी, गोर्धन यास और एन० जी० मुंजल कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1015 (फ० सं० 404/35/75-प्राई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 4th August 1975

S.O. 4163.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Sarvashri S. K. Chawla, P. C. Sharma, I. S. Ramchandani, Gordhan Dass and H. G. Munjal, who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

The appointments of Sarvashri M. M. Bhatnagar, N. N. Seth, Jagdev Singh Yadav, C. R. Cyal and V. P. Mehdiratta as Tax Recovery Officers made vide Notifications No. 722 (F. No. 404/221/74-ITCC) dated 24th September, 1974, 448 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 27th August, 1973, 385 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 18th June, 1973 and 448 (F. No. 404/177/73-ITCC) dated 27th August, 1973 respectively, are hereby cancelled with effect from the date Shri S. K. Chawla, Shri P. C. Sharma I, Shri S. Ramchandani, Shri Gordhan Dass and Shri H. G. Munjal, take over as Tax Recovery Officers.

This Notification shall come into force with effect from the date S/Shri S. K. Chawla, P. C. Sharma I, Shri S. Ramchandani, Gordhan Dass and H. G. Munjal take over charge as Tax Recovery Officers.

[No. 1015 (F. No. 404/35/75-ITCC)]

का० आ० 4164.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम० ए० मुख्यमूर्ति को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित प्रधिकारी हैं उक्त प्रधिनियम के अधीन कर वसूली प्रधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

प्रधिसूचना सं० 374 (फा० सं० 404/291/72-प्राई०टी०सी०सी०) तारीख 4 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई श्री ए० कृष्णमूर्ति की नियुक्ति 18 अगस्त, 1975 से रद्द की जाती है।

यह प्रधिसूचना 18 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1017 (फा० सं० 404/94/75-प्राई०टी०सी०सी०)]

S.O. 4164.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri M. A. Subramaniam who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

The appointment of Shri A. Krishnamurthy made under Notification No. 174 (F. No. 404/291/72-ITCC) dated the 4th September, 1972 is hereby cancelled with effect from 18th August, 1975.

This Notification shall come into force with effect from the 18th August, 1975.

[No. 1017 (F. No. 404/94/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

का०आ० 4165.—प्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन प्रधिनियम, 1946 (1946 का 25) द्वारा गठित, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर की पंक्ति के प्रत्येक प्रधिकारी को उक्त उपखंड के प्रयोगों के लिये विनियित करती है।

[सं० 1026 (फा० सं० 403/102/74-प्राई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 8th August, 1975

S.O. 4165.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said sub-clause, every officer of or above the rank of a Superintendent of Police of the Delhi Special Police Establishment, constituted by the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946).

[No. 1026 (F. No. 403/102/74-ITCC)]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का०आ० 4166.—प्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री प्रजीत सिंह और एस० पी० ए० उपल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित प्रधिकारी हैं, उक्त प्रधिनियम के अधीन कर वसूली प्रधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

प्रधिसूचना सं० 1001 (फा० सं० 404/97/75-प्राई०टी०सी०सी०) तारीख 30 जुलाई, 1975 के अधीन की गई श्री जे० बी० भारद्वाज की नियुक्ति रद्द की जाती है।

यह प्रधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को पैरा 1 में वर्णित प्रधिकारी कर वसूली प्रधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1029 (फा० सं० 404/97/75-प्राई०टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 12th August, 1975.

S.O. 4166.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri Ajit Singh and S. P. Uppal who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

The appointment of Shri J. B. Bhardwaj made under Notification No. 1001 (F. No. 404/97/75-ITCC) dated the 30th July, 1975 is hereby cancelled.

This Notification shall come into force with effect from the date the officers mentioned in para 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1029 (F. No. 404/97/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का० का० 4167—ग्रामकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री अनिल कुमार राय, श्रीपी० के० देव मलिक और नीमा दोर्जे लामा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित प्रधिकारी हैं, उक्त प्रधिनियम के अधीन कर वसूली प्रधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

यह प्रधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस सारीख को ऊपर वर्णित प्रधिकारी कर वसूली प्रधिकारियों के रूप में कार्यभार प्रहृण करते हैं।

[सं० 1032 (का० सं० 404/77/75-ग्राम-टी०सी०सी०)]

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4167.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri Anil Kumar Roy, Shri P. K. Deb Mallick and Nima Dorjay Lama, who are Gazette Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

This Notification shall come into force with effect from the date the Officers mentioned above take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1032 (F. No. 404/77/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

ग्रामकर

का० का० 4168—ग्रामकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री पी० एम० वैद्य को, जो केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित प्रधिकारी है, उक्त प्रधिनियम के अधीन कर वसूली प्रधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

प्रधिसूचना सं० 171 (का० सं० 404/274/72-ग्राम-टी०सी०सी०), तारीख 1 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई श्री टी० के० जार्ज कुट्टी की नियुक्ति उस तारीख से रद्द की जाती है जिस सारीख को श्री पी० एम० वैद्य कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार प्रहृण करते हैं।

यह प्रधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस सारीख को श्री पी० एम० वैद्य कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार प्रहृण करते हैं।

[सं० 1041 (का० सं० 404/63/75-ग्राम-टी०सी०सी०)]

श्री पी० मितल, उप-सचिव

New Delhi, the 16th August, 1975

S.O. 4168.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri P. M. Vaidya, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

The appointment of Shri T. K. George Kutty made under Notification No. 171 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated 1st September, 1972 is hereby cancelled with effect from the date Shri P. M. Vaidya takes over as Tax Recovery Officer.

This Notification shall come into force with effect from the date Shri P. M. Vaidya takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1041 (F. No. 404/63/75-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

स्टाम्प

का० का० 4169—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उस शुल्क से जो केरल वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले तेलीस लाख रुपये मूल्य के वधन पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधीन प्रभाव इ०, छूट देती है।

[सं० 36/75-स्टाम्प/फा. सं० 471/47/75-सीमा-शुल्क-7]

ORDER'

New Delhi, the 18th September, 1975

STAMPS

S.O. 4169.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes of the value of thirtythree lakhs of rupees, to be issued by the Kerala Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 36/75-Stamps/F. No. 471/47/75-Cus. VII]

आदेश

का० का० 4170—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि पुनर्वित्त निगम, मुम्बई को उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले सांलह करोड़ और पचास लाख रुपये अंकित मूल्य के वधनपत्रों के रूप में 3456 बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मद्दधे प्रभाव नाँ लाख और नव्वे हजार रुपये मात्र समीकित स्टाम्प शुल्क का संवाद करने की अनुमति देती है।

[सं० 37/75-स्टाम्प/फा. संख्या 471/67/75-सीमा-शुल्क-7]

ORDER

S.O. 4170.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agricultural Refinance Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of Nine lakhs and ninety thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on 3456 bonds in the form of promissory notes of the face value of sixteen crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the said corporation.

[No. 37/75-Stamp/F. No. 471/67/75-Cus. VII]

आदेश

का.आ. 4171.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से जो फर्नाटिक राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले एक साँ सौ तीस लाख और पचास हजार रुपये मूल्य के वचन पत्रों के रूप में बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती हैं।

[सं. 38/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/63/75-सीमा-शुल्क 7]

ORDER

S.O. 4171.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of one hundred thirtyseven lakhs and fifty thousand rupees, to be issued by the Karnataka State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 38/75-Stamp/F. No. 471/63/75-Cus. VII]

आदेश

का. आ. 4172.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो गुजराती विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले, दो करोड़ पचास हजार रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती हैं।

[सं. 39/75-स्टाम्प फा. सं. 471/72-75-सीमा-शुल्क]

ORDER

S.O. 4172.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of two crores and seventy-five lakhs of rupees, to be issued by the National Co-operative Development Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 39/75-Stamp/F. No. 471/72/75-Cus. VII]

आदेश

का.आ. 4173.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो जम्मू-कश्मीर वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले सत्ताहित लाख पचास हजार रुपये मूल्य के छिंवंचरों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती हैं।

[सं. 40/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/65/75-सीमा-शुल्क 7]

ORDER

S.O. 4173.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures to the value of twenty-seven lakhs and fifty thousand rupees, to be issued by the Jammu and Kashmir State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 40/75-Stamp/F. No. 471/65/75-Cus. VII]

आदेश

का.आ. 4174.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस शुल्क से, जो गुजरात राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले साँ सौ तीस लाख और पचास हजार रुपये मूल्य के वचनपत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती हैं।

[संख्या 41/75-स्टाम्प/फा. सं. 471/46/75-सीमा-शुल्क 7]

दी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4174.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of four hundred and forty lakhs of rupees to be issued by the Gujarat State Financial Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 41/75-Stamp/F. No. 471/46/75-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Ninth Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (2) of rule 6 rule of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the pension sanctioning authority, before passing any final order regarding reduction in the amount of pension, or gratuity, or both, shall serve upon the person concerned a notice specifying the reduction proposed to be made in such amount and the grounds therefore, and call upon such person to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time as may be allowed by

that authority, such representation as such person may wish to make against the proposed reauction and take into consideration the representation, if any, submitted by such person before passing the final order."

[No. F.5(3)-EV(A)/72]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
(विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग)

क्षेत्रीय कार्यालय

बंबई, 30 जनवरी, 1975

का० आ० 4176.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का सं० 46) की धारा 13 की उपशारा (2) के अनुसरण में रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति को गैर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये विकासोन्मुख डिजाइन "नियोजित परिवार—सब के लिये घन्नन" के उत्कीर्णन सहित 50 रुपये 10 रुपये और 10 पैसे के मूल्यवर्गों के सिक्कों के रूप में मुद्रा भारत से बाहर ले जाने अथवा भेजने की अनुमति देता है :

परंतु ऐसे देने (अर्थात् गैर व्यावसायिक प्रयोजनों) के लिये भारत से बाहर भेजे जानेवाले प्रत्येक मूल्यवर्ग के सिक्कों की संख्या किसी भी समय दो से अधिक न हो ;

परंतु आगे यह भी कि उपहार देने के प्रयोजन के लिये भारत से बाहर सिक्कों ले जाने के इच्छुक यात्रियों के मामले में सिक्कों की संख्या 50 रुपये और 10 रुपये के प्रत्येक मूल्य वर्ग के 2 सिक्कों से अधिक न हो ;

परंतु यह भी कि जब सिक्कों भारत से बाहर भेजे जाते हैं तब उन्हें भेजने वाला व्यक्ति—

(क) जब गिक्के वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से भेजे जाते हों तब हवाई पतलन अथवा बंदरगाह के सीमा शुल्क प्राधिकारियों,

(ख) जब सिक्के डाक से भेजे जाते हैं तब डाक प्राधिकारियों, को लिखित रूप में यह धोषणा देता है कि भेजे जाने वाले सिक्कों की संख्या और प्रकार इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

अध्यक्षा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये विकासोन्मुख डिजाइन वाले सिक्कों का अर्थ ऐसा सिक्का है जिसे संक्षेप राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1974 को विएव जनसंख्या वर्ष मनाये जाने के लिये विकासोन्मुख डिजाइन सहित जारी किया गया हो।

[स० एफ० ई० आर०ए० 24/75-आर०बी]
प्र० एस० शिरालकर, उप-गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
Central Office .

Bombay, the 30th January, 1975

S.O. 4176.—In pursuance of sub-section (2) of section 13 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, (No. 46 of 1973) the Reserve Bank is pleased to permit any person to take or send out of India for non-commercial purposes currency in the form of Development Oriented Design Coins with the inscription of "Planned Families—Food for All" of denominations of Rs. 50, Rs. 10 and 10 Paise:

Provided that the number of coins of each denomination sent out of India for making gifts (i.e. non-commercial purposes) does not at any one time exceed two;

Provided further that in case of passengers desirous of taking out of India for purposes of presentation, the number of coins does not exceed 2 coins each of denominations of Rs. 50 and Rs. 10;

Provided also that where the coins are being sent out of India, the person sending them out furnishes a declaration in writing that the number and kind of coins sent are in conformity with the requirements of this notification, to—

- the customs authorities at the air or sea port, where the coins are sent out by air or sea;
- the postal authorities, where the coins are despatched by post.

Explanation: For purposes of this Notification, "Development Oriented Design Coin" means a coin bearing a development oriented design issued to mark the year 1974 as World Population year by the United Nations.

[No. F.E.R.-A 24/75-R.B.]

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor.

(संक्षिप्त विवरण)

नई दिल्ली, 20 अगस्त 1975

का० आ० 4177.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के बाण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये, सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के द्वारा अधिकारी उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में, उन्हे सौंपे गये अधिकारियों का प्रयोग तथा सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे ।

तालिका

अधिकारी का पद

सरकारी स्थान के वर्ग स्थान कार्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं

1

2

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
बंबई क्षेत्र, बंबई ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
कलकत्ता क्षेत्र, कलकत्ता ।

पंजाब नेशनल बैंक के या उसकी ओर से किराये पर लिये गये या इसके द्वारा अधिगृहीत वे स्थान जो बंबई के महानगरीय शहर के भीतर स्थित हैं ।

पंजाब नेशनल बैंक के या उसकी ओर से किराये पर लिये गये या इसके द्वारा अधिगृहीत वे स्थान जो कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में स्थित हैं ।

[म० 7(9)बी० आ० III/74]
म० आ० उमगाविकर, प्रबन्ध सचिव

Department of Banking

New Delhi, the 20th August, 1975

S.O. 4177.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)

The Regional Manager, Punjab National Bank, Delhi Region, Delhi. Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab Na-

(1)

(2)

tional Bank and situated within the local limits of the Union Territory of Delhi.

The Regional Manager, Punjab National Bank, Bombay Region, Bombay.

Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab National Bank within the metropolitan city of Bombay.

The Regional Manager, Punjab National Bank, Calcutta Region, Calcutta.

Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Punjab National Bank and situated within the metropolitan city of Calcutta.

[No. 7(9)BO.III/74].

M.B. USGAONKAR, Under Secy.

नई विल्सनी, 6 सितंबर, 1975

का० ४१७८.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अगस्त 1975 के दिनांक 29 को समाप्त हुए सत्राह के लिये सेवा इण विभाग

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	29,84,12,000		सोने का सिक्का और चुलियनः—		
संचलन में नोट	6205,77,05,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,58,000	
जारी किये गये कुल नोट		6235,61,17,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		..
			विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,55,000
			रुपये का सिक्का		15,95,40,000
			भारत सरकार की रुपया प्रति- भूतियां		..
			देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		5915,39,22,000
कुल देयताएँ		6235,61,17,000	कुल आस्तियां		6235,61,17,000

दिनांक : 3 सितंबर, 1975

के, भारत पुरी, गवर्नर

29 अगस्त 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएँ	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूँजी	5,00,00,000	नोट	29,84,12,000
प्रारंभित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,70,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	5,06,000
(दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि	334,00,00,000	द्वारीदे और भुजाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	42,16,38,000
(स्थरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय शौधोगिक ऋण		(ग) सरकारी अज्ञानी बिल	933,79,30,000
(दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बचाव**	603,36,34,000
जमाराशियां—		निवेश**	687,99,24,000

देयताएँ	रुपये	प्रस्तुतियाँ	रुपये
(क) सरकारी		ऋण और प्रग्रामः—	
(i) केन्द्रीय सरकार	52,28,35,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	10,90,89,000	(ii) राज्य सरकारों को †	94,15,41,000
(ख) बैंक		ऋण और प्रग्रामः—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	577,52,32,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को @	37,27,35,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,43,57,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को @@	305,63,58,000
(iii) और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,48,76,000	(iii) दूसरों को	9,83,36,000
(iv) अन्य बैंक	77,36,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, प्रग्राम और निवेश	
(ग) अन्य	1135,93,26,000	(क) ऋण और प्रग्रामः—	
देय बिल	163,96,73,000	(i) राज्य सरकारों को	69,63,80,000
अन्य देयताएँ	706,54,05,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,54,14,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिकालीन बैंकों को	—
		(iv) कृषि पुनर्वित्त नियम को	87,20,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिकालीन बैंकों के डिवेंजरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और प्रग्राम	
		राज्य सहकारी बैंकों को कृषि और प्रग्राम	93,26,14,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, प्रग्राम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और प्रग्राम	320,98,06,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये शांडों/डिवेंजरों में निवेश	
		अन्य आस्तियाँ	347,50,18,000
रुपये	3685,85,29,000	रुपये	3685,85,29,000

*नकदी, आवधिक जमा और प्रल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और प्रग्राम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी और द्वारा जारी किये गये शांडों/डिवेंजरों में निवेश शामिल है।

@भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम की धारा 17(4) (ग) के प्रधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर प्रग्राम दिये गये 23,92,00,000/- रुपये शामिल हैं।

@@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और प्रग्राम शामिल नहीं हैं।
दिनांक: 3 सितंबर, 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर
[स० फ० 10(1)/75-बी० आ० I]
च० व० मीरबच्चानी, प्रवर सचिव

S.O. 4178.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 29th day of August 1975
ISSUE DEPARTMENT
New Delhi, the 6th September, 1975

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	29,84,12,000		Gold Coin and Bullion :-		
Notes in circulation	6205,77,05,000		(a) Held in India	182,52,58,000	
			(b) Held outside India	..	
Total notes issued	6235,61,17,000		Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total	304,26,55,000	
			Rupee Coin	15,95,40,000	
			Government of India Rupee Securities	5915,39,22,000	
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..	
Total liabilities	6235,61,17,000		Total Assets	6235,61,17,000	

K. R. PURI, Governor

Dated the 3rd day of September, 1975.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the
29th August, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	29,84,12,000
		Rupee Coin	2,70,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,06,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	42,16,38,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	933,79,30,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad* Investments**	603,36,34,000
		Loans and Advances to :—	687,99,24,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments†	94,15,41,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks@	37,27,35,000
		(ii) State Co-operative Banks@	305,63,58,000
		(iii) Others	9,83,36,000
(a) Government		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Central Government	52,28,35,000	(a) Loans and Advances to :—	
(ii) State Governments	10,90,89,000	(i) State Governments	69,63,80,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,54,14,000
(b) Banks		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(i) Scheduled Commercial Banks	577,52,32,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,43,57,000	(b) Investments in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,48,76,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
(iv) Other Banks	77,36,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	93,26,14,000
(c) Others	1135,93,26,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
Bills Payable	163,96,73,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	320,98,06,000
Other Liabilities	706,54,05,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	347,50,18,000
Rupees	3685,85,29,000	Rupees	3685,85,29,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

@Includes Rs. 23,92,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 3rd day of September, 1975.

K.R. PURI, Governor.

[F. No. 10/1/75-BO-I]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालिय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

भुवनेश्वर, 24 जुलाई, 1975

का० ना० 4179.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्रमता का सदुपयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालिय, भुवनेश्वर, के उपमाहर्ता को समाहर्ता के प्रधिकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 173 जी (4), के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 1/1975—सी० सं० IV(4) 2-सीई/72]

Collector of Central Excise, Customs

Central Excise

Bhubaneswar, the 24th July, 1975

S.O. 4179.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise in the Collectorate of Central Excise & Customs, Bhubaneswar, to exercise the powers of Collector under rule 173G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[Notification No. 1/1975—C. No. LV(4)2-CE/72]

कलकत्ता, 24 जुलाई, 1975

का० ना० 4180.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्रमता का सदुपयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता के उप समाहर्ताओं को अपनी सीमा के प्रधीन समाहर्ता के प्रधिकार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944 नियम 173 जी (4), के उपयोग की अनुमति देता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 2/1975—सी सं० IV(8) 2-सीई/72]

एच० एल० बनर्जी, समाहर्ता

Calcutta, the 24th July, 1975

S.O. 4180.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collectors of Central Excise in the Collectorate of Central Excise, Calcutta to exercise the powers of Collector under rule 173G(4) of the Central Excise Rules, 1944 in their respective jurisdiction.

[Notification No. 2/1975—C. No. IV(8)2-CE/72]

H. L. BANERJEE, Collector

मदुरै, 25 जुलाई, 1975

का० ना० 4181.—1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के 5वें नियम के प्रधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस कार्यालय की दिनांक 23-9-71 की प्रधिसूचना (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सी० सं० IV/16/83/71 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं एतद्वारा, उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मदुरै को 1944 की केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क नियमावली के 173 जी (1) नियम के प्रधीन (स्व० नि० का० के प्रधीन काम करने वाले,) प्रभिन्निमताओं को प्रार० जी० I प्रल० में लेखे रखने से छूट देने और इन लेखों के स्थान पर प्रभिन्निमताओं के निजी लेखों को स्वीकार करने से सम्बन्धित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्रधिकार प्रदान करता हूँ।

प्राधिकार: दिनांक 5-7-75 का बोर्ड पत्र का० सं० 215/5/74-के० उ० 6

[प्रधिसूचना सं० 2/75-सी० सं० IV/16/55/75-के० उत्पा०-2]

एम० एस० सुदामानियम, समाहर्ता

THE CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Central Excises

Madurai, the 25th July, 1975

S.O. 4181.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in partial modification of this Office Notification (Central Excises) C. No. IV/16/83/71 dated 23-9-1971, I hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise, Madurai, to exercise the powers of Collector under Rule 173G(4) of Central Excise Rules, 1944, and to exempt any manufacturer from maintaining accounts in Form RG 1 (for assessees working under SRP) and to accept the private Accounts of the manufacturer in lieu thereof.

Authority: Board's letter F. No. 215/5/74-CX. 6 dated 5-7-1975.

[Notification No. 2/75—C. No. IV/16/75 CX. 2]

M. S. SUBRAMANYAM, Collector

समाहर्तालिय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बंगलौर, 2 अगस्त, 1975]

का० ना० 4182.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के प्रन्तांत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा, इस समाहर्तालिय के प्रधीनकामों को, उक्त नियमावली के 96-वा० और 96-ड० नियमों के प्रधीन सूती कपड़ों/सूती धार्ता को एक कारखाने से दूसरे कारखाने में ले जाने के लिये भी 5 (प्रल० में) सामान्य बन्ध पत्रों को स्वीकार करते से सम्बन्धित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्रधिकार प्रदान करता हूँ।

[प्रधिसूचना सं० 3/75-सी सं० 8/1/75-ख-2]

द० यार० श्रीकन्तद्या, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Bangalore, the 2nd August, 1975

S.O. 4182.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules 1944, I hereby empower the Superintendents of Central Excise in this Collectorate to accept B-5 General Bonds for the purpose of movement of Cotton Fabrics/Cotton yarn from one factory to another under Rules 96D and 96E of Central Excise, Rules, 1944.

[Notification No. 3/75—C. No. IV/8/1/75 B. 2]

E. R. SRIKANTIA, Collector

कायालिय आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश

बोपाल, 3 सितम्बर, 1975

का० आ० 4183. —आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन दिनांक 31-3-1975 तक के व्यक्तियों की सूची भाग 'अ' के लिये (i)-नी मातृ से अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि एक वर्ष तीन माह से अधिक न हुई हो, भाग 'क' के लिये (ii)-एक वर्ष तीन माह तक उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि दो वर्ष तीन माह से अधिक न हो, भाग 'स' के लिये (iii)-दो वर्ष तीन माह तक उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम और (iv)-भुगतान न की गई कृत रकम के लिये है।

अनुसूची

क्रमांक	नियरितियों के नाम और पूरा पता	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	मे० रामदीन सिंह जौहान एंड क०, युक्तिया	1,56,746	—	25,942	182,688
2.	श्री ए० ए० पटेल, इंदौर	5,429	46,919	—	50,348
3.	श्री ए० ए० भंडारी, इंदौर	211	1,684	142,527	144,422
4.	श्री हुकमीचन्द चिमनलाल, इंदौर	121	76	599,944	560,141
5.	श्री मंगलचन्द चिमनलाल, इंदौर	121	76	554,541	554,738
6.	मे० स्वप्नभ्रतलाल मोटर सर्विस (प्रा०) लि०, इंदौर	1,468	59,560	—	61,028
7.	श्री सगरमल सिंग० ए० बीव, मिल्स लि०, इंदौर	7,310	10,055	102,674	120,039
8.	श्री कवीर अहमद हाजी अब्दुल करीम, भोपाल	25,494	5,656	46,567	77,717
9.	श्री अब्दुल करीम प्रोप० आफ करीम, भोपाल	8,478	3,000	25,133	36,611
10.	श्री अहमद नाथ प्राप० आफ करीम, भोपाल	8,211	2,832	25,952	36,945
11.	श्री कवीर अहमद प्रा० आफ करीम, भोपाल	7,893	2,772	20,427	31,092
12.	श्री रोकसिंह नानकसिंह, इंदौर	—	60,465	—	60,465
13.	मे० यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लि०, ग्वालियर	—	—	100,465	100,465
14.	मे० ए० पी० प्राटोबोवाइल्स (प्रा०) लि०, ग्वालियर	—	—	74,266	74,266
15.	मे० सरदार सिंह अमरसिंह, टिमरसी	—	—	633,810	633,810
16.	श्री गुलाबचन्द यादव, ए०स० ए० ए० ए० बाटेकर, पचमठी	—	—	122,414	122,414
17.	श्री बलबंतसिंह एंड संस, बैतूल	—	—	452,594	452,594
18.	श्री हरजेन्द्रसिंह करतासिंह, बैतूल	—	—	48,078	48,078
19.	मे० जियालाल यामलाल, बैतूल	—	47,212	99,145	146,357
20.	श्री जयबंतसिंह मेहरसिंह, बोरकेही सेह० मुलताई बैतूल	—	—	49,526	49,526
21.	मे० किशनसहाय कुंदनलाल, योड़ोडोगरी, जिला बैतूल	—	—	68,575	68,575
22.	मे० करमसिंह अतरसिंह, योड़ोडोगरी जिला बैतूल	—	—	166,813	166,813
23.	मे० किशनसहाय भागीरथ, योड़ोडोगरी, जिला बैतूल	—	—	45,012	45,012
24.	श्री कन्हैयालाल शोभाराम मेहतो, जुवाई, पी० प्रा० योड़ोडोगरी जिला बैतूल	—	—	28,689	28,689
25.	श्री करमसिंह अतरसिंह, बैतूल	—	—	34,968	34,968
26.	श्री मोतीलाल मेहतो, जुवाई योड़ोडोगरी	—	—	55,764	55,764
27.	मे० पटेल मोतीलाल मेहती एंड क०, जुवाई योड़ोडोगरी	—	—	2,02,700	202,700
28.	श्री रामसिंह केशरसिंह, योड़ोडोगरी	—	—	30,164	30,164
29.	श्री ज्वालासिंह लक्ष्मसिंह, सोहागपुर	—	—	49,484	49,484
30.	श्री अंदनमल, गंज बैतूल	—	—	37,956	37,956
31.	मे० बालसा जुनेजा टिम्बर ट्रेडिंग क०, गु० नौ० टि० मा०, इंदौर प्रोप० शारसिंह	—	—	28,912	28,912
32.	श्री बद्रीनारायण रामेश्वर, इंदौर	—	—	3,47,532	3,47,532
33.	श्री जी० पुष्पतिनाथ, सियांगंज, इंदौर	—	—	43,320	43,320
34.	मे० मंगलचन्द हुकमीचन्द, इंदौर	—	—	3,47,279	3,74,279
35.	मे० महादेव होजरी (प्रा०) लिमि०, (फैक्ट्री), इंदौर	—	—	1,03,195	1,02,195
36.	श्री आकर्तलाल मिश्रीलाल, मवसौर	—	—	6,56,104	6,56,104

[क्रमांक० सी० ए० 10/74-75/विंग्र०पा]

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, M.P.

Bhopal, the 3rd Sept. 1975

S.O. 4183.—List of defaulters as on 31-3-1975 u/s 287 of the I.T. Act, 1961 (i) is for Part 'A'—Amount in default for periods exceeding nine months but not exceeding one year and three months; (ii) for Part 'B'—Amount in default for periods of one year and three months and above but not exceeding two years and three months; (iii) for Part 'C'—Amount in default of two years and three months and above and (iv)—for Total amount in default.

SCHEDULE

S. No.	Name of the assessee and full address	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	M/s. Ramdung Singh Chauhan & Co. Chudia	1,56,746	..	25,942	182,688
2.	Shri A.A. Patel, Indore	3,429	46,919	..	50,348
3.	Shri N.M. Bhandari, Indore	211	1,684	142,527	144,422
4.	Shri Hukamchand Chimanlal, Indore	121	76	559,944	560,141
5.	Shri Mangalchand Chimanlal, Indore	121	76	554,541	554,738
6.	M/s. Swayamberlal Motor Service (P) Ltd., Indore	1,468	59,560	..	61,028
7.	M/s. Sagarmal Spg. & Wvg. Mills Ltd. Indore	7,310	10,055	102,674	120,039
8.	M/s. Kabir Ahmed Hazi Abdul Karim Bhopal	25,494	5,656	46,567	77,717
9.	Shri Abdul Karim P/O above	8,478	3,000	25,133	36,611
10.	Shri Ahmed Nathu P/O above	8,211	2,832	25,952	36,995
11.	Shri Kabir Ahmed P/O above	7,893	2,772	20,427	31,092
12.	Shri Ronaksing Nanaksingh, Indore	..	60,465	..	60,465
13.	M/s. United Transport Pvt. Ltd., Gwalior	100,465	100,465
14.	M/s. M.P. Automobiles (P) Ltd., Gwalior	74,266	74,266
15.	M/s. Sardarsingh Amarsingh, Timarni	633,810	633,810
16.	Shri Gulabchand Yadav, M.E.S. Contractor, Pachmari, Itarsi	122,414	122,414
17.	Shri Balwant Singh & Sons, Betul	452,594	452,594
18.	Shri Harjendar Singh Kartar Singh, Betul	48,078	48,078
19.	M/s. Jiyalal Shyamal, Betul	..	47,212	99,145	146,357
20.	Sbri Jaswant Singh Mehar Singh, Borkehi, Teh. Multai, Betul	49,526	49,526
21.	M/s. Kishan Sahay Kundanlal, Ghoradongri	68,575	68,575
22.	M/s. Karam Singh Attar Singh Ghoradongri	166,813	166,813
23.	M/s. Kishan Sahay Bhagirath, Ghoradongri	45,012	45,012
24.	M/s. Kanhiyalal Sobaram Mehto, Juwadi P.O. Ghoradongri, Betul	28,689	28,689
25.	Shri Karam Singh Attarsingh, Betul	34,968	34,968
26.	Shri Motilal Mehto, Juwadi, Ghoradongri	55,764	55,764
27.	M/s. Patel Moti LaL Mehto & Co., Juwadi, Ghoradongri	2,02,700	202,700
28.	Shri Ram Singh Keshar Singh, Ghoradongri	30,164	30,164
29.	Shri Jawala Singh Ladha Singh, Sohagpur	49,474	49,484
30.	Shri Chandanmal, Ganj, Betul	37,956	37,956
31.	M/s. Khalsa Juneja Timber Trading Co., Indore Prop. : Darsingh Trilok-singh	28,912	28,912
32.	Shri Badrinarayan Rameshwar, Indore	3,47,532	3,47,532
33.	Shri G. Pushpathinath, Siyaganj, Indore	43,320	43,320
34.	M/s. Mangalchand Hukamchana, Indore	3,74,279	3,74,279
35.	M/s. Mahadeo Hosiery Pvt. Ltd., Indore	1,03,195	1,03,195
36.	Shri Onkerlal Mishrilal, Mandsaur	6,56,104	6,56,104

कांगड़ा ४१८४.—प्रायकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८७ के प्रतीक दिनांक ३१-३-१९७४ तक के अप्तिक्रमी अधिनियमों की सूची, भाग 'ज' के लिये (i)-नी माह से अधिक वी कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि एक वर्ष तीन माह से अधिक न हई हो; भाग 'ब' के लिये (ii)-एक वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम किन्तु ऐसी कालावधि दो वर्ष तीन माह से अधिक न हो; भाग 'स' के लिये (iii)-दो वर्ष तीन माह तथा उससे अधिक की कालावधि में भुगतान न की गई रकम (iv) और भुगतान न की गई कुल रकम के लिये है।

भनुसूची

क्रमांक	निधारितियों के नाम और पूरा पता	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	मे० स्वयम्भरलाल मोटर सर्विस प्राय० लि०, इंदौर	59,560	--	--	59,560
2.	,, सगरमल सिप०एच वीवि० मिल्स लि०, इंदौर	10,055	1,02,674	1,12,729	
3.	श्री रोनकसिंह नारायणसिंह, इंदौर	60,465	--	--	60,465
4.	,, ए०ए० पटेल, इंदौर	81,208	--	--	81,208
5.	,, एन० एम० भडारी, इंदौर	1,684	1,42,527	1,44,211	
6.	मे० जियालाल स्वाम लाल, बैतूल	47,212	2,08,466	2,55,678	
7.	,, एस०क० शेष रसूल मोटर ट्रांसपोर्ट क० प्रा० लि०, जबलपुर	68,498	73,960	2,62,949	3,05,407
8.	,, हीराजी कल्याणजी आसानी, राजनाविगाव	27,640	--	73,643	1,01,283
9.	मवनलाल शंकरलाल, बारासिवामी	600	27,443	51,289	79,332
10.	प्रभुदयाल पतिराम, रायपुर	58,680	--	3,62,166	4,20,846
11.	पीलालाल बैनराम, दुर्ग	6,907	86,565	707	94,197
12.	,, पालुराम धनानिया, रायगढ़	86,975	--	4,19,297	536,272
13.	" रामचंद्र भुरा, सिवनी	1,587	17,014	--	18,601
14.	सुदर्शन द्वासपोर्ट प्राय० लि०, बिलासपुर	58,680	--	1,51,469	2,10,149
15.	श्री हुकमीचर्च चिमनलाल, इंदौर	--	2,742	5,57,202	5,59,944
16.	मे० ग्रमरसिंह सतकुमार, जबलपुर	--	40,434	--	40,434
17.	हरखस्सिंह मानिक, जबलपुर	--	90,520	--	90,520
18.	स्थानानारायण दिवेशी, जबलपुर	--	60,259	--	60,259
19.	एस० बहादुरसिंह, मोटर स्टेन्ड, जबलपुर	--	1,56,748	47,598	2,04,346
20.	मे० पुरुषोलमदास मोदा, रायगढ़	--	32,585	2,466,691	24,99,276
21.	,, सोहनलाल सुरेशचन्द, भानुपारा	--	4,680	1,21,791	1,26,471
22.	श्री बद्रीनारायण रामेश्वर, इंदौर	--	--	3,47,532	3,47,532
23.	,, मंगलचर्च चिमनलाल, इंदौर	--	--	3,94,055	3,94,055
24.	मे० महावेव होजरी क०, इंदौर	--	--	1,05,606	1,05,606
25.	,, मंगलचर्च हुकमीचर्च, इंदौर	--	--	3,60,759	3,60,759
26.	श्री पाण्डुलिनाथ, इंदौर	--	--	43,320	43,320
27.	,, ग्रोकारलाल मिश्रीलाल, मदसौर	--	--	8,56,104	6,56,104
28.	मे० गूनाइडेण द्वासपोर्ट, ग्वालियर	--	--	1,00,465	1,00,465
29.	,, एम० पी० प्राटोमोबाइल (प्रा०) लि०, ग्वालियर	--	--	49,162	49,162
30.	श्री भजूर दुर्सेन, प्रो० साधर्मा देवेश, घोपाल	--	--	4,01,872	4,01,872
31.	मे० न्यू घोपाल टेक्सटाइल्स लि०, घोपाल	--	--	12,55,653	12,55,653
32.	,, घोपाल टेक्सटाइल्स लि०, घोपाल	--	--	2,78,022	2,78,022
33.	मे० सरवारसिंह ग्रमरसिंह, दिमरनी	--	--	6,33,810	6,33,810
34.	श्री गुलाबचन्द यादव, पंचमढी	--	--	1,39,640	1,39,640
35.	मे० ज्वालासिंह लधामिह, युहापुर	--	--	56,348	56,348
36.	,, बलबन्तसिंह एवं संस, बैतूल	--	--	3,22,644	3,22,644
37.	श्री चांदमल, बैतूल	--	--	37,956	37,956
38.	घनीरसिंह किशनलाल, कारेस्ट कार्गेक्टर, घोड़ाडोगरी	--	--	96,107	96,107
39.	मे० जियालाल स्वाम लाल, बैतूल	--	--	2,08,466	2,08,466
40.	श्री जसबन्तसिंह मेहरसिंह, वरदेही, लै० मूलमाई जिला बैतूल	--	--	49,526	49,526
41.	मे० किशन सहाय किशनलाल, घोड़ाडोगरी	--	--	68,575	68,575
42.	करमसिंह ग्रमरसिंह, घोड़ाडोगरी	--	--	1,66,813	1,66,813
43.	केणब सहाय भागीरथ, घोड़ाडोगरी	--	--	45,022	45,022

44. श्री कन्देयालाल शोभाराम मेहतो जूबाजी, घोड़ाडोगरी	—	—	28,689	28,689
45. „ करतारसिंह भरतरसिंह, बैतूल	—	—	34,968	34,968
46. „ मोतीलाल मेहतो, एंड क० बैतूल	—	—	55,764	55,764
47. म० पटेल मोतीलाल मेहतो, एंड क०, बैतूल	—	—	2,02,700	2,02,700
48. श्री रामसिंह केशरसिंह, घोड़ाडोगरी	—	—	55,164	55,164
49. म० रामपूरसिंह जगद्देवी, एंड क० गुरिया, पो० आ० लिंगोली, बैतूल	—	—	25,942	25,942
50. „ खाससा जुनेजा, टिम्बर ट्रेलिंग, क०, गु०ना०टिंमा० हंशीर, प्र० वरसिंह त्रिलोकसिंह	—	—	—	—
51. नव भारत कन्सट्रक्शन क०, जबलपुर	—	—	28,912	28,912
52. जगदीश कुमार चर्ट्समूजाई	—	—	41,858	41,858
53. श्री मोतीलाल चावला द्वारा ए० आ० चावला जबलपुर	—	—	32,520	32,520
54. अन्नलकरीम अब्दुलशाकूर, जबलपुर	—	—	35,863	35,863
55. म० मेहताब सिंह, एंड संस, जबलपुर	—	—	1,17,938	1,17,938
56. श्री धरमदास अय्यवाल, प्र० रामराम नायूलाल (हि०स०प०) कटनी	—	—	52,173	52,173
57. „ अमृतलाल अनन्द, रायपुर	—	—	2,56,926	2,56,926
58. „ बी०ए० गुरुता, दुर्ग	—	—	1,02,948	1,02,948
59. म० गुरुता, कन्सट्रक्शन क०, दुर्ग	—	—	69,779	69,779
60. „ केमरीलाल एंड ब०, रायपुर	—	—	58,838	58,838
61. „ पिंडियारायण प्रभुदयाल, सिवनी	—	—	27,875	27,875
62. „ एयाम सिंह एंड संस, राजनांदगांव	—	—	6,32,381	6,32,381
63. श्री शिवभाई, द्वारा म० राजेन्द्र टिम्बर, क०, रायपुर	—	—	85,325	85,325
64. „ उष्मीराम रामस्वरूप, रायगढ़	—	—	37,238	37,238
65. „ हरजेन्द्रसिंह करतारसिंह, बैतूल	—	—	2,07,124	2,07,124
	—	—	48,078	58,078

[क्रमांक सी० एम० 10/74/75 दि० मा०सा०]
के० जगद्देवी, आयुक्त

S.O. 4184.—List of defaulters as on 31-3-1975 u/s. 287 of the I. T. Act, 1961 (i) is for Part 'A'—Amount in default for periods exceeding nine months but not exceeding one year & three months (ii) for Part 'B'—Amount in default for periods of one year and three months & above but not exceeding two years and three months; (iii) for Part 'C'—Amount in default of two years and three months & above and (iv) for Total amount in default.

SCHEDULE

S. No.	Name of assessee and full address	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
		3	4	5	6
1	2				
1. M/s. Swyamberlal Motor Service Pvt. Ltd. Indore		59,560	59,560
2. M/s. Sagarmal Spg. & Wvg. Mills, Indore		10,055	..	1,02,674	1,12,729
3. Shri Ronak Singh Narainsingh, Indore		60,465	60,465
4. Shri A.A. Patel, Indore		81,208	81,208
5. Shri N.M. Bhandari, Indore		1,684	..	1,42,527	144,211
6. M/s. Jiyalal Shyamal, Betul		47,221	..	2,08,466	255,678
7. M/s. S.K. Sheikh Rasool Motor Transport Co. Pvt. Ltd., Jabalpur		68,498	73,960	2,62,949	305,407
8. M/s. Hirji Kalyanji Jassani, Rajnandgaon		27,640	..	73,643	101,283
9. M/s. Madanlal Shankarlal, Warasconi		600	27,443	51,289	79,332
10. M/s. Prabhudayal Patiram, Raipur		58,680	..	3,62,166	420,846
11. M/s. Pilalal Chaitram, Durg		6,907	86,565	707	94,197
12. M/s. Paluram Dhananra, Raigarh		86,975	..	4,49,297	536,272
13. M/s. Ramchand Bhura, Seoni		1,587	17,014	..	18,601
14. M/s. Sudarshan Transport Pvt. Ltd. Bilaspur		58,680	..	1,51,469	210,149
15. Shri Hukmichand Chimantai, Indore		..	2,742	5,57,202	559,944
16. M/s. Amarsingh Sant Kumar, Jabalpur		..	40,434	..	40,434
17. M/s. Harbanssingh Manik, Jabalpur		..	90,520	..	90,520
18. M/s. Shyam Narayan Trivedi, Jabalpur		..	60,259	..	60,259
19. S. Bahadur Singh, Motor Stand, Jabalpur		..	1,56,748	47,598	204,346

1	2	3	4	5	6
20.	M/s. Purshotamdas Moda, Raigarh	32,585	24,66,691	24,99,276	
21.	M/s. Sohanlal Sureshchand, Bhatapara	4,680	1,21,791	1,26,471	
22.	Shri Badrinarayan Rameshwar, Indore	..	3,47,532	3,47,532	
23.	Shri Mangalchand Chimanlal, Indore	..	3,94,055	3,94,055	
24.	M/s. Mahadeo Hosiery Factory, Indore	..	1,05,606	1,05,606	
25.	M/s. Mangalchand Hukmichand Indore	..	3,60,759	3,60,759	
26.	Shri G. Pashupatinath, Indore	..	43,320	43,320	
27.	Shri Onkarlal Mishrilal, Mandsaur	..	6,56,104	6,56,104	
28.	M/s. United Transport Gwalior (P) Ltd., Gwalior	..	1,00,465	1,00,465	
29.	M/s. M.P. Automobiles (P) Ltd., Gwalior	..	49,162	49,162	
30.	Sri Manzoor Hussain Prop : Sadhna Traders, Bhopal	..	4,01,872	4,01,872	
31.	M/s. New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal	..	12,55,653	12,55,653	
32.	M/s. Bhopal Textiles Ltd., Bhopal	..	2,78,022	2,78,022	
33.	M/s. Sardarsingh Amarsingh, Timarni	..	6,33,810	6,33,810	
34.	Shri Gulabchand Yadav, Pachmarhi	..	1,39,640	1,39,640	
35.	M/s. Jawalal Singh Ladha Singh, Sohagpur	..	56,348	56,348	
36.	M/s. Balwant Singh & Sons, Betul	..	3,22,644	3,22,644	
37.	Shri Chandmal, Betul	..	37,956	37,956	
38.	Shri Dhanyvirsingh Kishanlal, Forest Contractor, Ghoradongri	..	96,107	96,107	
39.	M/s. Jiyalal Shyamalal, Betul	..	2,08,466	2,08,466	
40.	Shri Jaswant Singh Mehar Singh, Bardchi, Tch. Multani, Betul	..	49,526	49,526	
41.	M/s. Kishan Sahaya Kishanlal, Ghoradongri	..	68,575	68,575	
42.	M/s. Karam Singh Attarsingh, Ghoradongri	..	1,66,813	1,66,813	
43.	M/s. Keshav Sahaya Bhagirath, Ghoradongri	..	45,022	45,022	
44.	Shri Kanhiyalal Shobharam Mehto, Juwadi, Ghoradongri	..	28,689	28,689	
45.	Shri Kartarsingh Attarsingh, Betul	..	34,968	34,968	
46.	Shri Motilal Mehto & Co., Betul	..	55,764	55,764	
47.	M/s. Patel Motilal Mehto & Co., Betul	..	2,02,700	2,02,700	
48.	Shri Ramsingh Kesharsingh, Ghoradongri	..	55,164	55,164	
49.	M/s. Ramdhusingh Jagannath Singh & Co., Gudia, P.O. Chicholi, Betul	..	25,942	25,942	
50.	M/s. Khalsa Juncja Timber Trading Co., GNTM, Indore Prop : Darsingh Trilok-singh	..	28,912	28,912	
51.	Nav Bharat Const. Co., Jabalpur	..	41,858	41,858	
52.	Jagdish Kumar Chaturbhujbhai, Jabalpur	..	32,520	32,520	
53.	Shri Motilal Chawla C/o M.R. Chawla, Jabalpur	..	35,863	35,863	
54.	Shri Abdul Karim Abdul Shakoor, Jabalpur	..	1,17,938	1,17,938	
55.	M/s. Mehtab Singh & Sons, Jabalpur	..	52,173	52,173	
56.	Shri Dharamdas Agarwal Prop : Ramsaran Nathulal (HUF) , Katni	..	2,56,926	2,56,926	
57.	Shri Amritlal Anand, Raipur	..	1,02,948	1,02,948	
58.	Shri B.L. Gupta, Durg	..	69,779	69,779	
59.	M/s. Gupta Construction Co., Durg	..	58,838	58,839	
60.	M/s. Koniwal & Bros, Raipur	..	27,875	27,875	
61.	M/s. Shivnarain Prabhudayal, Sconi	..	6,32,381	6,32,381	
62.	M/s. Shyamsingh & Sons, Rajnandgaon	..	85,325	85,325	
63.	Shri Shivbhai C/o M/s. Rajendra Timber Co., Raipur	..	37,238	37,238	
64.	Shri Udmiram Ramswaroop, Raigarh	..	2,07,124	2,07,124	
65.	Shri Harjinder Singh Kartar Singh, Betul	..	48,078	48,078	

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित का कार्यालय)

आवेदन

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

कांग्रेस 4183.—सर्वश्री इन्चेक टायर्स लिं. कलकत्ता के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को 12,00,000 रुपये (बारह लाख रुपये मात्र) गूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी०/धी०/1401467 विनाक 27-7-1974 इससे संलग्न सूची के अनुसार कच्ची सामग्री/संघटकों के आयात के लिए प्रवान किया गया था।

2. उन्होंने (सर्वश्री इन्चेक टायर्स लिं. कलकत्ता) उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई है या प्रस्तावनस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी हारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस पर 9,45,883 रुपये (नौ लाख पैंतालिस हजार प्राठ सौ तिरासी रुपये मात्र) का उपयोग करना आवश्यक था। लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत कराया गया था।

3. प्रपत्रे तक के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताशारी संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं. पी०/धी०/1401467 विनाक 27-7-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है या प्रस्तावनस्थ हो गई है और निवेश देता है कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रही जाती है।

4. लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या रबड़ 22/4/73-74/आर०एम-2]
प्राइ०वी० कुनकत, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 11th September, 1975

S.O. 4185.—M/s. State Trading Corporation of India Ltd, New Delhi, were granted Import Licence No. P/D/1401467 dated 27-7-1974, with Letter of Authority in favour of M/s. Incheck Tyres Ltd., Calcutta, for import of Raw Materials/Components as per list attached to it valued at Rs. 12,00,000 (Rs. Twelve Lakhs only).

2. They (M/S. Incheck Tyres Ltd., Calcutta) have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an un-utilized balance of Rs. 9,45,883/- (Rs. Nine lakhs forty-five thousand eight hundred and eighty only). The licence was registered with Customs House, Bombay.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs purposes Copy of Import Licence No. P/D/1401467 dt. 27-7-1974 has been lost or misplaced and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Rubber/22/4/73-74/RM II]
I. V. CUNKATH, Dy. Chief Controller

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित का कार्यालय)

प्रतेरण

ग्राहमबाबाद, 11 सितम्बर, 1974

कांग्रेस 4186.—सर्वश्री कैमो क्राफ्ट, पठालाली गोलबाड़, बिल्लीमोरा को इथिल आमोडायजो डेंजीन ब्लोरोमिनेट आदि के आयात के लिए लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253, विनाक 16-9-74 मूल्य 26037 रु (छम्बीस हजार सेतीम रुपये मात्र), पी०/एस०/1403254, विनाक 16-9-74 मूल्य 13018 रुपये (तेरह हजार अट्ठारह रुपये मात्र) एवं पी०/एस०/1403255, विनाक 16-9-74 मूल्य 13018 रुपये (तेरह हजार अट्ठारह रुपये मात्र) स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253, विनाक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति), पी०/एस०/1403254, विनाक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां) एवं पी०/एस०/1403255, विनाक 16-9-74 की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंसों की मूल प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई हैं।

प्रपत्रे दाखिल के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253 एवं पी०/एस०/1403255 वोनों का दिनाक 16-9-74 है की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एवं लास सेंस संख्या : पी०/एस०/1403254, दिनाक 16-9-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क प्रतियां खो गई हैं और निवेश देता हूँ कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस संख्या : पी०/एस०/1403253 एवं पी०/एस०/1403255 वोनों का दिनाक 16-9-74 है, की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एवं लास सेंस संख्या : पी०/एस०/1403254, दिनाक 16-9-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां रह की जाती है।

[सं. 1653/एन शू/4338/पी 33/ए एम-74/एस एस आई]

धी० डिसूजा, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy-Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER
Ahmedabad, the 11th September, 1974

S.O. 4186.—M/s. Kemo Kraft, Pachhali Golwad, Billimora has been granted Import licence No. P/S/1403253 dated 16-9-74 for Rs. 26037/- (Rs. Twenty Six thousand and thirty seven only), P/S/1403254 dated 16-9-74 for Rs. 13018/- (Rs. Thirteen thousand and eighteen only) and P/S/1403255 dated 16-9-74 for Rs. 13018/- (Rs. Thirteen thousand and eighteen only) for item Ethyl Oxyethyl Aminodiazole benzene Chlorozincate etc.

They have applied for duplicate copies of license No. P/S/1403253 dt. 16-9-74 (Custom purpose copy), P/S/1403254 dt. 16-9-74 (Custom and Exchange purpose copies) and P/S/1403255 dt. 16-9-74 (Custom purpose copy) on the ground that the original above copies have been lost without having been registered with any Custom authority.

In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the Custom purpose copies of licence Nos. P/S/1403253 and P/S/1403255 dt. 16-9-74 and Exchange and Custom purpose copies of licence No. P/S/1403254 dt. 16-9-74 have been lost and direct that the duplicate of the said copies of the licences should be issued the applicant firm.

The original custom purpose copies of licence Nos. P/S/1403253 and P/S/1403255 dt. 16-9-74 and exchange and customs purpose copies of licence No. P/S/1403254 dated 16-9-74 are cancelled.

[No. 1653/NU/4338/P. 33/AM-74/SSI]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)
बृहिं-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1975

का०प्रा० 4187.—पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के प्रधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला ग्रहमदाबाद तालुका विरमगाम के लिये भारत के राजपत्र के पाग-11, अंड 3 (ii) के पुण्ड संख्या 1288 से 1292 तक विनाक 29-3-75 को प्रकाशित का०प्रा० संख्या 959 के द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की प्रधिकृति संख्या 12017/1/75 एल०एल० एल० विनाक 12-3-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़।

अनुसूची

गांव हंसलपुर सुरेश्वर तालुका विरमगाम जिला ग्रहमदाबाद
गुजरात राज्य
के स्थान पर पड़े

क्रमांक	तक			तमांक			तक		
	एच	ए	चौमीस	एच	ए	चौमीस	एच	ए	चौमीस
796	0	35	15	796	0	25	15		
936	0	23	95	936	0	23	92		

[सं० 12017/1/75 एल०एल० एल०]
टी०पी० सुब्रह्मण्यम्, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 13th September, 1975

S. O. 4187.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/1/75-L&L Dt. 12-3-75 published vide S.O. No. 959 dated 29-3-75 from page No. 1288 to 1292 of the Gazette of India Part II Section 3(i) for Taluka Viramgam Distt. Ahmedabad Gujarat State, under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Village : Hansalpur-Sureshver Tal : Viramgam
Distt. : Ahmedabad.
Gujarat State.

For Read

S. No.	Extent	S. No.	Extent	H.A.Sq. M.	H.A.Sq. M.
				0-35-15	0-25-15
796		796			
936	0-23-95	936	0-23-92		

[No. 12017/1/75-L&L].

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

अर्जी मंत्रालय
(कोयला विभाग)
नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1975

का०प्रा० 4188.—कोयला वाले क्षेत्र (भ्रजन और विकास) प्रधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 को उपधारा (1) के प्रश्नीन, भारत सरकार के इस्तात और बाल मंत्रालय (कोयला विभाग) की प्रधिकृति सं० का० प्रा० 2245, तारीख 20 अगस्त, 1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उस प्रधिकृति से उपायद अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान में की भूमियों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और उक्त प्रधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को प्रपती रिपोर्ट दे दी है;

अब केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और विहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपायद अनुसूची में वर्णित 599.52 एकड़ (लगभग) या 242.61 हैक्टेयर (लगभग) भूमियां अर्जित की जानी चाहियें;

अतः, अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 599.52 एकड़ (लगभग) या 242.61 हैक्टेयर (लगभग) भूमियां अर्जित की जाती हैं।

2. इस प्रधिकृति के अन्तर्गत आने वाले रेखांकों का निरीक्षण उपायकृत, हजारी बाग के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, कौसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, (बिहार) में किया जा सकता है।

अनुसूची
दामोदर नदी तल
वक्षिण कररापुरा कोयला क्षेत्र^{प्रभाग}
का० सं० राजस्व 48/74
तारीख 19-11-74 (गोट सं० 1)
जिसमें प्रजित भूमियां दर्शित हैं
“(अंड 'क')”

सभी प्रधिकार

क्रम	ग्राम	धारा	पाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणीया
	संख्या		संख्या			
1.	संगो		कर्णांग	97	हजारी- बाग	
2.	उरीमारी		”	155	”	
3.	तोकीसूद		रामगढ़	1	”	
4.	कोरीगारा		”	2	”	
5.	सांकुल		”	21	”	

कुल क्षेत्र:— 199.50 एकड़ (लगभग)
या:— 80.73 हैक्टेयर (लगभग)

अंगों ग्राम में अर्जित प्लाट सं०:— 1670 (भाग)
उरीमारी ग्राम में अर्जित प्लाट सं०:— 757 (भाग)
तोकीसूद ग्राम में अर्जित प्लाट सं०:— 1,485 और 137 (भाग)
कोरीगारा ग्राम में अर्जित प्लाट सं०:— 1 और 2003

सीमा-वर्णन

ए-जी—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् ग्रामों और देवगढ़ ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है, तत्पश्चात् तोकीसूद ग्राम में प्लाट सं० 137 (दामोदर नदी) से होकर दामोदर नदी के दक्षिण तट तक जाती है।

बी-सी—लाइन तोकीसूद, कीरीगारा और सांकुल ग्रामों में दामोदर नदी के आंशिक दक्षिण तट के साथ-साथ जाती है।

सी-डी—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् मांकुल ग्राम के प्लाट सं० 2003 और सिंचाल ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ और उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 757 और 752 की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

डी-ई—लाइन उरीमारी ग्राम में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है।

ई-एफ—लाइन उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 757 से होकर (जो उरीमारी बंड (बलरामपुर परियोजना) के लिए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन प्रजित क्षेत्र की आंशिक सामान्य सीमा का भाग है) जाती है।

एक-जी—लाइन दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो ग्राम उरीमारी के प्लाट सं० 757 और ग्राम सांकुल के प्लाट सं० 2003 की आंशिक सामान्य सीमा है), पोंतंगा ग्राम के प्लाट सं० 1974 और सांकुल ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, पोंतंगा ग्राम के प्लाट सं० 1876 और कीरीगारा के ग्राम प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, ग्रस्वा ग्राम के प्लाट सं० 374 और तोकीसूद ग्राम के प्लाट सं० 485, ग्रस्वा ग्राम के प्लाट सं० 374 और तोकीसूद ग्राम के प्लाट सं० 1 की सामान्य सीमा के साथ-साथ, ग्रामों ग्राम के प्लाट सं० 1670 और तोकीसूद ग्राम के प्लाट सं० 1 (जो उरीमारी बंड (बलरामपुर परियोजना) के लिए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन प्रजित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है) की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

जी-एच—लाइन ग्रंगो ग्राम के प्लाट सं० 1670 (दामोदर नदी) से होकर जाती है।

एक-ए—लाइन ग्रंगो ग्राम में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है और आरम्भ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

बंड 'ए'

इति० सं० राजस्व/48/74-

तारीख 19-11-74

(शीट सं०--II)

(जिसमें प्रजित भूमियां दर्शित हैं)।

सभी अधिकार

क्रम	ग्राम	बाना	धाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
संख्या				संख्या		
1.	बसरिया	माण्डू	38	हजारीबाग		भाग
2.	मुन्हू	माण्डू	39	हजारीबाग		भाग

कुल क्षेत्र :— 95.13 एकड़ (लगभग)
या 38.50 हेक्टेयर (लगभग)

बसरिया ग्राम में प्रजित प्लाट सं०-231, 433 और 434
मुन्हू ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—561 (भाग)

सीमा वर्णन

प्राई-जे—लाइन दामोदर नदी से होकर (अर्थात् ग्राम के प्लाट सं० 514 और बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 434 की सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

जे-के—लाइन दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 434 और इंदुमा ग्राम के प्लाट सं० 66, बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 231 और इंदुमा ग्राम के प्लाट सं० 197, बसरिया ग्राम के प्लाट सं० 433 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 1, बुन्हू ग्राम के प्लाट सं० 561 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 20 की सामान्य सीमा है) बुन्हू ग्राम के प्लाट सं० 561 और चोरधारा ग्राम के प्लाट सं० 25 की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ (जो दामोदर नदी तल में, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) प्रधिनियम की 1957 धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित बंड-II की आंशिक सामान्य सीमा है) जाती है।

के-एस—लाइन बुन्हू ग्राम के प्लाट सं० 561 से होकर (जो दामोदर नदी तल में, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) प्रधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित बंड-II की आंशिक सामान्य सीमा का भाग है) जाती है।

एस-प्राई—लाइन बुन्हू और बसरिया ग्रामों में दामोदर नदी के आंशिक बाएं तट के साथ-साथ जाती है और प्रारंभ बिन्दु 'प्राई' पर मिलती है।

बंड-ग

इति० सं० राजस्व/48/74

तारीख 19-11-74

(शीट सं० 3)

(जिसमें प्रजित भूमियां दर्शित हैं)

सभी अधिकार

क्रम	ग्राम	धाना	धाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
संख्या				संख्या		
1.	सिर्का	माण्डू	136	हजारीबाग		भाग
2.	बरिगाडा	"	137	"		"
3.	हेसला	"	138	"		"
4.	चैनगारा	रामगढ़	57	"		"
5.	हेहल	"	58	"		"
6.	चुन्हू	"	59	"		"
7.	उलौग	"	78	"		"
8.	चोटकना	"	79	"		"

कुल क्षेत्र : 304.89 एकड़ (लगभग)
या 123.38 हेक्टेयर (लगभग)

सिर्का ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—243, 429, 516 और 1010।

बरिगाडा ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—138

हेसला ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—122 और 123।

चैनगारा ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—1220 और 1221।

हेहल ग्राम प्रजित प्लाट संख्या :—1

चुन्हू ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—1।

उलौग ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—1, 112, 418, 419 और 578

चोटकना ग्राम में प्रजित प्लाट सं०—1।

सीमा-वर्णन

एम-एन—लाइन बामोदर नदी से होकर पर्यात् सिर्का ग्राम के प्लाट सं० १ और 243 की सामान्य सीमा, चौरक्षारा ग्राम के प्लाट सं० 304 और बैनगारा ग्राम के प्लाट सं० 1220 की सामान्य सीमा (जो तल खण्ड-II में कोयला बाले क्षेत्र (प्रज्ञन धीर विकास) भवित्विम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन प्रधिसूचित क्षेत्र की भागिक सामान्य सीमा) के साथ-साथ जाती है।

एन-ओ—लाइन बैनगारा, हेतुल, घटुआ, उलौग, छोटकना ग्रामों में बामोदर नदी के विशिष्ट तट के साथ-साथ जाती है।

ओ-पी—लाइन दामोदर नदी से होकर (पर्यात् छोटकना ग्राम के प्लाट सं० 1 की पूर्वी सीमा और हेतुला ग्राम के प्लाट सं० 123 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ) जाती है।

पी-एम—लाइन हेसला, अरिगाड़ा, सिर्का ग्रामों में बामोदर नदी के पाएं तट के साथ-साथ जाती है प्रोटोर पारंभ-विन्दु 'एम' पर मिलती है।

[सं० का० 25/14/73-सी 5/सील]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4188.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 2245 dated the 20th August, 1974, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 599.52 acres (approximately) or 242.61 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 599.52 acres (approximately) or 242.61 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the office of National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Damodar River Bed
South Karanpura Coalfield

DRG No. Rev. /48/74
Dated 19-11-74

(Sheet No. 1)

(Showing lands acquired)

All Rights

"(Block—'A')

S. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area Remarks
1.	Ango	Barkagaon	97	Hazaribagh	Part
2.	Urimari	"	155	"	"
3.	Tokisud	Ramgarh	1	"	"
4.	Kirigara	"	2	"	"
5.	Sankul	"	21	"	"

Total area :—199.50 acres (approximately)
or :—80.73 hectares (approximately)

Plot number acquired in village Ango :—1670 (part).

Plot number acquired in village Urimari :—757 (part).

Plot numbers acquired in village Tokisud :—1, 485 & 137 (part).

Plot number acquired in village Kirigara :—1.

Plot numbers acquired in village Sankul :—1 & 2003.

BOUNDARY DESCRIPTION

A—B Line passes through Damodar River (i.e. along the part common boundary of villages Ango and Deogarh) then passes through plot number 137 (River Damodar) in village Tokisud upto Right Bank of Damodar River.

B—C Line passes along the part Right Bank of Damodar River in villages Tokisud, Kirigara and Sankul.

C—D Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot number 2003 of village Sankul and plot number 1 of village Seal, and also along the common boundary of plot numbers 757 and 752 of village Urimari).

D—E Line passes along the part left Bank of River Damodar in village Urimari.

E—F Line passes through plot number 757 of village Urimari (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, for Urimari Block (Balrampur Project).

F—G Line passes along the part Central line of River Damodar (which is the part common boundary of plot number 757 of village Urimari and 2003 of village Sankul along common boundary) of plot number 1864 of village Potonga and plot number 1 of village Sankul, along common boundary of plot number 1876 of village Potonga and plot number 1 of Village Kirigara, along common boundary of plot number 374 of village Aswa and 485 of village Tokisud, along part common boundary of plot number 1670 of village Ango and 1 of village Tokisud (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 for Urimari Block (Balrampur Project).

G—H Line passes through plot number 1670 (River Damodar) of village Ango.

H—A Line passes along the part left Bank of River Damodar in village Ango and meets at starting point 'A'.

BLOCK 'B'
DRG No. Rev/48/74
Dated 19-11-74
(Sheet No. II)
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl.	Village No.	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Basaria	Mandu	38	Hazaribagh		Part
2.	Bundu	"	39	"		"
Total area : 95.13 acres (approximately) or 38.50 hectares (approximately)						

Plot numbers acquired in village Basaria :
Plot number acquired in village Bundu

BOUNDARY DESCRIPTION

I-J—Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot number 514 of village Gidi and plot number 434 of village Basaria).

J-K—Line passes along the part Central line of River Damodar (which is the common boundary of plot number 434 of village Basaria and 66 of village Dundua, plot number 231 of village Basaria and 66 of village Dundua, plot number 231 of village Basaria & 197 of village Dundua, plot No. 433 of village Basaria and 1 of village Chordhara, plot number 561 of village Bundu and 20 of village Cherdhara, part common

231, 433 & 434
561 (part.)

boundary of plot number 561 of village Bundu and 25 of village Chordhara (which forms part common boundary of Block II notified under section 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Damodar River Bed).

K-L—Line passes through plot number 561 of village Bundu (which forms part common boundary of Block-II notified under section 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Damodar River Bed).

L-I—Line passes along the part left Bank of River Damodar in villages Bundu and Basaria and meets at starting point 'I'.

BLOCK 'C'
DRG No. Rev/48/74
Dated 19-11-74
(Sheet No. III)
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl.	Village No.	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sirkha	Mandu	136	Hazaribagh		Part
2.	Arigada	"	137	"		"
3.	Hesla	"	138	"		"
4.	Chainingara	Ramgarh	57	"		"
5.	Hehal	"	58	"		"
6.	Ghutua	"	59	"		"
7.	Urlang	"	78	"		"
8.	Ghotakana	"	79	"		"

Total area : 304.89 acres (approximately)
or 123.38 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Sirkha : 243, 429, 516 & 1010.
Plot number acquired in village Arigada : 138.
Plot numbers acquired in village Hesla : 122 & 123.
Plot numbers acquired in village Chainingara : 1220 & 1221.

Plot number acquired in village Hehal : 1.
Plot number acquired in village Ghutua : 1.
Plot numbers acquired in village Urlang : 1, 112, 418, 419 & 576.

Plot number acquired in village Chhotakana : 1.

BOUNDARY DESCRIPTION

M-N—Line passes through Damodar River (i.e. along the common boundary of plot numbers 1, & 243 of village Sirkha and common boundary of plot number 304 of village Chordhara

and 1220 of Village Chalngara (which forms part common boundary of the area notification U/s 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 in River Bed Block-II).

N-O—Line passes along the Right Bank of River Damada in villages Chringara, Hehal, Ghutua, Urlang, Chhotakana,

O-P—Line passes through Damodar River (i.e. along the eastern boundary of plot number 1 of village Chootakana, and eastern boundary of plot number 123 of village Hesla).

P-M—Line passes along the left Bank if River Damodar in villages Hesla, Arigada, Sirkha and meets at starting point 'M'.

मई विल्सी, 5 सितम्बर, 1975

का० आ० ४१८९.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वापे क्षेत्र (भ्रजन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उधारा (1) के अधीन भारत सरकार के इसपात्र 'और' खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० ६९०(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1973 की अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूचियों में विनियिष्ट भूमियों और अधिकारों को अंजित करने के प्रपत्रे आशय की सूचना दी थी ।

और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सभी प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी है ।

और केन्द्रीय सरकार का, सभी प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने तथा विहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि:

(क) इस से उपाबद्ध अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हैक्टेयर (लगभग) परिमाप की भूमि; और

(ख) इस से उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हैक्टेयर (लगभग) परिमाप की भूमियों में अनियों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें से जाने के अधिकारों ।

का अंजित किया जाना चाहिए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्योपित करती है कि उक्त अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हैक्टेयर (लगभग) परिमाप की भूमि की तथा उक्त अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हैक्टेयर (लगभग) परिमाप की भूमियों में अनियों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन पर कार्य करने उन्हें प्राप्त करने और उन्हें से जाने के अधिकारों को अंजित किया जाता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आपे क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त गिरिहोह (विहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राज्यीय कोयला विकास निगम सिमिटेज (राज्यव अनुभाग), कार्यालय "इरभगा हाउस", राज्यी में किया जा सकता है ।

अनुसूची—'क'
बोकारो खान्ड—1 (सवांग विस्तारण)
पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र¹
उपखण्ड—'क'

जी० आर० जी० स० राजस्व/25/74

तारीख 2-7-74

(अंजित की गई भूमियों को इंशित करने क्षेत्र)

सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	वाना	वाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-णिया
1	सवांग	गुमिया	107	गिरिहोह		भाग
2.	प्ररमो	नवडोह	11	गिरिहोह		भाग
3.	गोविन्दपुर	(पेसी)	15

कुल क्षेत्र: 60.75 एकड़ (लगभग)

या 24.58 हैक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अंजित प्लाट सं० 1282 (भाग) ।

ग्राम प्ररमो में अंजित प्लाट सं० 444 और 776 ।

ग्राम गोविन्दपुर में अंजित प्लाट सं० 2272 (भाग)

सीमा वर्णन

क—क—रेखा कुनार नदी (ग्राम प्ररमो में प्लाट सं० 774 की परिचयी सीमा के साथ-साथ तथा सवांग और सर्वेरा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ से होकर जाती है ।

क—ग—घ—रेखा ग्राम सवांग में कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है ।

घ—इ—रेखा ग्राम सवांग में प्लाट सं० 1282 (कुनार नदी) से हो कर जाती है (सवांग गोलियरी के खालू धृति धरातल के क्षेत्र के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा ही है) ।

इ—च—रेखा कुनार नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (पर्याप्त सवांग और ग्रामों ग्रामों, सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के माध्य-माध्य) जाती है (सवांग रेखांक, खालू धृति धरातल के क्षेत्र के साथ जिसकी सामान्य सीमा भी है) ।

च—छ—रेखा गोविन्दपुर परसो ग्रामों में कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और आसम्भ बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

उप-खण्ड—'ख'

सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	वाना	वाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-णिया
1	सवांग	गुमिया	107	गिरिहोह		भाग

कुल क्षेत्र: 82.00 एकड़ (लगभग)

या 33.18 हैक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अंजित प्लाट सं०:—44 (भाग), 808 (भाग), 809 (भाग), 810 (भाग), 818 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग), 1281 (भाग) और 1295 (भाग) ।

त्रिमा वर्षां

ज-ग—रेखा ग्राम सवांग के प्लाट सं० 44, 809, 808, 810 और 818 से हो कर जाती है।

ज-ग-ट—रेखाएं ग्राम सवांग में प्लाट सं० 818, 1281, 818, 832 और 831 से हो कर जाती हैं (अनन्त प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ब' के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा है)।

ट-ठ—रेखा ग्राम सवांग प्लाट सं० 831, 832, 1281, 1895 और 1281 से हो कर जाती है। (सवांग कोलियरी के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है)।

ठ-ड—रेखा गोविन्दपुर और सवांग ग्रामों में कुनार नदी के प्रांशिक द्वाएं किनारे के साथ-साथ जाती है (अनन्त प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी प्रांशिक समान्य सीमा है)।

इ-ठ-ग-त-थ-द-धन्न-प-फ—रेखाएं ग्राम सवांग में प्लाट सं० 1281 और 818 से होकर जाती हैं अनन्त प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है।

फ-ग—रेखा ग्राम सवांग के प्लाट सं० 818, 809, 818 और 44 से हो कर जाती है।

ग-ज—रेखा प्लाट सं० 44 की मध्य रेखा के साथ-साथ (धर्यात् सवांग और ससवारा ग्रामों की प्रांशिक सीमा के साथ) जाती है और भारंभ बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

मनुसूची—'ख'
उपखण्ड—'ग'

जी०/प्रार०/जी०/सं० राजस्व/26/74
तारीख 2-7-74

(उन भूमियों को वर्णित करते हुए जिनमें खनिज के अनन्त, खदान, बोर करने, खोखने और उनकी तलाश करने, प्राप्त करने, पर कार्य करते और उनके से जाने के प्रधिकार प्रजित किए गए हैं)।

सवांग प्रधिकार

क्रम सं०	ग्राम	धाना सं०	धाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-णिया
1. सवांग	गुमिया	107	गिरिधीह	भाग		
					कुल क्षेत्र : 61.75 एकड़ (लगभग) या 24.99 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम सवांग में प्रजित प्लाट सं०—818 (भाग), 1281 (भाग), 1282 (भाग) और 1775 (भाग)।

त्रिमा वर्षां

ग-म-ध-फ—रेखाएं ग्राम सवांग के प्लाट सं० 1281 और 818 से हो कर जाती है।

फ-प-न-थ-द-व-त-ण-ड-ड—रेखाएं सवांग ग्राम के प्लाट सं० 818 और 1281 (सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ड-ड—रेखा सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों में कुनार नदी में प्रांशिक द्वाएं किनारे (सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' से साथ भी जिसकी प्रांशिक सामान्य सीमा है) के साथ साथ जाती है।

ठ-ज—रेखा ग्राम सवांग में प्लाट सं० 1775 से हो कर प्रथात् सवांग कोलियरी की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है।

च-ड—रेखा कुनार नदी की प्रांशिक मध्य रेखा के साथ साथ (प्रथात् सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'क' प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

इ-ष—रेखा ग्राम सवांग प्लाट सं० 1282 से हो कर (प्रथात् सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'क' प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

ध-ग—प्रेरेखा कुनार नदी के प्रांशिक द्वाएं किनारे के साथ साथ (प्रथात् सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'क' की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जीती है और भारंभ बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

उपखण्ड—प

सवांग प्रधिकार

क्रम सं०	ग्राम	धाना सं०	धाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्प-णिया
1. सवांग	गुमिया	107	गिरिधीह	भाग	कुल क्षेत्र : 21.00 एकड़ (लगभग) या 8.50 हेक्टेयर (लगभग)	

ग्राम सवांग में प्रजित प्लाट सं० : 803 (भाग), 804 (भाग), 805, 818 (भाग), 825 (भाग), 828 (भाग), 829 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग) और 1281 (भाग)।

त्रिमा वर्षां

इ-य—रेखा ग्राम सवांग में प्लाट सं० 818, 804, 818 और 803 से हो कर जाती है।

य-ट—रेखा ग्राम सवांग में प्लाट सं० 808, 818, 825, 824, 829 और 831 (जिसकी सवांग कोलियरी खान के साथ भागतः सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ट-ड—रेखा ग्राम सवांग में प्लाट सं० 831, 832, 818, 1281 और 818 (जिसको सभी प्रधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है और भारंभ बिन्दु 'म' पर मिलती है।

[सं० फ० 25/24/73-सी 5/सैल]

New Delhi, the 5th September, 1975

S.O. 4189.—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), S.O. No. 690 (E) dated the 8th November, 1973, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and rights specified in the Schedules appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made its report to the Central Government;

' And whereas the Central Government, after considering the report the competent authority and after consulting the Government of Bihar is satisfied that;

(a) the land measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto, and;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government

hereby declares that the land, measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in the said Schedule 'A' and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in the said schedule 'B' are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), "Darbhanga House", Ranchi.

SCHEDULE 'A'

BOKARO BLOCK—I (SAWANG EXTENSION)

EAST BOKARO COALFIELD

SUB- BLOCK—'A'

DRG No. Rev/26/74
Dated 2-7-74
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
2.	Armo	Nawadith (Bermo)	11	Giridih		Part
3.	Gobindpur	"	15	Giridih		Part
Total Area : 60.75 acres (approximately) or 24.58 hectares (approximately)						
Plot number acquired in village Sawang Plot numbers acquired in village Armo Plot number acquired in village Gobindpur						1282 (Part). 474 & 776. 2772 (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B—line passes through Kunar Nadi (i.e. along the Western boundary of plot No. 474 of Village Armo and along the part common boundary of villages Sawang and Sasbera).

B-C-D—lines pass along the part Right Bank of Kunar Nadi in village Sawang.

D-E—line passes through plot number 1282 (Kunar Nadi) of village Sawang (which also forms common boundary with the surface area of Sand Lease of Sawang colliery).

E-F—line passes along the part central line of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Armo, Sawang & Gobindpur) (which also forms common boundary with the Surface area of Sand Lease of Sawang Colliery).

F-G—line passes through plot number 2772 (Kunar Nadi) of village Gobindpur (which also forms part common boundary with Sawang Colliery).

G-A—line passes along the part left Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur & Armo and meet at starting point 'A'.

SUB-BLOCK—'B'

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part.
Total area : 82.00 acres (approximately) or 12.18 hectares (approximately)						
Plot numbers acquired in village Sawang						44 (Part), 808 (Part), 809 (Part), 810 (Part), 818 (Part), 831 (Part), 832 (Part), 1281 (Part) & 1295 (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION :

H-I—line passes through plot numbers 44, 809, 808, 810 and 818 of village Sawang.

I-J-K—lines pass through plot numbers 818, 1281, 818, 832 and 831 of village Sawang (which also forms part common boundary with sub-block 'D' Mining Rights).

K-L—lines passes through plot numbers 831, 832, 1281, 1295, 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

L-M—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur and Sawang (which also forms part common boundary Sub-Block 'C'—(Mining Rights).

SCHEDULE—'B'
SUB-BLOCK—'C'

DRG No. Rev/26/74
Dated 2-7-74

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are acquired).

Mining Rights	Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1. Sawang			Gumia	107	Giridih		Part
Total area : 61.75 acres (approximately) or 24.99 hectares (approximately)							
Plot numbers acquired in village Sawang							
818 (Part), 1281 (Part), 1282 (Part) and 1775 (Part).							

BOUNDARY DESCRIPTION :

C-Y-X-V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang.

V-U-T-S-R-Q-P-O-N-M—lines pass through plot numbers 818 and 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

M-L—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Sawang and Gobindpur (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

SUB-BLOCK—'D'

Mining Rights	Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1. Sawang			Gumia	107	Giridih		Part
Total area : 21.00 acres (approximately) or 8.50 hectares (approximately)							
Plot numbers acquired in village Sawang							
803 (Part), 804 (Part), 805, 818 (Part), 825 (Part), 828 (Part), 829 (Part), 831 (Part), 832 (Part) and 1281 (Part).							
[No. 25/24/73—CS/CEL]							

BOUNDARY DESCRIPTION :

I-Z—line passes through plot numbers 818, 804, 818 and 803 of village Sawang.

Z-K—line passes through plot numbers 803, 818, 825, 828, 829 and 831 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

K-J-I—lines pass through plot numbers 831, 832, 818, 1281 and 818 of village Sawang (which also forms common boundary with Sub-Block 'B' All Rights) and meets at starting point I.

M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'C' Mining Rights.)

V-W—line passes through plot numbers 818, 809, 818 and 44 of village Sawang.

W-H—line passes along the Central line of plot number 44 (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Sisbera and meets at starting point 'H').

नई विज्ञप्ति, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 4190.—कोयला बाले क्षेत्र (प्रजन और बिकास) प्रधि-
नियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों और उसे इस नियम समर्थ बनाने वाली प्रत्य सभी
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग 2,
खड 3, उप-खड (ii) में पृष्ठ 2895-2901 पर प्रकाशित भारत सरकार
के सत्कालीन इसात और खान भवालय के बाने और धारु विभाग की
प्रधिसूचना सं०का०आ० 2630 तारीख 9 अगस्त, 1965 को विद्युतित
करती है।

[सं०का० 19(23)/75(सेल)]

New Delhi, the 10th Sept., 1975

S.O. 4190.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals), No. S.O. 2630 dated the 9th August, 1965, published at pages 2895 to 2901 in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 28th August, 1965.

[No. 19(23)/75 CEL]

का०धा० 4191.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रदीत होता है कि इसे उपर्युक्त अनुसूची में वर्णित भूमियों से कोयला प्राप्त होने की संभावना है:

अत अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त वित्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उनमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के प्रपते धारण की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत धाने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची या उपायुक्त, गिरिधीह (बिहार) में कार्यालय या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1 कौमिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत धाने वाली भूमि में उपर्युक्त सब अधिक, उभत अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में निरिष्ट सब मान चिन, चाटं और अन्य रस्तावेजें, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, गण्डीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को दे देते हैं।

अनुसूची
गोविन्दपुर क्षेत्र
पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र
डाउंग मं० राजस्व/53/74
तारीख 21-12-74
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमियां शांश्वर हैं)

क्रम सं.	प्राम	थाना	थाना सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्दपुर	नवाडीह (बेर्मो)	15	गिरिधीह	भाग

1	2	3	4	5	6
2	प्रामो	नवाडीह (बेर्मो)	11	गिरिधीह	भाग
		कुल क्षेत्र	1660.00	एकड़	(लगभग)
		या	671.77	हेक्टर	(लगभग)

सीमा-वर्णन

ए-सी-	लाइन गोविन्दपुर धाम में कुनार नदी की अधिक पैर्वी सीमा के साथ साथ जाती है।
बी-सी-	लाइन गोविन्दपुर धाम में कुनार नदी की अधिक उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है।
ची-डी-ई-एफ-	लाइन गोविन्दपुर धाम से होकर जाती है।
एफ-ए-	लाइन गोविन्दपुर धाम में होकर जाती है और आरंभ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[स०फ० 19/23/75-सैल]

एस०धा०ए० रिजिस्ट्री, उप-मन्त्रिमण्डप

S. O. 4191.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue section), Darbhanga House, Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar), or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section(7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

GOVINDPUR BLOCK

EAST BOKARO COALFIELD

DRG No. Rev/53/74

Dated 21-12-74

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	Govindpur	Nawadilh (Bermo)	15	Giridih,		Part
2.	Armo	"	11	"		"
Total Area : 1660.00 acres (approximately) or 671.77 hectares (approximately)						

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B—line passes along the part eastern boundary of River Kunar in village Govindpur.

B-C—line passes along the part Northern boundary of River Kunar in village Govindpur.

C-D-E-F—lines pass through village Govindpur.

F-A—line passes through village Govindpur and meets at starting point 'A'.

[No. 19(23)/75-CEL]

S.R.A. RIZVI, Dy. Secy.,

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

का०धा० 4192.—केन्द्रीय सरकार, बहुएक सहकारी सोसायटी प्रधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) की प्रधिसूचना संघ्या एल 11011/2/70-पी० एंड० सी० तारीख 8 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त प्रधिसूचना की शर्त 1 में, क्रम संघ्या (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संघ्याएं अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(13) पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।

(14) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।"

[सं०एल० 11011/2/70-एल० एंड० एम०]

ना० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 11th September, 1975

S.O. 4192.—In exercise of the powers conferred by section 5 B of the Mul-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Cooperation) No. L. 11011/2/70-P&C dated the 8th November, 1973 namely:—

In condition I of the said notification, after serial No. (12) and the entries relating thereto, the following serial No. shall be inserted namely:—

(13) Petrofils Cooperative Ltd., New Delhi.

(14) National Heavy Engineering Cooperative Ltd., New Delhi.

[No. L11011/2/70-L&M]

N. KRISHNAMURTHI, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का०धा० 4193.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद प्रधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड(ख)का प्रत्युत्तरण करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित विश्वविद्यालय द्वारा, प्रत्येक के सम्मुख लिखि गई तिथि से, भारतीय मायकियान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है:—

व्यक्ति का नाम	विश्वविद्यालय का मित्रित की नाम	तिथि
1. डॉ.एस०जे० दामनी एम०डी०, एफ०सी०पी०एस०के०एम० स्कूल विश्वविद्यालय प्राव पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च, भर्मदाबाद-6		6-2-1975
2. डॉ.एम०पी० पाह, प्रिमिपल, मैसूर कस्तुरबा मेडिकल कालेज, भंगलौर विश्वविद्यालय		1-5-1975
3. डॉ. धार०के० मेंदा, एफ०भार० बम्बई एस०सी० धर्म नैशन, भवाने कामा रोड, बम्बई-400001		21-2-1975

अब, यतः उक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) का प्रत्युत्तरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि डॉ.एम०पी० पाह और धार०के० मेंदा इस परिषद के सदस्य बने रहेंगे और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की प्रधिसूचना सं० 5-13/59-चिकित्सा-1 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; यामतः:

उक्त प्रधिसूचना में "खंड (ख) या धारा 3 की उप धारा (1) में निर्वाचित शीर्षक के प्रधीन" क्रम संघ्या 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संघ्या और इससे संबंधित प्रविष्टियों रख ली जायें: यामतः

"11. डॉ.एस०जे० दामनी, एम०डी०; एफ०सी०पी०एस०के० एस० स्कूल धर्म पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च, भर्मदाबाद-6। [सं०सी० 11013/1/75-एम०पी०टी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4193.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956), the following persons have been elected by the University specified against each of them to be members of the Medical Council of India with effect from the date noted against, each, namely:—

Name of person	Name of University	Date of election
1. Dr. S.J. Damany, MD, FCPS, K.M. School of Post-graduate Medicine and Research, Ahmedabad-6.	Gujarat University	6-2-1975
2. Dr. M.P. Pai, Principal, Kasturba Medical College, Bangalore.	Mysore University	1-5-1975
3. Dr. R.K. Menda, FRCS, Amarchand Mansion, Madame Cama Road, Bombay-400001.	Bombay University	21-2-1975

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Dr. M.P. Pai and Dr. R.K. Menda shall continue to be the member of the said Council and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) or sub-section (1) of Section 3", for serial No. 11 and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be substituted, namely :—

"11—Dr. S.J. Damany, MD, FCPS,
K M. School of Postgraduate Medicine and Research,
Ahmedabad-6".

[No. V. 11013/1/75-MPT]

का० आ० 4194.—वन्त चिकित्सा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उप-धारा (2) धारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय दत्त चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद उक्त प्रधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।—
उक्त अनुसूची के भाग 1 में;

(1) क्रम संख्या 14 के सामने, "मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी (आपरेटिव) (डेण्टिस्ट्री) एम०डी०एस० (आपरेटिव) केरल" विषय-विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय।—

"मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी—एम०डी०एस० (प्रास्य) केरल (प्रास्यटिक डेण्टिस्ट्री)।

(2) क्रम संख्या 15 के सामने, मैसूर विषयविद्यालय से संबंधित बैचलर, आफ डेण्टल सर्जरी बी०डी०एस० मैसूर विषयविद्यालय से संबंधित शब्दों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय।—

"मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी—एम०डी०एस० (आपरेटिव मैसूर (आपरेटिव डेण्टिस्ट्री)।

(इस अहंता को तभी मान्यता दी जायेगी जबते कि इसे पहले प्रदान किया गया हो।)

[म०वी० 12017/4/74—एम०पी०टी०]
के० मी० मिश्र, अवर सचिव

S.O. 4194.—in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following amendments in the Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the said Schedule,—

(i) against serial No. 14 relating to the Kerala University, after the entry "Master of Dental Surgery (Operative Dentistry) M.D.S. (Operative), Kerala", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Dental Surgery

(Prosthetic Dentistry) M.D.S.(Pros.), Kerala";

(ii) against serial No. 15 relating to the Mysore University, after the entry "Bachelor of Dental Surgery

78 GI/75—6

B.D.S. Mysore", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Dental Surgery M.D.S. (Operative), (Operative Dentistry) Mysore";

(This qualification shall be recognised only when granted before 12-9-1975).

[V. 12017/4/74-MPT]

K. C. MISRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 4195.—प्रोष्ठि एवं प्रसाधन सामग्री प्रधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ग की उप धारा (7) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में स्ववेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार श्री पी० एन० वी० कुरुप को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के 27 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या एक्स 19012/2/75—ए०पी० सी० मी० के अन्त्रीन गठित आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रौष्ठि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का संविध नियुक्त करती है।

[स० एक्स 19012/2/75—ए०पी० सी०]
पी० वी० इरिहरसंकरन, उप-सचिव

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4195.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 33C of the Drugs and Cosmetics Act 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Shri P. N. V. Kurup, Adviser in Indigenous Systems of Medicine, Ministry of Health and Family Planning to be the Secretary of the Ayurvedic and Unani Drugs Technical Advisory Board constituted under the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Notification No. X.19012/2/75-APC, dated the 27th August, 1975.

[No. X. 19012/2/75-APC]
P. V. HARIHARASANKARAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० आ० 4196.—भूतपूर्व राजस्व तथा कृषि विभाग की अधिसूचना 1616 एक दिनांक 25 जुलाई, 1900 के खंड (क) के नियमों के नियम 3 तथा नियम 4 को दृष्टि में रखते हुए, जिनमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, के अनुसार भारत सरकार (1) श्री वेबी नन्दन प्रसाद सिंह, रत्नाचारा, पी० प्रा० डॉली, मुजफ्फरपुर (बिहार), (2) श्री पी० मुकर्जी, स्टोनी-कापल, शिलोंग (असम) तथा श्री ए० एम० रथनास्वामी, 93, पीटेस रोड, मद्रास के स्थान पर (1) श्री राम लखन, भूतपूर्व सबस्य, विधान, सभा 86 मेलूपुरा, वाराणसी (2) श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, एडवोकेट, प्रकाश पैट्रोल पी० प्रा० सप्तराम, जिला राहताम (बिहार) श्री एन० महालियम, 49 सैन्ट मेरी रोड, मद्रास को इडियन पीपल्स फैमिल ट्रस्ट के प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है। ये नियुक्तियां तत्काल ही प्रभावी होंगी।

[स० 15-2/75/एस० आर० 2]

वास्त्र प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4196.—In accordance with clause (a) of Rule 3 of the Rules published with the late Department of Revenue and Agriculture Notification No. 1616 F dated 25-7-1900 read with Rule 4 thereof as amended from time to time, the Government of India are pleased to appoint (1) Shri Ram Lakhan, Ex-MLA 86 Bhelupura, Varanasi, (2) Shri Jagannath Prasad Singh, Advocate, Prakash Petrol, P.O. Sasaram, Distt. Rohtas (Bihar) and (3) Shri N. Mahalingam 49, St. Mary's Road, Madras as members of the Board of Management, Indian People's Famine Trust with immediate effect vice (i) Shri Devki Nandan Prasad Singh, Ratwara P.O. Dholi, Muzaffarpur (Bihar), (ii) Shri B. Mookherjee, Stonycraft, Shillong (Assam) and (iii) Shri A. M. Rathnaswamy, 93 Peters Road, Madras.

[No. 15-2/75-SR II]

CHANDRA PRAKASH, Dy. Secy.

नोवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 4197.—श्री धी० एस० मानेकर ने, जिसे भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० ३४९६, नारीश० ३ दिसम्बर, १९७३ द्वारा मौर्मुगांगो डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, १९६२ के नियम ४ के उपनियम (३) के अधीन अपना पद त्याग दिया है;

और उक्त सदस्य के पदत्याग से उक्त डॉक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम ४ के उपनियमों के अनुसार में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[सं० एन डी जी/6/13/75 (i)]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4197.—Whereas Shri V. S. Manerkar who was appointed as member of the Mormugao Dock Labour Board by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 3496, dated the 3rd December, 1973, has resigned his office under sub-rule (3) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board by the resignation of the said member;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. LDG/6/13/75(i)]

का० आ० 4198.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, १९६२ के नियम ४ के उपनियम (१) के द्वितीय परन्तुक के भार पठित डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ९) की धारा ५क की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त वक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी० के० उणी को मौर्मुगांगो डॉक

श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत मंत्रालय के अम श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० १२२०, नारीश० १५ अप्रैल, १९६५ में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रक्रिया:—

उक्त अधिसूचना में, “डॉक कर्मकारों और नौवहन वाप्तियों के नियोजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य” शीर्षक के अन्तर्गत, मद (२) के सामने, “श्री धी० एस० मानेकर” प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “श्री टी० के० उणी” रखी जाएगी।

[सं० एन डी जी/6/3/75 (ii)]

श्री० संकारालिङ्गम्, अवार सचिव

S.O. 4198.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri T. K. Unny as a member of the Marmugao Dock Labour Board and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1220 dated the 5th April, 1965, namely :—

In the said notification under the heading “Members representing the employers of dock workers and shipping companies, against item (2); for the entry “Shri V. S. Manerkar”, the entry “Shri T. K. Unny” shall be substituted.

[No. LDG/6/13/75 (ii)]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

CORRIGENDUM

(Merchant Shipping)

S.O. 4199.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 442, dated the 31st January, 1975, published on page 614 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th February, 1975 in line 4 for “1970”, read “1960”.

[No. 12-MAO(146)/74-MA]

D. C. AHIR, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, ९ सितम्बर, १९७५

का० आ० 4200.—जम्मू टेलीफोन एकमध्ये प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के संबंध में एक गार्वैतिक सूचना जम्मू में प्रथमित भमालार पक्षों में प्रकाशित की गई थी; जैसा कि भारतीय तार नियम १९५१ के नियम ४३४ (iii) (ख ख) में प्रवेशित है, वे सभी व्यक्ति, जिन पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, अपनी आपत्ति और सुमाध इग सूचना के नामाचारणों में प्रकाशित होने की तारीख से ३० दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

जनगाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना ४, ९ और ११ फरवरी, १९७५ को अमरण: “इमारत”, “सन्देश” तथा “कौमी आवाज” दैनिक समाचारपत्रों में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जनसाधारण ने कोई भी आपत्ति और सुभाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (iii) (ख ख) तारा प्रवत्त सार्वजनिकों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिवेशक एवं द्वारा घोषणा करते हैं कि 1-10-1975 से जम्मू का संशोधित स्थानीय क्षेत्र नियम प्रकार होगा।

जम्मू टेलीफोन एवं वेब प्रणाली

जम्मू भा स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो फैसला निवाला के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु आ टेलीफोन उपभोक्ता जम्मू नगर-पारिवार सीमा के बाहर स्थित है, लेकिन जिन्हें जम्मू टेलीफोन एवं संबंधित प्रणाली से सेवा प्रदान नी जाती है, वे इस व्यवस्था के अन्तर्गत एवं संबंधित प्रणाली से जब तक 5 कि. मी० तकी दूरी के भीतर स्थित हैं, वे इस व्यवस्था से जम्मू टेलीफोन एवं संबंधित प्रणाली से अद्यापर्याप्त रूप से प्रदान करते हैं।

[मा० 3-16/74-PH-B(1)]

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4200.—Whereas a public notice for revising the local area of Jammu Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Jammu, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 11th February, 1975 in Daily "Quami Awaz", on 8th February 1975 in Daily "Imarat" and on 9th February, 1975 in Daily "Sandesh" Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-10-1975 the revised local area of Jammu shall be as under:

Jammu Telephone Exchange System :

The local area of Jammu shall cover an area falling under the jurisdiction of Jammu Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Jammu Municipality limit but who are served from Jammu Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located with 5 kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-16/74-PHB]

भारत दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का. आ. 4201.—उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना उदयपुर में प्रवालत समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ख) में संशोधित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वे सभी अपनी आपत्ति और सुभाव इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 7 और 10 जूलाई 1975 को दैनिक समाचार पत्र "जय राजस्थान" में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जनसाधारण से कोई भी आपत्ति और सुभाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (3) (ख ख) इसार प्रदर्श सार्वजनिकों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिवेशक एवं द्वारा घोषणा करते हैं कि 1-10-1975 से उदयपुर का संशोधित स्थानीय क्षेत्र नियम प्रकार होगा :

उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

उदयपुर का स्थानीय क्षेत्र यही होगा जो कि उदयपुर नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता उदयपुर नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें उदयपुर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक्सचेंज रो जब तक 5 कि. मी० दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायी करेंगे।

[सं. 3-12/74-पी. एन बी (1)]

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 4201.—Whereas a public notice for revising the local area of Udaipur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Udaipur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th July and 10th July 1975 in Daily Newspaper "Jai Rajasthan";

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-10-1975 the revised local area of Udaipur shall be as under :

Udaipur Telephone Exchange System :

The local area of Udaipur shall cover an area falling under the jurisdiction of Udaipur Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Udaipur Municipal limit but who are served from Udaipur Telephone Exchange system shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(1)]

का. आ. 4202.—भीलवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना भीलवाड़ा में प्रविलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ख) में अपीक्षित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वे सभी अपनी आपत्ति और सुभाव इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 7 और 10 जूलाई 1975 को दैनिक समाचार पत्र "नवज्योगीत" में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपैर और सुभाव प्राप्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपैर और सुभाव

उक्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपैर सुभाव प्रदृश शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकनार महानदेशक एवं स्थानीय घोषणा करते हैं कि 1-10-75 से भीलवाड़ा का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

भीलवाड़ा टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

भीलवाड़ा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि भीलवाड़ा नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टैलीफोन उपभोक्ता भीलवाड़ा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं तेकिन जिन्हें भीलवाड़ा टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि. मी. दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शूल्क वर से अवायगी करेंगे।

[स. 3-12/74-पी. एच. बी (2)]

S.O. 4202.—Whereas a public notice for revising the local area of Bhilwara Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bhilwara, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th July 1975 in Daily Newspaper "Navjyoti"

And whereas no objection and suggestion, have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-10-1975 the revised local area of Bhilwara shall be as under :

Bhilwara Telephone Exchange System.—The local area of Bhilwara shall cover an area falling under the jurisdiction of Bhilwara Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Bhilwara Municipal limit but who are served from Bhilwara Telephone Exchange system shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any Exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(ii)]

का. आ. 4203.—जोधपुर टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना जोधपुर में प्रचलित समाधार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि भारतीय तात्र नियम 1951 के नियम 434 (3) (ख ल) में अपेक्षित है। जिन व्यक्तियों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वे सभी अपनी आपैर और सुभाव इस सूचना के समाधार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का काष्ट करें।

सर्व साधारण की जानकारी के लिए उक्त सूचना 10 दिसम्बर, 1974 को "सर्व राजस्थान" "जलते दीप" और "जनगण" द्वारा समाचार पत्रों में निकाली गई थी।

उक्त सूचना पर जन साधारण से कोई भी आपैर और सुभाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब उक्त नियम के नियम 434 (3) (ख ल) क्षारा प्रदृश शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकनार महानदेशक एवं स्थानीय घोषणा करते हैं कि 1-10-75 से जोधपुर का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

जोधपुर टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

जोधपुर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि जोधपुर नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। किन्तु जो टैलीफोन उपभोक्ता भीलवाड़ा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें जोधपुर टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि. मी. दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, तब तक स्थानीय शूल्कदर से अवायगी करेंगे।

[स. 3-12/74 पी. एच. बी. (3)]

एच. सी. माथुर, निदेशक

S.O. 4203.—Whereas a public notice for revising the local area of Jodhpur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Jodhpur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 10th December 1973 in Daily Newspapers "Tarun Rajasthan", "Jalte Deep" and "Jangan";

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that, with effect from 1-10-1975 the revised local area of Jodhpur shall be as under;

Jodhpur Telephone Exchange System.—The local area of Jodhpur shall cover an area falling under the jurisdiction of Jodhpur Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Jodhpur Municipal limit but who are served from Jodhpur Telephone Exchange system shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any Exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB(iii)]

H. C. MATHUR, Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का. आ. 4204.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (4) द्वारा प्रदृश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न बगों के मालदिल्लों के लिए, मालदिल्लों के प्रत्येक बगों के संबंध में विनियिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिकृत वहन अमता नियत करती है, प्रतिति:—

क. बड़ी लाइन मालदिल्लों :—

1. अनुज्ञात अधिक लदान की सीमा :—

(1) 4 पहिये या 6 पहिये वाले मालदिल्लों में दो भीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें एक भीटरिक टन की लदान सहायता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

(2) बी और एक्स, बी और आई, बी आर एस, बी ग्राह एच, बी सी एक्स, बी और बी एस या किसी बी और बी एक्स मालडिब्बों के सिवाएँ किसी बोगी मालडिब्बे में चार मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें दो मीटरिक टन की लदान सहयता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

2 अधिक लदान की शर्तें

- (1) अधिक लदान केवल $10'' \times 5''$ और $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ धुरे के मालडिब्बों को ही लागू होगा और यह तब जब कि धुरे का व्यास त्रिमाण: $4.5/8''$ और $4.3/16''$ से नीचे न गिरे।
- (2) बोगी मालडिब्बों की दशा में, भार सम्बितरित किया जाएगा।
- (3) अधिक लदान, किसी भी परिस्थिति में, अमानक बी एक आर्स पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और केवल मानक टाइप बोगी रेल ट्रक (बी आर्स) पर अधिक लदान किया जा सकेगा।
- (4) भारतीय रेल सम्बेलन संगम पथ निर्बंधन नक्शे में यथा उपर्युक्त अधिकतम अनुज्ञय धुरी भार को बढ़ाया नहीं जाएगा।

छोटी लाइन मालडिब्बे :—

1 अनुज्ञात अधिक लदान की सीमा :—

- (1) 4 पहिये या 6 पहिये वाले मालडिब्बे में एक मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें $\frac{1}{2}$ मीटरिक टन की लदान सहयता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।
- (2) बोगी मालडिब्बे में दो मीटरिक टन की सीमा तक, जिसमें एक मीटरिक टन की लदान सहयता भी सम्मिलित है, अधिक लदान किया जा सकेगा।

2 अधिक लदान की शर्तें :—

- (1) अधिक लदान केवल $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ और $7'' \times 4''$ धुरे के मालडिब्बों को ही लागू होगा और यह तब जब कि धुरे का व्यास त्रिमाण: $4''$ और $3.11/16''$ से नीचे न गिरे।
- (2) भारतीय रेल सम्बेलन संगम पथ निर्बंधन नक्शे में यथा उपर्युक्त अधिकतम अनुज्ञय धुरी भार को बढ़ाया नहीं जाएगा।

ग. बड़ी लाइन और छोटी लाइन मालडिब्बे :—

किन्तु 4 पहिये वाले माल डिब्बों, 6 पहिये वाले मालडिब्बों या बोगी मालडिब्बों जिनमें उनके धुरे का व्यास ऊपर विहित सीमाओं से नीचे होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से जिनसे ये अधिक लदान के प्रयोग हो जाते हैं, इस प्रकार अधिक लदान नहीं किया जा सकता, पर यह वर्णने के लिये कि ऐसे मालडिब्बों में अधिक लदान अनुज्ञात नहीं है, निम्नलिखित चिह्न होगा :—

“मालडिब्बों के दोनों और वहन अमता के घंटों के साथ-साथ पाहन्टों के सामने भार नोक आला श्वेत तारक 125 एम एम (5") होगा।”

[स० 75/एम (एन०)/951/69]
ए० एस० गुप्ता, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4204.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 53 of the

Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby fixes the maximum carrying capacity for the various classes of wagons, subject to the conditions, specified in relation to each class of wagons, namely :—

A. Broad Gauge wagons :—

1. Extent of overloading permitted—

- (1) A 4-wheeler or a 6-wheeler wagon may be overloaded to the extent of two tonnes inclusive of the loading tolerance of one tonne.
- (2) A bogie wagon except a BOX, BOI, BRS, BRH, BCX, BOBS or a BOBX wagon may be overloaded to the extent of four tonnes inclusive of the loading tolerance of 2 tonnes.

2. Conditions for overloading—

- (1) The overloading shall apply only to wagons with $10'' \times 5''$ and $9''$ into $4\frac{1}{2}''$ journals provided that the journal diameter is not turned below $4.5/8''$ and $4.3/16''$ respectively.
- (2) In the case of bogie wagons, the load shall be evenly distributed.
- (3) The overloading shall under no circumstance be permitted on non-standard BFRs and only the Standard type bogie rail trucks (BRs) may be overloaded.
- (4) The maximum permissible axle loads, as shown in the Indian Railway Conference Association Track Restriction Map, shall not be exceeded.

B. Metre Gauge Wagons :—

1. Extent of overloading permitted—

- (1) A 4-wheeler or a 6-wheeler wagon may be overloaded to the extent of one tonne including loading tolerance of $\frac{1}{4}$ tonne.
- (2) A bogie wagon may be overloaded to the extent of two tonnes including loading tolerance of 1 tonne.

2. Conditions for overloading :—

- (1) The overloading shall apply only to wagons with $9'' \times 4\frac{1}{2}''$ and $7'' \times 4''$ journals provided that the journal diameter is not turned below $4''$ and $3.11/16''$ respectively.
- (2) The maximum permissible axle load, as shown in the Indian Railway Conference Association Track Restriction Map, shall not be exceeded.

C. Broad Gauge and Metre Gauge wagons.—A 4-wheeler wagon, a 6-Wheeler wagon or a bogie wagon which can not be so overloaded owing to its journal diameter being below the limits prescribed above or for any other reasons which render them unfit for overloading, shall bear the following marking to indicate that overloading is not permitted on such wagons :—

“A four-pointed white star 125 mm(5") across the points along side the figure of the carrying capacity on both sides of the wagons.”

[No. 75/M(N)/951/69]
A. L. GUPTA, Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 4205.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्र अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री मासी ताल भागवत प्रसाद, बलुआ पत्थर आन स्वामी, बाहेटा, लाक घर करोली, जिला सवाई माधो-पुर (राजस्थान), की बोहेर्टी बलुआ पत्थर आन, करौली के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीधोगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद भी न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करता बांधनीय समझती है;

अतः, अब, श्रीधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 वीं वारा, 10 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत (प) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की वारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रीधोगिक अधिकारण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री मासीताल भागवत प्रसाद, आन स्वामी, करोली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान की बोहेर्टी बलुआ पत्थर की आनों में नियोजित कर्मकार, संवेतन शौहर के और राष्ट्रीय श्रवकाश-दिनों की मंजूरी के हकदार हैं? यदि हाँ तो कितने और कितने अवसरों पर और किस तर्ज से?

[संख्या एल 29011/43/75-डी० आ० (3बी०)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 4205.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Baharta Sand Stone Mine, Karauli of Shri Mangil Bhagwat Prasad, Sand Stone Mine Owner, Baherta, Post Office Karauli, District Sawaimadhopur, (Rajasthan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Baherta Sand Stone Mines of Shri Mangil Bhagwat Prasad, Mine Owner, Karauli, District Sawaimadhopur, Rajasthan are entitled to grant of paid festival and national holidays? If so, how many and on what occasions and from which year?

[No. L-29011/43/75-D.O. 3(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

का० आ० 4206.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्र अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईंडिया सीमेण्ट्स

लिमिटेड डाकघर, शंकर नगर जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीधोगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांधनीय समझती है;

अतः, अब, श्रीधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं श्रीधोगिक अधिकारण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी विल टी० पालानीप्रपत होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकारण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ईंडिया सीमेण्ट्स लिमिटेड, शंकरनगर धर्सन, डाकघर शंकर नगर जिला तिरुनेलवेली के प्रबन्धतंत्र की, श्री टी० गणपति, ड्रिलर, सेजीनाल्लुर लाइमस्टोन फैब्रीरी, को 28 अगस्त, 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?

[संख्या एल-29011/95/75-डी० आ०-3बी०]

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1975

S.O. 4206.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs India Cements Limited, Sankarnagar Post Office, District Tirunelveli, Tamil Nadu, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the India Cements Limited, Sankarnagar Works, Sankarnagar Post Office, District Tirunelveli, in dismissing Shri T. Ganapathy, Driller, Sezhinallur Limestone Quarry, from service with effect from the 28th August, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/95/75-D.O. III. B]

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

का० आ० 4207.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्र अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में टाटा केमिकल्स लिंग, डाकघर राजावाह, जिला जूनागढ़, गुजरात के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीधोगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांधनीय समझती है;

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के अंडे (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीत अधिकारी श्री एम० य० आहार होगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद पर उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड, आक्षर रानाबाबा, जिला जूनागढ़, गुजरात के प्रबन्धतत्र का पत्थर खदान, रानाबाबा, गुजरात के द्वंद्व चापक श्री जयपाल भिह औ० ठाकुर की सेवा, 24 अक्टूबर, 1974 में समाप्त करना न्यायोजित है? यदि नहीं तो कर्मकार किम अनुतोष का हवायार है?

[मध्या एल-29011/89/75-डी-३(भी)]

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1975

S.O. 4207.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to management of Tata Chemicals Limited, Post Office Ranavav, District Junagadh, Gujarat, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri M. U. Shah as Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the termination of services of Shri Jaipal Singh B Thakur, a Truck Driver of Stone Quarry, Ranavav, Gujarat, with effect from 24th October, 1974 by the management of Tata Chemicals Limited, Post Office Ranavav, District Junagadh, Gujarat, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No L-29011/89/75-D III B]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जूलाई, 1975

का आ० 4208.—केन्द्रीय सरकार की गय है कि इस में उपावक्ता अनुगृही में विनिर्दिष्ट विषयों के थारे में गार्डीय कोल्याका विकास लिमिटेड (नेशनल सोल इवेन्यूमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड) की कुरागिया कोलियरी, जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश के प्रबन्धतत्र से सबड़ नियोजित है और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वालीनीय समझसी है,

अत अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंडे (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या राष्ट्रीय कोल्या विकास लिमिटेड (नेशनल सोल इवेन्यूमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड) की कुरागिया कोलियरी जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश के प्रबन्धतत्र की उक्त कोलियरी के द्वारा में निम्नलिखित असिक्ति कार्य लेना न्यायोजित है? यदि नहीं, तो उक्त कोलियरी के द्वारा किया अनुतोष के हकदार है और किस तारीख से?

- (क) उत्स्कोटक (शाटफायरर) कले कारतूस देकर गूराखों को भरने में उसकी महायता करना,
- (ख) जब उत्स्कोटक शाटफायरर सीढ़ी पर भड़ कर सूराखों को भरने से न हो, तो उन्हें स्थानों पर सीढ़ी हो पाना,
- (ग) छत की सतह और कर्णों को सवारना,
- (घ) सधीन द्वारा काटे गए फेंस से अधिनियासीनों को साफ़ नहाना ताकि सूराख करने के लिए फेंस भाफ़ किया जा सके,
- (ङ) उन्हें कारतूसों को इलाके में ले जाना और उनका उद्दिष्ट जनत्र स्थानों पर छटा बाधना और जैसे भौं और जब आवारणक तारामूसों को बाधने के लिए उन्हें फेंसों पर ले जाना

[संख्या एल-22011/7/74-एल०आर-2/डी-२ वी]

एस० एस० एम० अम्बर, अनुभाग अधिकारी (विषेष)

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

S.O. 4208.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kurasia Colliery, District Surguja, Madhya Pradesh, of National Coal Development Corporation Limited, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Kurasia Colliery, district Surguja, Madhya Pradesh, of National Coal Development Corporation Limited, in taking the following extra work, namely;

- (a) helping the Shotfirer in charging the holes by handing him clay cartridges
- (b) holding the ladder in high places when the shotfirer is engaged in charging the holes by climbing a ladder,
- (c) dressing the roof side and floor,
- (d) cleaning the gummings from the machine cut face to make the face clean for drilling the holes,
- (e) carrying the clay cartridges within the district and stacking the same at the convenient places and carrying the same to faces as and when required for stemming the charges,

from the dressers of the said colliery is justified? If not, to what relief the dressers of the said colliery are entitled and from what date?

[No. L-22011/7/74/IRII/DIIIB]

S. H. S. TYFR, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

आदेश

का० आ० 4209.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सन्वाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित श्रौद्धोगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची]

क्या पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली प्रदेश, श्री महादेव प्रसाद शुक्ल, प्रधान चपराही की जन्म-तिथि में परिवर्तन न करना और उसकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति को प्रवर्तित करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल० 12012/51/75/डी०-२८]

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1975

S.O. 4209.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Punjab National Bank, Delhi Region, is justified in not altering the date of birth of Shri Mahadeo Prasad Shukla, Head Peon and enforcing his premature retirement from service? If not, to what relief is the said workmen entitled?

[No. L-12012/51/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 4210.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक श्राफ इंडिया से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित श्रौद्धोगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक श्राफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रबन्धताल की, श्री विरेन्द्र कुमार, अंग्रेजीलिक पास बुक लेखक की सेवाएँ, 9 जुलाई, 1974 से अमान्य करने और उक्त कर्मकार को पूर्णकालिक लिपिक के रूप में नियुक्त न करने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल० 12012/71/75-डी०-२८]

ORDER

S.O. 4210.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India, New Delhi in terminating the services of Shri Virendra Kumar, Part-time pass book writer with effect from the 9th July 1974 and in not appointing the said workmen as full time clerk is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/71/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 4211—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धताल से भम्बू नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित श्रौद्धोगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची]

क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धताल की, श्री नरद किशोर काल्मीकी की 21 जुलाई, 1970 की और उसके पश्चात् प्रति वर्ष 21 जुलाई, को बेतन-बृहि ने देने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल० 12012/73/75-डी०-२८]

ORDER

S.O. 4211.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank in not granting increment to Shri Nand Kishore Balmiki on 21st July, 1970 and subsequently on 21st July every year is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/73/75/D-II/A.]

तर्हि विलम्बी, 11 अगस्त, 1975

आवेदन

का० आ० 4212.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटेड बेस्टर्न बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आंदोलिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, आंदोलिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित आंदोलिक अधिकरण, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या यूनाइटेड बेस्टर्न बैंक लिमिटेड, मुम्बई के लिए श्री आर०वी० पटवर्धन द्वारा 8 जनवरी, 1975 को दिया गया त्यागपत्र स्वेच्छा से था और क्या उसे प्रबन्धालय द्वारा स्वीकार कर दिया गया था? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हक्कार है?

[संख्या० ए८ 12012/69/75-डी०-२५]

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1975

S.O. 4212.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the United Western Bank Limited, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the resignation letter given by Shri R. V. Patwardhan clerk of the United Western Bank Limited, Bombay on 8th January, 1975 was voluntary and whether the same was accepted by the Management? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/69/75/DII/A]

आवेदन

का० आ० 4213.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ पटियाला से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मकारों के बीच एक आंदोलिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, आंदोलिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक आंदोलिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच०आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय अड्डेगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त आंदोलिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला, पटियाला के प्रबन्धालय का, उक्त बैंक की मेहम शास्त्रा के सशस्त्र-रक्षक श्री मार्गहर सिंह की सेवाएं 18 फरवरी, 1975 से समाप्त करना चाहीय चित्त है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हक्कार है?

[संख्या० ए८ 12012/72/75-डी० 2५]

ORDER

S.O. 4213.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Patiala and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

Whether the management of State Bank of Patiala, Patiala is justified in terminating the services of Shri Magher Singh, Armed Guard of the Meham Branch of the said Bank with effect from the 18th February, 1975? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/72/75/DII/A]

आवेदन

का० आ० 4214.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ीदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आंदोलिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, आंदोलिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक आंदोलिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री कौ०एन० श्रीवास्तव होंगे जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त आंदोलिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्षमा बैंक बड़ीया के प्रबन्धतंत्र का श्री नरेन्द्र मिश्र शेखा-एवं-रोकड़ लिपिक, पीलीभीत, की सेवाएं 18 अप्रैल, 1973 से समाप्त करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हक्कदार है?

[संख्या एल० 12012/135/73-एल०प्रा०-3]

ORDER

S.O. 4214.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. N. Srivastava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of Baroda was justified in terminating the services of Shri Narendra Singh, Accounts-cum-cash clerk, Pilibhit, with effect from the 18th April, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/135/73/LRIII]

प्रावेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4215.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में सेट्स बैंक ब्रांफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आधिकारिक विवाद विद्यमान है।

मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, प्रब्र. आ० 4215.—केन्द्रीय सरकार प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक आधिकारिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० प्रा० २०० सौधी होंगे जिनका मुद्यालय चंडीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त आधिकारिक अधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्षमा सेट्स बैंक इंडिया, चंडीगढ़ के प्रबन्धतंत्र की उक्त बैंक के प्रदेशत बाजार पटियाला रियल शेखा के उपस्थिती एवं उपरासी श्री करतार सिंह को लिपिक के रूप में प्रोमोटि न देने की कार्यवाही भेदभाव पूर्ण और अनुचित अम-व्यवहार का कृत्य है? यदि ऐसा है तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हक्कदार है?

[संख्या एल०-12012/81/75-डी-2]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1975

S.O. 4215.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in denying promotion to Shri Kartar Singh, Daftari-cum-Peon, Adolat Bazar, Patiala of the said Bank as clerk is an act of discrimination and unfair labour practice? If so to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/81/75/DII/A]

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4216.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to Ruby General Insurance Company Limited Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd September, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A., LL.B., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 8 of 1970

BETWEEN

Workmen of Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch.

AND

Management of Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch.

APPEARANCES :

Sri M. Panduranga Rao, Advocate—for Workmen.

Shri B. K. Seshu, Hon. Secretary, Federation of A. P. Chambers of Commerce & Industry—for Management.

AWARD

This dispute is now before me for adjudication as per an order of remand dated 4-11-1974 passed by the High Court of Andhra Pradesh for reconsideration of the question whether the claimant should be reinstated in service or payment of compensation could be the adequate consequential relief.

2. Facts necessary for the disposal of the question now in issue briefly stated are these:—The petitioner claimant joined the service of the Respondent—Company in March, 1958 as a Typist-cum-Clerk. He was later promoted as Accountant in the year 1962. His services were terminated with effect from 2-9-1968. On a direction issued by the High Court, the Government of India referred the following question for adjudication by the Industrial Tribunal at Hyderabad.

“Whether the Management of the Ruby General Insurance Company Limited was justified in terminating the services of Shri M. Vishwanath, a workman of the Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad Branch with effect from the 2nd September,

1968 ? If not, to what relief is Shri M. Vishwanath entitled ?"

3. The reference was registered as Industrial Dispute No. 8 of 1970 and notices were directed to both the parties. The workman filed a claim statement inter alia alleging his appointment in the month of March, 1958 as Clerk and his promotion as an Accountant on 1st November, 1962 by the Respondent. On promotion as an Accountant, he was drawing Rs. 175.00 per month. He received increments from time to time and was drawing a sum of Rs. 425.00 as on the date of termination. It is however alleged that an increment of Rs. 40.00 ordered to be paid on 26-5-1967 was not given effect to. The Branch Manager of the Hyderabad Branch, Sri Preetam Singh, is said to have taken utter dis-like to him, and wrote false complaints against him to the Head Office. Out of malice the said Branch Manager got him transferred to Aurangabad on 1-7-1968. The transfer is characterised as a mala fide one and intended to harass the Petitioner. The Petitioner however joined service at Aurangabad but the Branch Manager got an Order issued by the Divisional Manager on 2-9-1968 terminating the services of the Petitioner with immediate effect. This order was received by the Petitioner on 6-9-1968. It is contended that though this purported to be an order of termination it was in effect a cloak for dismissal, as by a letter dated 17 March, 1968, Several allegations of misconduct were said to have been made against the Petitioner. No opportunity was given to him to refuse the allegations. The order that followed is said to be violative of principles of natural justice and illegal. As per the contract of employment, the Management is said to have no power to pass an order of termination with one month's notice. The order, is therefore said to be void and illegal. The petitioner is said to have addressed a letter dated 27th September, 1968 asking for the details of allegations so that he could answer them. But by a letter dated 5th October, 1968 the Divisional Manager is said to have informed him that his services were properly terminated and that the petitioner can collect his dues from the Branch Office after signing the vouchers. On 14-10-1968 the Petitioner was served with the letter purporting to have been issued on 6th September, 1968 that in all a sum of Rs. 825.00 would be paid to him. The Branch Manager insisted that the Petitioner should sign the final settlement Memo which the Petitioner refused and he addressed a letter to the Divisional Manager, Bombay on 16-10-1968. To this a reply was sent to him stating that any further correspondence would not be replied at all. It is contended that the notice pay was not paid as part of the same transaction of termination and therefore, the order of termination is illegal. It is also contended that the said order is the outcome of personal malice which the Branch Manager bore against the Petitioner. It is thus contended that the Petitioner is entitled to reinstatement.

4. In the counter filed by the Respondent, it was contended that the Petitioner was employed mainly in a managerial capacity as Incharge of the accounts of the Branch Office and he thus not being a workman, the Industrial Disputes Act has no application and the Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the reference. It is, however, conceded that at the time of the termination the Petitioner was incharge of the accounts section and was drawing emolument amounting to Rs. 425.00. As regards the increment of Rs. 40.00 referred in the claims statement it is urged that though the Branch Manager with good faith recommended the said increment, the Head Office rejected the same as the Petitioner was not entitled to it. It is denied that the Branch Manager bore any ill-will towards the Petitioner or that he made any complaints against him to the Head Office. It is also denied that on account of the malice of the Branch Manager, the Petitioner was transferred to Aurangabad on 1-7-1968. The order of termination dated 2-9-1968, was a termination simpliciter and was done in pursuance of the inherent right of the Management. It is denied that it was a cloak for dismissal or that it was on account of any allegations of misconduct. It is contended that inspite of many allegations against the Petitioner opportunities were afforded to him and the Petitioner was warned from time to time. The termination order is said to be in no way violative of principles of natural justice. The Management is said to have the power to pass such an order with one month's notice, and it accordingly passed a proper termination order stating that he can collect the dues from the Branch. It is denied that the Branch Manager insisted upon the Petitioner to sign any final Settlement memo. It is also denied that the termination order was the outcome of the malice of the Branch Manager. It is averred that the

Petitioner was treated by the Company very well but he started making false allegations against the Branch Manager itself. The Petitioner was advised from time to time to rectify his behaviour. The allegations made by the petitioner were said to have been enquired into by the Divisional Manager and they were found to be baseless. The warning given to him was said to be of no avail. The Petitioner started neglecting his routine work and income tax returns were not submitted by him regularly. The Petitioner gave advances to the staff members without the prior permission of the Branch Manager. The amounts were not deposited in the Bank from time to time regularly. A Memo was issued to him on 7-10-1967 to which the Petitioner replied on 11-10-1967. The language and the tenor of the reply is said to border upon in subordination for which disciplinary action could have been taken but the Management gave another opportunity to the Petitioner to improve. On transfer to Aurangabad, the Petitioner, instead of attending to the business of the Company and improving the same, is said to have picked up quarrels with M/s. Kailash Motors, Aurangabad, a valuable client of the Company which was giving a premium of Rs. 1,50,000.00 a year. The said Kailash Motors wanted the Petitioner to be transferred from that place. As the Respondent could not afford to loose the business at Aurangabad the Petitioner was asked to get back to Hyderabad and await further orders. But instead, he went to Bombay ignoring the instructions given to him by the Divisional Manager. It is thus contended that in view of the past conduct and behaviour the Management lost confidence in the Petitioner particularly when he was incharge of a responsible post of the Company. Instead of making it difficult for a petitioner to get an alternative employment, the Management considered it fit to terminate his services by way of termination simpliciter. Even after the termination the Petitioner is said to have indulged in writing articles defaming the character of the Branch Manager and undermining the reputation of the Company and its officers. In view of the alleged loss of confidence it was contended that the Petitioner is not entitled to any reinstatement. It was also urged that the Management was ready and willing to prove the charges levelled against the Petitioner before the Tribunal. Thus the claim was sought to be rejected.

5. The claimant-workman examined himself as W.W.1 and relied upon Exs. W1 to W13 by way of documentary evidence. In rebuttal the Branch Manager of Hyderabad Branch was examined as M.W.1 and the Divisional Manager of Bombay was examined as M.W.2 and Exs. M1 to M31 were relied upon by way of documentary evidence.

6. The Tribunal in the first instance held that the order of termination was bad, but instead of the order the reinstatement of the workman, it held that the Respondent should pay compensation of Rs. 4,887.50 together with a sum of Rs. 425.00 to the claimant. Aggrieved by this award the workman filed Writ Petition No. 5429 of 1972 contending that he is entitled to be reinstated. The operative portion of the order of the High Court in the Writ Petition is as follows :—

"I have already pointed out that the Tribunal must take an overall picture of the situation and consider fairly and objectively all the circumstances in favour of and against reinstatement. Since that has not been done in the present case the award of the Tribunal is quashed to that extent and the Tribunal is directed to reconsider the question whether the Petitioner should be reinstated in service or payment of compensation only should be ordered."

7. The question holding the dismissal order being bad having become final, the only point for consideration is whether the reinstatement of the workman should be ordered or the Respondent should be ordered to pay compensation only. After remand the workman has examined W.W.2 in further oral evidence. But the Management was content with the evidence already on record.

8. The law is well settled that on setting aside the dismissal order or the termination order, the employee is entitled for reinstatement. It is true that in exceptional cases where reinstatement cannot be ordered payment of compensation is the other alternative. The question therefore is whether there exist exceptional circumstances to make a departure from the ordinary rule of ordering reinstatement. His Lordship Chinnappa Reddi J. has set out in the order of

remand the factors to be considered cumulatively, for and against the claimant bearing in mind the underlying principle of industrial adjudication that the workman is entitled to the security of his tenure unless there are strong grounds which go against him. The factors in favour of reinstatement are therefore the following :

1. The ordinary rule of reinstatement.
2. The service of 10-1/2 years put in by the claimant.
3. The grant of regular increments from time to time upto the date of termination.
4. His promotion in July, 1968.
5. The circumstance that his integrity was never doubted and last but not the least the absence of any prospect of his appointment as the claimant has crossed the age of 40 years.

It was on the other hand contended by the Management that the claimant was working as an Accountant in a small establishment and he was holding a post of confidence but in that capacity he abused his powers and paid advances without the sanction or permission of the Branch Manager for which he was issued a Memo. Similarly in the capacity of an Accountant though there was a duty cast upon the claimant to submit the income tax returns, he defaulted in submitting them and this has caused untold inconvenience to the Branch. The claimant was also in the habit of proceeding on leave without prior sanction which was a breach of the discipline. Lastly the performance of the claimant at Aurangabad in connection with Kailash Motors jeopardised the interests of the Company, in the sense that on account of the claimant not keeping good relations with the said Motors, the Insurance Company was faced with the risk of losing a very valuable customer. All these circumstances led to the loss of confidence. It was thus contended that the reinstatement of such a workman is neither just nor reasonable.

9. Before advertiring to the consideration of the above circumstances for or against the claimant in detail, a contention put forward on behalf of the workman deserves consideration. The arguments was that the Branch Insurance Office at Hyderabad is a commercial establishment within the meaning of Section 2(5) of the Shops and Establishments Act. M.W.1 though confronted with this aspect was not in a position to deny or affirm whether this branch was registered under the Shops and Establishments Act. However it can be said that the Insurance Establishment either it be a Branch or a Head Office is a commercial establishment within the meaning of Section 2(5) of the Shops and Establishments Act. Section 40 of the said Act lays down that the termination of the employees services can be made atleast with one month's notice in writing or wages in lieu thereof. The contention of the learned counsel for the workman is that orders of termination can both be of void and voidable nature. The first category of cases cover those which are void on account of the non-compliance of the above referred to provisions of Section 40. The latter type of cases take into their habit such cases where the termination order is held to be bad for want of proper domestic enquiry or otherwise. In cases of void orders of termination, it is contended that reinstatement follows automatically. As to the scope of Section 40 the learned counsel for the workman relied upon the judgment of Andhra Pradesh High Court rendered by his Lordship Chinnappa Reddi J. in Writ Petition No. 705 of 1973. Dealing with Section 40 of the Shops and Establishments Act it was observed :

"Where the prescribed notice is not given there can be no termination of service without payment of wages etc."

In the instant case it is contended that under Ex. W9, the order of termination, all that is said is that the workman will paid one month's notice salary in lieu of notice together with legitimate dues, but while passing the termination order the actual payment was not made. Thus the contention proceeded that as the one month's wages were not paid along with the termination order the said Order is void. It was on the other hand contended by the learned counsel for the Management that this contention is, now being raised

for the first time after remand and that as the same was not raised in the Writ Petition the workman is precluded from raising the same. Assuming that in view of the void, nature of the order reinstatement is to follow automatically, I would now proceed to consider the circumstances whether reinstatement could be ordered or compensation would be the proper remedy.

10. The contention of the Management was that before the claimant was sent to Aurangabad after some training at Bombay he was working as an Accountant which was post of confidence and that he was abused the trust reposed in him. It is alleged that without the sanction or permission of the Branch Manager he advanced amounts to the other staff members. The claimant when cross examined would however admit that without the sanction of the Branch Manager he advanced those amount only to the Peons. Though the workman would put it that he was not an Accountant, in one of his letters with regard to promotion i.e. in Ex. M 9, it is admitted by him that he was asked to handle the accounts independently; In the Memo Ex. M 1 and M 3 his designation is shown as an Accountant. From Ex. M 3 it is clear that the Branch Manager has issued a Memo on 21-10-1967 calling upon the claimant to explain as to why he paid the advances to all the staff members. Thus the payment of advances without the permission of the Branch Manager by the claimant in his capacity as an Accountant goes established. Under Ex. M 1 a Memo was issued to the claimant calling upon his explanation as to why the income tax returns are not filed by him. Ex. M 2 is the explanation given by the claimant. Under Ex. M 4 dated 23rd April, 1968 the claimant was called upon to give his explanation as to why premium amount of Rs. 820.00 received from Autofin Limited was not deposited in time. Ex. M 5 is a letter from the Divisional Manager dated 10th July 1968 calling upon the claimant as to why he proceeded on leave before obtaining prior permission for the same. These were the Memos given and explanations called before the claimant was posted to Aurangabad. I may incidentally refer that in the year 1967 though an additional increment was recommended by the Branch Manager M.W. 1, the Head Office has turned down the said recommendations. In that context the claimant addressed a few letters to the Divisional Manager. I need not advert to that correspondence for the purpose of the question now in issue. What was contended by the Management is though action could have been taken with regard to the above lapses on the part of the claimant yet it refrained from doing so and instead posted him at Aurangabad, whereafter due to the failure of the claimant to have good relations with Kailash Motors, the Company was exposed to the risk of losing a valuable customer or client. Though it is the contention of the workman that Kailash Motors took an unhelpful attitude towards him as he did not agree for certification of a false claim with regard to the damage to a tractor etc., it certainly emerges that the Divisional Manager of this Company had to tender an apology to the said Kailash Motors. It also emerges that the relation of this claimant with Kailash Motors were no way helpful to the Insurance Company. Ex. M 22 is a letter addressed by the Divisional Manager to the claimant wherein it is recited that the claimant instead of creating goodwill and procuring other business through the influence of Kailash Motors, he made a mess and spoiled the business relations with Kailash Motors. We are not now on the question whether the stand of the claimant was correct or that out of oblique motive the Kailash Motors took an antagonistic stand against the claimant. It can nevertheless be said that the Management of the Insurance Company was exposed to risk of losing a valuable client on account of the claimant not keeping good relations with them. Under Ex. M 31 dated 28th August 1968 the Divisional Manager of this Company had to tender an apology to Kailash Motors for the misconduct of the claimant. These circumstances are urged by the Management as leading to the loss of confidence. It was on the other hand contended by the workman that even according to M.W. 2 the posting of the claimant at Aurangabad was a working promotion to him and that even prior to that, the Divisional Manager has stated in Ex. M 23 that the integrity of the claimant was never doubted. It is true that in Ex. M 23 a letter addressed by the Divisional Manager to the claimant it stands noted that his (claimants) honesty was never doubted. But in the following sentences it is also recited that he did not like the manners of the claimant. It is further stated therein that if the claimant cannot pull on with the Manager Preetam Singh, the claimant was 'welcome to resign'. It is also the evidence

of M.W. 2 that though the claimant was sent to Aurangabad as his services as an Accountant were satisfactory, it is also his evidence that he was not satisfied with the claimant's general conduct and integrity. It was also urged by the learned counsel for the workman that the claimant was sent to Aurangabad after regular increments being given and admittedly it was a case of working promotion; if so the prior Memos of explanations called for cannot be now pressed into service to show that there was loss of confidence. In support of his contention that the earlier unsatisfactory conduct cannot be looked into, he relied upon the judgement of the Supreme Court reported in Service Law Reporter 1970 page 375. It was held therein that :

"The adverse confidential reports earlier to the crossing of the efficiency bar cannot be used in enquiry against the employee."

The further observations of this ruling are as follows :—

"It is unthinkable that if the authorities took any serious view of the charge of dishonesty and in efficiency contained in the confidential reports of 1941-42, they could have overlooked the same and recommended the case of the officer as one fit for crossing the efficiency bar in 1944."

Relying upon the above observations it was contended that the adverse memos issued to the claimant prior to his posting at Aurangabad have to be eschewed from consideration and that the Management cannot fall back upon them. Similarly the facts of the Supreme Court ruling reported in A.I.R. 1975 page 661 were relied upon to show that where increments are given or promotion is given, as appreciation of the hard working, the plea of the Management that the conduct of the workman prior to the said date led to the loss of confidence stands demolished by the very factum of granting increment or promotion. I may however note that the question of loss of confidence have to be decided on the facts of each case. It might be that even though the earlier conduct of the claimant was not very satisfactory, the fact that the Management went on giving him increments and also gave a working promotion to him by posting him at Aurangabad, would suggest that the Management was not serious in taking any action against him or at any rate the so called lapses were not such which made the Management to get rid of the employee. It is equally possible that as the claimant was not pulling on well with the Branch Manager, the Divisional Manager thought it fit to post him at Aurangabad and thus further the business prospects of the company. To my mind the Management did not treat the earlier conduct or the performance of the claimant as unsatisfactory. It might be that his general manners were not liked by the Divisional Manager but since his integrity was not doubted, his continuance in service was not only acquiesced but by posting him to Aurangabad the Company certainly wanted to press his services for its business prospects. Though it was the contention of the learned counsel for the workman that as to what happened to Kailash Motors at Aurangabad resulting in a strained relationship between the claimant and the said Motors the Management has not lead any evidence, I have already noted above that the Company stood exposed to the risk of losing a valuable client. It might be that the claimant was justified in his stand but in judging the question of loss of confidence it is the opinion formed by the employer about the suitability of the employee for the job assigned to him that is relevant even though erroneous. But if the opinion formed by it is bona fide, such an opinion is final. In the light of the correspondence referred to above wherein the Divisional Manager has to apologise to the Kailash Motors, it can only be said that the opinion formed by him about the claimants performance is a bona fide one, though when the whole matters comes up for judicial scrutiny the stand of the Management may not be justifiable. But it can be repeated that as to the suitability of the employee the judgement of the employer if bona fide, is not subject to review by industrial adjudication. This position has to be reached in the light of the judgement of the Supreme Court reported in AIR 1972 page 1343. The question now is whether on account of this incident can it be said that the claimant has forfeited his right to continue in service. It is true that the Management was faced or was exposed to the risk of losing a valuable client who was giving business turn over of Rs. 1,50,000.00 and odd per year. But when the Management has decided to put the claimant at Aurangabad, there itself it exercised his discretion wrongly. I do

not mean to make any observations about the judgment of the Management but it can yet be said that it was putting a square peg in a round whole. The choice of putting the claimant at Aurangabad does not appear to be a judicious one. But the point is whether the workman has forfeited his right to continue in service. It can incidentally be noted that the Management contends that subsequent to the dismissal the claimant admittedly handed over two articles contained in Ex. M 6 and M 7 which contain slanderous material about the working of this Insurance Company. W.W. 1 1 would admit having passed them to M. W. 1 to the Branch Manager. From this admission it cannot be said that W.W. 1 the claimant herein was the author of these articles. As noted above after remand W.W. 2 is examined to show that these two articles were written at his instance by his distant relative Mr. Andrews. It is true that there is nothing in these articles to show that Mr. Andrews was their author. Equally there is nothing to show that the evidence of W.W. 2 (Mr. K. D. Xavier an erstwhile Clerk in this every Branch and who is said to have been beaten by M.W. 1 as noted in one of the complaints made by the claimant to the Divisional Manager), is unreliable or unworthy of trust. That apart, the two articles relate to a period long after the termination order and for if any reason the claimant thought it fit, even in a revengful mood to hand over the articles containing slanderous matters regarding the working of the Insurance Company, that conduct of the claimant cannot be said to be detrimental to the interest of the Company. Thus noting the factors for and against reinstatement the one circumstance that stores against the claimant is his unsatisfactory performance at Aurangabad. As against it, his integrity was never doubted, though his general manners were felt to be not pleasing. It can as well be said that any lapses on his part prior to his being posted at Aurangabad were condoned by the Management. The claimant has put in nearly 10-1/2 years of service. He is now about to cross the age of 40. It can also be said that the prospects of his seeking a job with similar emoluments is remote. It can be noted that even though he was holding the post of an Accountant in a small establishment like Branch Office and also committed some breaches, those lapses were not viewed seriously by the Management. The underlying principle of industrial adjudication is to ensure security of tenure of a workman. Above all the normal rule on setting aside the termination order is that of reinstatement. Since it is not shown by the Management that one month's wages as required by Section 40 of the Shops and Establishments Act were paid along with the order of termination that termination order is void and this also entails reinstatement. But the conduct of the claimant at Aurangabad immediately preceding the order of termination was in no way helpful may positively prejudicial to the interest of the Company. Having regard to all the circumstances discussed above, I am led to order the reinstatement of the claimant but with only 1/3rd back wages.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 26th day of August, 1975.

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined for
Workmen :

W.W.1 M. Viswanath
W.W.2 K. D. Xavier

Witnesses Examined for
Respondent :

M.W.1 Preetam Singh
M.W. 2 J. B. Setalwad.

Documents Exhibited For Workmen :

Ex. W1 Letter dt. 1-5-68 from the Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Camp, Hyderabad addressed to M. Vishwanath.

Ex. W2 Letter dt. 28-5-68 of M. Vishwanath.

Ex. W3 Letter dt. 3-6-68 from the Divl. Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.

Ex. W4 Letter dt. 10-8-68 from M. Vishwanath addressed to Jagdishbhai.

Ex. W5 Letter dt. 10-8-68 from M. Vishwanath addressed to the Motor Claims Department, Divisional Office, Bombay.

Ex. W6 Letter dt. 12-8-68 of M. Vishwanath addressed to Srivyas.

Ex. W7 Letter dt. 17-8-68 addressed to Sri Vyas.

Ex. W8 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to M. Vishwanath.

Ex. W9 Letter dt. 2-9-68 of Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Sri M. Vishwanath.

Ex. W10 Certified copy of the order of the High Court in W.P. No. 2138 of 1969 dt. 5-12-1969.

Ex. W11 Letter dt. 11-7-67 of M. Vishwanath addressed to J.B. Setalwad, Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay.

Ex. W12 Letter dt. 15-8-63 of M. Vishwanath and copies to Preetam Singh.

Ex. W13 Agreement dt. 28-11-63 arrived at between Ruby General Insurance Company Limited, Bombay Office, Bombay and Its staff members effective for five years from 1-1-1963 to 31-12-1967.

Documents Exhibited for Respondent :

Ex. M1 Memo dt. 7-10-67 of Branch Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad addressed to M. Vishwanath.

Ex. M2 Reply of M. Vishwanath dt. 11-10-67 to Ex. M1 i.e. to the Branch Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Hyderabad.

Ex. M3 Memo dt. 21-10-67 of Branch Manager, addressed to M. Vishwanath.

Ex. M4 Memo dt. 23-4-68 of Branch Manager addressed to M. Vishwanath.

Ex. M5 Copy of the letter of Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay dt. 10-7-68 addressed to M. Vishwanath at Aurangabad

Ex. M6 Leader News Paper dt. 6-7-69 in which the Ruby General Insurance Company's affairs contains

Ex. M7 Leader News Paper dt. 10-7-69 in which it contains the Ruby General Insurance Company's affairs.

Ex. M8 Letter dt. 29-12-65 from M. Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay

Ex. M9 Letter dt. 23-5-67 of M. Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.

Ex. M10 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, addressed to Vishwanath.

Ex. M11 Letter dt. 10-7-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay to Vishwanath.

Ex. M12 Letter dt. 2-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Vishwanath.

Ex. M13 Letter dt. 29-6-67 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay to Vishwanath.

Ex. M14 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Sri S. C. Bafna Kailash Motors, Aurangabad.

Ex. M15 Letter dt. 6-9-68 of Vishwanath.

Ex. M16 Copy of the letter dt. 6-9-68 of Branch Manager, Hyderabad to Vishwanath.

Ex. M17 Letter dt. 16-8-67 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay addressed to Vishwanath.

Ex. M18 Letter dt. 6-9-67 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.

Ex. M19 Letter dt. 8-3-66 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.

Ex. M20 Letter dt. 22-3-1966 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad, Divisional Manager, Bombay.

Ex. M21 Letter dt. 28-3-1966 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, addressed to Vishwanath.

Ex. M22 Letter dt. 20-8-68 of J. B. Setalwad, Divisional Manager Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.

Ex. M23 Letter dt. 2-6-1967 of J. B. Setalwad, Divisional Manager, Ruby General Insurance Company Limited, Bombay addressed to Vishwanath.

Ex. M24 Letter dt. 12-8-1967 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad.

Ex. M25 Letter dt. 16-8-1967 of J. B. Setalwad addressed to Vishwanath.

Ex. M26 Letter dt. 6-9-1967 of Vishwanath addressed to J. B. Setalwad.

Ex. M27 Letter dt. 16-9-1967 of J. B. Setalwad to Vishwanath.

Ex. M28 Letter dt. 2-6-1967 of Setalwad to Preetam Singh.

Ex. M29 Letter dt. 10-8-1968 of S.C. Bafna, addressed to J. B. Setalwad.

Ex. M30 Letter dt. 12-8-1968 of S. Bafua, Kailash Motors, Aurangabad addressed to M/s. Ruby General Insurance Company Limited, Bombay.

Ex. M31 Letter dt. 20-8-1968 of J. P. Setalwad addressed to S. C. Bafna.

T. NARSINGH RAO, Presiding Officer
[No. F. 10/2/70-LRI]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

प्रावेश

नई विलो, 6 अगस्त, 1975

कांग्रेस 4217.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक धनु-सूची में विनियिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एम्सो गोवा (प्राइवेट) लिमिटेड मारगांगो (गोवा) और मैसर्स मेटको ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मारगांगो (गोवा) के प्रबन्धताल से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कम्बारों के बीच एक श्रौतोगिक विवाद विद्यमान है ;

प्रीत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए मिशनियल करना बांधमानीय समझती है ;

प्रतः, श्रूत श्रौतोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की जा धारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित श्रौतोगिक अधिकरण (संख्या 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्विवित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स एम्सो गोवा (प्राइवेट) लिमिटेड (गोवा) और मैसर्स मेटकों ब्रोर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (गोवा) की, श्री विठ्ठल आनन्द सावन्त, पर्यवेक्षक की सेवाएं 7 दिसम्बर, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[संख्या एल-26012/7/75-डी-4-बी०]

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1975

S.O. 4217.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Emco Goa (Private) Limited, Margao (Goa) and Messrs Metco Ores (Private) Limited, Margao (Goa) and their workman in respect of the matters specified in the Schedule here to annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefor, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No.2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Emco Goa (Private) Limited (Goa) and Messrs Metco Ores (Private) Limited (Goa) in terminating the services of Shri Vithal Anant Sawant, Supervisor with effect from the 6th December, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-26012/7/75—D—IV.B]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० आ० 4218.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखड़ अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स उड़ीसा मिनरल इंडस्ट्रीज कम्पनी के अधीन टेकेदार—मैसर्स माइन कन्स्ट्रक्शन कंसर्न, डाकघर शार्किल जिला केंद्रोंसार से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चांगनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपाधारा (i) के अन्तर्गत (अ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद की उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कॉर्पर लिमिटेड की इंडियन कॉर्पर काम्पलेक्स की मोसाबोनी माइन्स के प्रबंधतन्त्र की, श्री एम० सी० शोपाल, स्कोटक (ब्लास्टर) को 22-7-1974 से परव्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-29011/58/74-एल आर 4/डी-4बी०]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1975

S.O. 4218.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No.2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited in dismissing Shri M.C. Ghosal, Blaster with effect from 27-7-1974 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/58/74—LR-IV/D-IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का० आ० 4219.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखड़ अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स उड़ीसा मिनरल इंडस्ट्रीज कम्पनी के अधीन टेकेदार—मैसर्स माइन कन्स्ट्रक्शन कंसर्न, डाकघर शार्किल जिला केंद्रोंसार से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चांगनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपाधारा (i) के अन्तर्गत (अ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठसीन अधिकारी श्री बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स उड़ीसा मिनरल इंडस्ट्रीज कम्पनी के अधीन टेकेदार मैसर्स माइन कन्स्ट्रक्शन कंसर्न, डाकघर शार्किल, जिला केंद्रोंसार, की निम्नलिखित कार्रवाईयां न्यायोचित थीं?

(1) 19 फरवरी, 1975 से आत्माराम गोड़, घनिक की पदच्युति।

(2) ठाकुरानी खान, स्थित घपने स्थापन से मैसर्स बौलानी ब्रोर्स लिमिटेड की बौलानी स्टोर अयस्क खान स्थित घपने स्थापन में सर्वश्री रमेश मुण्डा, लखन गोप और मधुरा दास, खनिकों का 26 फरवरी, 1975 से स्थानान्तरण और बाद में 12 मार्च, 1975 से उनकी सेवायें की समाप्ति। यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[फाईल संख्या एल-26012/8/75-डी-4 (बी०)]

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4219.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs Modern Construction Concern, contractors under the Messrs Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the following actions of Messrs Modern Construction Concern, Contractors under Messrs Orissa Mineral Development Company, Post Office Barbil, District Keonjhar were justified?

- (1) Dismissal of Shri Atmaram Gond, Miner with effect from 19th February, 1975.
- (2) Transfer of Sarvashri Ramesh Munda, Lakan Gope, and Mathura Das, Miners with effect from 26th February, 1975 from their establishment at Thakurani Mines to their establishment at Bolani Iron Ore Mines of Messrs Bolani Ores Limited and subsequent termination of their services with effect from 12th March, 1975.

If not, to what relief are the workmen entitled?

[F. No. I.—26012/8/75—DIV(B)]

आदेश

का० प्रा० 4220.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल के भारत रायाना हरसा आयरन और माइन्स हासपेट के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहती है;

अतः, अब, आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10की उप-धारा (i) के छण्ड (घ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक आद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भागवत होंगे, जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

यह मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल की भारत रायाना हरसा आयरन और माइन्स, हासपेट के प्रबंधतन्त्र की, आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25व के उपबन्धों का अनुपालन किए बिना श्री श्री० बेनकमा चैटी की सेवायें समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-26012/9/75-डी-4-(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी, (विशेष)

ORDER

S.O. 4220.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G.S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet, in terminating the services of Shri V. Venkanna Chetty without complying with the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947, was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-26012/9/75-D-LV(B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

वर्ष दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

का० प्रा० 4221.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरल एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की जामादोबा कोलियरी, डाकघर जामादोबा, जिला धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आद्योगिक विवाद विद्यमान है।

ओर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहती है;

अतः, अब, आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (i) के छण्ड (घ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार आद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

यह मैसर्स टाटा आयरल एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की जामादोबा कोलियरी, डाकघर जामादोबा, जिला धनबाद के प्रबंधतन्त्र की, श्रीमती सरस्वतिया, राजगीर कामिन, टिकट संख्या 26440 को, 15 मार्च, 1975 से प्रधिविधित कारण सेवा निवृत्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष की हकदार है?

[संख्या एल-26012/125/75-डी-3-ए]

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1975

S.O. 4221.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Jamadoba Colliery of Messrs. Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, in superannuating Smt. Saraswati, Mason Kamin, Ticket No. 26440, from service with effect from the 15th March, 1975 is justified? If not, to what relief is the worker entitled?

[No. L-20012/125/75/D.IIIA.]

आदेश

का० आ० 4222—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग लिमिटेड की भाट्डी कोलियरी, डाकघर-मोहुदा, जिला धनबाद के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विचार मान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना चांगलीय समझती है।

प्रतः, यद्यु, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के अप्पण (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संभा० 2. धनबाद के न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोक लिमिटेड की भाट्डी कोलियरी, डाकघर मोहुदा, जिला धनबाद के प्रबंधतत्र का, श्री लाल बिहारी सिंह, रात्रि रक्षक को पदन्धन करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किसे तागेक से?

[संख्या एल-20012/158/74-पल-आर०-2/झी०]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विषेष)

ORDER

S.O. 4222.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad, are justified in dismissing from service Shri Lal Bihari Singh, Night Guard? If not, to what relief is the said workmen entitled and from what date?

[No. L-20012/158/74/LRII/D.IIIA]

L. H. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० आ० 4223—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आवारी बोर्ड, बरेली के प्रबंधतत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विचार मान है—

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना चांगलीय समझती है,

अतः, यद्यु, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1917 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के अप्पण (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री के० एन० श्रीवास्तव होंगे, जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा, और उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या आवारी बोर्ड, बरेली की, श्री लालता प्रसाद को सफाई निरीक्षक के बजाय सहायक सफाई निरीक्षक के रूप में बहाल करने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-13012 (1)/75-डी-2 बी]

New Delhi, the 14th August, 1975

ORDER

S.O. 4223.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Cantonment Board, Bareilly and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. N. Srivastava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Cantonment Board, Bareilly in reinstating Shri Lal Parshad as Assistant Sanitary Inspector instead of as Sanitary Inspector, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-13012(1)/75-D.IIB]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

का० आ० 4224—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में केन्द्रीय सोक नियन्त्रण विभाग में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विचार मान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना चांगलीय समझती है,

भ्रतः, अब, और्जोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की वर्ता 10 की उम्मीद, (1) के अंतर्गत (प) द्वारा प्रदत्त शर्कियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विवाद की उक्त अधिनियम की धारा 7A के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार और्जोगिक अधिकरण, दिल्ली की न्यायिनीयता के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मुख्य इंजीनियर नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रबन्धसंस्थान को, श्री लालजी राय, अकास्मिक कर्मकार (तत्काल) की सेवाएँ 3-9-74 से समाप्त करते की कार्यवाही व्यावेचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस प्रतीक का हक्कार है?

[संख्या एल-42012/15/75 डी०-२३०]

New Delhi, the 18th August, 1975

ORDER

S.O. 4224.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Public Works Department and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Public Work Department under the Engineer-in-Chief, New Delhi, in terminating the services of Shri Laljee Rai, a casual workman (Plumber) with effect from 3-9-1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-42012/15/75—D.HB]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

ग्रुहिणी

का० आ० 4225.—भारत के राजान, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii), तारीख 22 मार्च, 1975 के पृष्ठ 1217 पर प्रकाशित भारत सरकार, धर्म मंत्रालय की प्रधिसूचना की संख्या का० आ० 909, तारीख 11 मार्च, 1975 में—

“कर्मान्” शीर्षक के मात्रांत्र ; विनियोग विवादप्रस्त विषयों से संबंधित मध् (1) में, “1-12-74” के लिए “1-12-73” पक्षिण

[संख्या एल-42012(7)/75-डी०-२३० (धी)]

New Delhi, the 5th September, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 4225.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 909 dated the 11th March, 1975 published on pages 1217 and 1218 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd March, 1975—

Under the heading “Agreement”, in item (i) relating to specific matters in dispute, for “1-12-74” read “1-12-1973”.

[No. L-42012(7)/75-D.2(B)]

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 4226.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam and their workman, which was received by the Central Government on the 10th September, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A. LL.B., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 20 of 1975

BETWEEN

Workman of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam.

AND

The Management, Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam.

Appearance :

- (1) Sri A. Lakshmana Rao, Advocate for Workman.
- (2) None for Management.

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour through notification No. L-14012(2)/75-D. 2(B), dated 29th May, 1975 referred the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam and their workman under Sections 10(1)(d) and 7A of the I.D. Act for adjudication by the Tribunal on the following issue :

“Whether the action of the Management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Capital Dredging Project No. 2, Directorate General Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapatnam in retrenching Shri R. George, Sub-clerk (Stores), with effect from 9-3-75 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?”

2. The reference was registered as I.D. No. 20 of 1975 and Notices were issued to the workman and to the Management. The workman filed a claims statement, inter alia alleging that he was appointed as Sub-clerk by the respondent Management on 13-5-1974 at Rs. 200 per month. In July, 1974 the respondent asked the workman to act as a Supervisor in the Department of shore pipe-line without changing his designation and pay. The Management is said to have kept the workman for months together under a promise that it would confirm his promotion and increase his pay. Thus the workman trusting the management discharged the duties of a Supervisor, accepting the salary of a Sub-clerk. It is alleged that the management though coming from a Socialist Country has been exploiting the workmen. In many of the pay slips the designation of this workman is said to have not been shown but in the Duty Fitness Certificate the workman is said to have been shown as supervisor. In the month of January, 1975 the workers of this Company are said to have gone on strike and struck the work for about 33 days. During the said period the workman co-operated with the management and discharged his duties as a Supervisor. Though he did not join the strike the management entertained a baseless suspicion that the workman was supporting the workers on strike and thus the management issued

an ousting order dated 7-3-75. According to the management the reason for ousting him is said to be the want of vacancy. The allegation of the want of vacancy is characterised by the workman as false and incorrect. That post of a Supervisor is given to Shri A. Appa Rao who is a junior to the claimant herein. In the order of ousting it is not mentioned that the claimant was retrenched nor the retrenchment compensation was offered to the workman. It is contended that the order of ouster amounts to dismissal and the said order is said to be illegal and mala fide and against the principles of natural justice. It is urged that the management has exploited this workman for more than 8 months without changing his resignation and paying lesser wages for his services as a Supervisor. His dismissal order is said to be the outcome of suspicion by the management that this workman has been helping the workmen on strike. He thus prayed for his reinstatement with full back wages.

3. In the counter filed by the management, it is alleged that the appointment of the claimant was as a Sub-Clerk (Stores) with effect from 13-5-1974 on temporary basis in the scale of Rs. 200-8-280. It is alleged that his services were utilised as Sub-Clerk (Stores) in Shore Pipe Line from July, 1974. The claim of the claimant-workman that he was acting as a Supervisor in the Shore Pipe Line, is denied. It is further contended by the management that as the post of Sub-Clerk in stores has been abolished, the claimant was ousted from service by paying the following benefits, viz. one month's pay, 15 days pay as gratuity, bonus at 10 per cent for the year ending on 31-12-1974. It is further contended by the management that the claimant was only doing the job of a clerical nature and that he had no technical skill which is required for the post of a Supervisor. The post of Supervisor requires either Civil Engineering qualification or Licentiateship in Civil Engineering or experience of at least seven years in Road and Building Construction. The claimant is said to have had no such qualifications to be employed as a Supervisor. The designation of the claimant as a Supervisor shown in Duty Fitness Certificate is said to be the result of false representation to the Medical Unit. The designation entered therein is said to be the result of declaration made by the workman himself. It is thus contended that the self declaration is of no avail and does not bind the management. It is denied that the management suspected the bona fide of this workman during the period of strike by the other workmen. If it had been so it would have instituted a domestic enquiry. It is contended that the post of Supervisor of Shore Pipe Line is given to Mr. A. Appa Rao Reddy who held the necessary qualifications, which qualifications the claimant did not possess. It is contended that the claimant did not complete the qualifying service of one year yet the management gave him the benefits of gratuity, bonus and one month notice pay as stated earlier. In giving those benefits the management is said to have acted with magnanimity. It is also denied that the ousting order amounts to a dismissal. The ousting is said to have been ordered for want of vacancy and that the workman is not entitled to retrenchment compensation. It is also contended that the retrenchment compensation is to be paid to a workman who has completed one full year of service. It is thus denied that the order is violative of any principles of natural justice. The claim of the claimant is said to be vexatious and is intended to malign the management. The management has also withdrawn an alleged earlier offer to provide the workman with the job of Sub-Clerk in Stores Department in case of any vacancy arising therein. The claim of the workman is thus resisted.

4. In a rejoinder filed by the workman, the earlier pleas are reiterated. It is also contended that Mr. A. Appa Rao Reddy had no requisite qualifications but since during the strike period he arranged the supply of labour with the help of one contractor by name Prasad Rao, the management favoured him by appointing him as Supervisor even though he was a junior to the claimant herein. It is urged by the workman that he has completed his probation period without any blemish, and he has become a regular employee as per the Service Rules and Standing Orders of this Company. It is reiterated that from July onwards he was not a clerk but was performing the duties of a Supervisor till the date of his dismissal.

5. On receiving the counter on 21-7-1975 the case was posted for enquiry to 5-8-1975. Notices were directed to both the parties accordingly. On 5-8-1975 the workman was

present for enquiry but none was present for management in spite of service of notice of the date of enquiry. The enquiry was posted to 6-8-1975. On the said date also none was present for the management. As the workman came all the way from Visakhapatnam his evidence was recorded in the absence of the management. After recording his evidence the case was posted to 19-8-1975 for further enquiry, and a notice was again directed to the management intimating the stage of the proceedings and with the direction to it that it is at liberty to participate in the proceedings. That notice was also served on the management. But inspite of service the management was absent on 19-8-1975. The workman closed his evidence, and arguments were heard and the matter was reserved for award. After some time of the closing of the matter a representative of the management appeared. He was orally informed of the steps to be taken to enable him to reopen the matter. But inspite of advising him about the procedure to be followed he has not chosen to file any petition to reopen the matter. On the other hand a further counter statement dated 23rd August, 1975 is sent through post. In this additional counter the pleas raised in the counter are again reiterated. The further contention is that the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act is attracted to the facts of the case and therefore the suggestion is that the Tribunal has no jurisdiction to entertain this reference. It may be stated that there is no foundation for this contention as the workman is directly employed by the respondent-management and not through any contractor. This contention therefore fails.

6. I would now examine the evidence of the workman and decide whether he is entitled to any relief. The claimant in addition to examining himself as W.W. 1 in Oral evidence also relied upon Ex. W 1 to Ex. W 8 in documentary evidence. His version is that he was appointed on 13th May 1974 as Sub-Clerk in Stores but no appointment letter was immediately given to him. Ex. W 1 is the appointment letter showing his appointment with effect from 13th May, 1974. Significantly enough it does not contain the date of issue. As per the terms of appointment the probation was initially for a period of 3 months. Regardless of the fact whether he worked in the Stores as Sub-Clerk or in the Shore Pipe Line either as Sub-Clerk or otherwise, his total period of service exceeded more than nine months. It is not the case of the management that his probation was extended from time to time. While the management will put in that from July, 1974 the claimant worked as a Sub-Clerk in the Shore Pipe Line, the workman would allege that his services were taken as a Supervisor in that Department. If I may say to the question whether the claimant has worked as a Supervisor or he had no qualification to hold that post or whether any junior by name A. Appa Rao Reddy was appointed to that post are not questions really now in issue. According to the management the services of the workman were terminated because the post of a Sub-Clerk is no more available. Though the workman would put it that he has been working as a Supervisor, admittedly there is no appointment letter appointing him to the post of a Supervisor. It is true that in the Medical Fitness Certificate Ex. W.W. 4 issued by the Medical Officer the designation of the workman is shown as Supervisor of the Shore Pipe Line. It is not conclusive to say that the workman was working at that time as Supervisor in the Shore Pipe Line Department. In the pay slips Ex. W. 8 series all that is found noted is that the workman is in the Shore Pipe Line Department, his designation is not shown therein. The workman as W.W. 1 put it that his designation was purposefully omitted in the said pay slips. Be that whatever it may, in the absence of his regular appointment as Supervisor in the Shore Pipe Line Section, it does not appear that any relief can be granted to him treating him as a Supervisor in that section. It would certainly emerge from the admission of the management that the claimant was later working in the Stores of the Shore Pipe Line Section. The question is whether the original post of Sub-Clerk (Stores) is abolished which necessitated retrenchment of this workman. The evidence of W.W.1 is to the following effect :

7. "It is not true to say that the post of Sub-Clerk in which I was initially appointed is abolished and thus any retrenchment was necessitated. In fact Mr. Lakshman Rao is working in the same post of a Sub-Clerk but he is now designated as a helper.

8. At one stage he has deposed.

"Mr. Vijayan Pillai, Laxman Rao and Prakash Rao joined as Sub-Clerks subsequent to my appointment. Mr. Raju joined the service of the Company one and half months after I joined. All the above four persons who are juniors to me are still working in the company in the Stores Division. But the management deliberately divided that section in November, 1974 into stores Section and Workshop. In fact the workshop is a part and parcel of the Stores."

9. From the above evidence it is clear that the juniors to the claimant herein are still continuing in service and that Mr. Laxman Rao is working in the same post which was held by the claimant herein. But that post is designated as a Helper. I have already noted above that it is not the case of the management that the services of the claimant during the probation period were in any way unsatisfactory or that his period of probation has been extended. By mere changing the designation of a post of Store Keeper to that of a Helper or by dividing the section into two could not have resulted in the abolition of a post, when it is the version of the claimant W.W.I that the same post continues under a redesignation of a Helper and that a junior to him is still continuing in that post. Though I have held that for the purpose of this dispute, it is not necessary to go into the question whether the claimant was really working as a Supervisor or not, suffice it to say that the termination of his services on the ground of abolition of a Sub-Clerk in the Stores remains unjustified. As the said post continues and is held by a junior, and though the said post is redesignated as Helper but is substantially the same, the ground for ousting the claimant cannot be said to be justified or reasonable. The one and the only reason given by the management for ousting the claimant is the want of vacancy. In the circumstances and in the light of the evidence it does not appear to be true. Hence the ousting of the claimant-workman in the light of the above evidence is held to be unjustified. He is thus entitled to be reinstated with full back wages. The reinstatement of the workman with full back wages is therefore ordered.

10. Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 28th day of August, 1975.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined

For Workmen :

Witnesses Examined For Management :

W.W. 1 Shri R. George

NIL

Documents Exhibited for Workmen :

- Ex. W 1.—Appointment Letter of Shri R. George as Sub-Clerk (Stores).
- Ex. W 2.—Pay Scales of monthly paid employees and employees drawing above Rs. 500/- p.m. (Appendix I).
- Ex. W 3.—Letter of the Head of the Department dated 10-2-1975 addressed to Shri R. George (in Ugo-slavian Language).
- Ex. W 4.—Duty Fitness Certificate of Shri R. George issued by the Medical Officer, Ivan Milutinovic Pim on 3-3-1975.
- Ex. W 5.—Prescription of the Medical Officer Ivan Milutinovic Pim in respect of George's health.
- Ex. W 6.—Ousting Order of Shri R. George, temporary Sub-Clerk Shore Pipe Line w.e.f. 8-3-1975.
- Ex. W 7.—Standing Orders of M/s. Ivan Milutinovic Pim-1973.
- Ex. W 8.—Pay Envelop of Shri George for the month of August, 1974 for Rs. 191.15.

- Ex. W 8(a).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of September, 1974 for Rs. 199 only.
- Ex. W 8(b).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of October, 1974 for Rs. 257 only.
- Ex. W 8(c).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of May, 1974 for Rs. 208.95.
- I.x. W 8(d).—Pay Envelop (D.A.) of Shri R. George for Rs. 260 only.
- Ex. W 8(e).—Pay Envelop of Shri R. George for the month of November, for Rs. 307 only.
- Ex. W 8(f).—Pay Envelop for Shri R. George for the month of December, for Rs. 354 only.

Documents Exhibited for Management :

NIL

T. NARSINGH RAO,, Presiding Officer

[No. L 42012(2) /75-D-2(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer, (Spl.)

प्रादेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

का. ० धा. ० ४२२७.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपायोग प्रान्त सूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना आवश्यक समझती है;

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त प्रक्रियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

प्रान्तसूची

इस कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध प्रबन्धालंक का, श्री नमाजु-हीन, इलेक्ट्रिक प्लाट लाइट ब्रेटेंडेन्ट, अपर रीसोर्ज रिसर्च स्टेशन काल्टा की उसके अपने कर्मचारों के प्रतिरिक्षण आउट बोर्ड मोटर हंजनों और स्टेशन बैन की सर्विसेंग और भरमत करने और काल्टा स्टेशन स्थित पम्प घलाने के लिए विशेष बेतन देने से इकार करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस प्रान्तसूची का हकदार है?

[संख्या एल 32012/14/75 डी-II-ए]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4227.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in refusing special pay to Shri Namajuddin, Electric Plant Light Attendant, Upper Reaches Research Station, Falta for carrying out servicing and repairs of outboard motors engines and station Van and operation of pump at Falta Station in addition to his own duties ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-32012/14/75-D. IV(A)]

आदेश

का० आ० 4228—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन-न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहीय समझती है ;

अतः अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्धोगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

स्था कलकत्ता पत्तन-न्यास के मुख्य यान्त्रिक इंजीनियर के अधीन कार्य करने वाले विद्युत कर्मचारीवृन्द की निम्नलिखित मांगें न्यायोद्धित हैं ? यदि हाँ, तो संबंधित कर्मकार किया अनुसूचित के हकदार हैं ?

मांगें

- (1) प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक पारी में 6 घण्टों के स्थान पर 9 घण्टे कार्य करने के लिए एक धृष्टि के अतिकालिक भत्ते की मंजूरी ।
- (2) ऊंचाई में तार बांधने तथा जलयान गैर्में के लिए बाहर काम करने हेतु परिवहन की आवश्यकता ।
- (3) केवल धृष्टि से अर्धकुशल श्रमिकों के रूप में प्रोत्स्थिति किए जाने की वर्तमान स्थिति के विपरीत विद्युत स्थापन दौर्चे में और अधिक अर्धकुशल श्रमिकों के पार्श्व वा सूजन ।

[पंक्ति एल-32011/16/74-पी०डी०/सी०एम०टी०/डी-4(ए)]

ORDER

S.O. 4228.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following demands of the Electrical Staff working under the Chief Mechanical Engineer of the Calcutta Port Trust are justified ? If so, to what relief are the concerned workmen entitled ?

DEMANDS

- (i) Granting of one hour overtime to each of the workmen for performing 9 hours of duty in each shift instead of 8 hours.
- (ii) Arrangements of transport be made for overhead wiring and vessels gangs for working outside.
- (iii) Creation of more semi-skilled labour posts in electrical set up as against the present position of having only a handful of semi-skilled labour posts and unskilled labour being promoted directly to skilled labour.

[No. L-32011/16/74-PD/CMT/D-IV(A)]

प्रावेश

नई विल्ली, 19 अगस्त, 1975

का० आ०—4228 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची 2 में विनिविष्ट विषयों के बारे में इससे उपावद्ध अनुसूची 1 में विनिविष्ट मोर्मुगाबो बन्दरगाह (गोवा) में 12 नौमरकों के प्रबन्धतांत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहीय समझती है ;

अतः अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्धोगिक अधिकरण संस्था 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची-1

1. मैसर्स एजेंसियां कार्मिकल मैरिटिमा, वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
2. मैसर्स एजेंसियां अल्ट्रामैरिटा प्राइवेट लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
3. मैसर्स चौगुल ब्रदर्स, मोर्मुगाबो बन्दरगाह (गोवा) ।
4. मैसर्स द्वामोदर मंगलजी एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
5. मैसर्स एलेसबाप्रों पेरोरा एण्ड संज, वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
6. मैसर्स माचादो एण्ड सन्टे, एजेंट्स एण्ड स्टीविडोअर्स प्रा० लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
7. मैसर्स गोसालिया गिपिंग प्रा० लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
8. मैसर्स लिमा लिटाप्रो एण्ड कॉ० मोर्मुगाबो बन्दरगाह (गोवा) ।
9. मैसर्स मोर्मुगाबो नावोरोरा लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
10. मैसर्स राजाराम बी० रेडिज, वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
11. मैसर्स बी० एम० सालगामोकर एण्ड ब्रदर्स, प्रा० लिं., वास्को-डी-गामा (गोवा) ।
12. मैसर्स बी० एम० डेम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मोर्मुगाबो बन्दरगाह (गोवा) ।

प्रमुखांक-2

(क) क्या प्रमुखांक-1 में विनिश्चित सौर्योदात्रे बम्बरगाह (गोवा) के नीमरको की, श्री राजाराम कालुराम औसार, प्रस्थायी गेंग अमिन (जिस्ट्रीकरण सं. सी. आर. डब्लू-17) को 7 अक्टूबर 1974 से नियाजन देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोंचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कमेकार किस भनुतोष का हकदार है ।

[संख्या एन-36012 (2)/75-डी-4 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1975

S.O. 4229.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of 12 Stevedores at Mormugoa Harbour (Goa) specified in the Schedule I annexed hereto and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule II hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

1. Messrs Agencia Commercial Maritima, Vasco-da-Gama (Goa).
2. Messrs Agencia Ultramarina Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
3. Messrs Chowgule Brothers, Mormugoa Harbour (Goa).
4. Messrs Damodar Mangalji and Company (Private) Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
5. Messrs Elcsbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama (Goa).
6. Messrs Machado and Sons, Agents and Stevedores Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
7. Messrs Gosalia Shipping Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
8. Messrs Lima Leitao and Company, Mormugoa Harbour (Goa).
9. Messrs Mormugoa Navegadora Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
10. Messrs Rajaram V. Redij, Vasco-da-Gama (Goa).
11. Messrs V. M. Salgaocar and Brothers Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
12. Messrs V. S. Dempo and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa).

SCHEDULE II

- (a) Whether the action of the Stevedores of Mormugoa Harbour (Goa) specified in Schedule I in refusing employment to Shri Rajaram Kaluram Jaiswar, Temporary Gang Worker (Registration No. C.R.W.-17) with effect from the 7th October, 1974 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-36012(2)/75-D-IV(A)]

New Delhi, the 11th September, 1975

S.O.4230.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to (i) Messrs Armen George and Company (Private) Limited, (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau, (iii) Messrs G. and K. Shipping (Private) Limited, and (iv) Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

SHRI E. K. MOIDU ... Presiding Officer.

Reference No. 20 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to :

- (i) Messrs Armen George and Company (Private) Limited.
- (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau.
- (iii) Messrs G and K Shipping (Private) Limited, and
- (iv) Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri B. N. Ash, Advocate.

On behalf of Workmen.—Shri Bacha Prasad, General Secretary, Calcutta Dock Workers' Union.

State : West Bengal

Industry : Port & Dock

AWARD

By Order No. L-32012/18/74-P&D/CMT/DIV(A) dated 7th March, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand for bonus for the year 1973-74 in respect of the workmen employed under Messrs Armen George and Company (Private) Limited, Messrs Calcutta Shipping Bureau, Messrs G and K Shipping (Private) Limited and Messrs Commercial Clearing Agency (Private) Limited, is justified ? If so, to what rate are they entitled ?"

2. Both the management as well as the union representing the workmen filed their written statements raising various contentions as regard the bonus payable to the workmen for the year 1973-74 by the specified companies mentioned in the Schedule to the Reference.

3. The case was posted to 17-9-1975 for settlement of the dispute between the parties. But, today the parties appeared and filed a settlement of the dispute. So, the date of hearing was advanced to this date and the reference is disposed of.

4. On consideration of the relevant clauses of the settlement mentioned as Annexure A to the petition, I am satisfied that the settlement is in the interest of both the employers and employees and that it is just and proper that the settlement be recorded.

5. In the result an award is passed in terms of the settlement. The terms of settlement together with the Annexure A will form part of the award.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Dated, Calcutta,

The 2nd September, 1975.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, CALCUTTA**
Reference No. 20 of 1975
In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Employers in relation to the Management of

- (i) Messrs Armen George & Co. (Pvt.) Ltd., 35, Ezra Street, Calcutta-1.
- (ii) Messrs Calcutta Shipping Bureau, 11/1, DaCree Lane, Calcutta, and their handling workers represented by Calcutta Dock Workers' Union (HMS), 27-B, Circular Garden Reach Road, Kidderpore, Calcutta-23 on Bilateral Level on 1-9-1975.
- (iii) Messrs G & K Shipping Private Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.
- (iv) Messrs Commercial Agencies Pvt. Ltd., 12-A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

AND

Their workmen, represented by Calcutta Dock Workers' Union, 27B, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23.

The humble joint petition, on behalf of the parties above-named.

Most respectfully SHEWETH :

1. That the workmen, who are employed by and are on the pay-roll of the four above-named Companies, have been paid their Bonus for the year 1973-74 and they have no claim whatsoever outstanding in that behalf.

2. That the labourers hitherto employed on MMTC's work, (Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd.) by the above-named four Companies, through Labour Contractors, are members of Calcutta Dock Workers' Union, and are represented by the Union, and the claim for Bonus for the year 1973-74, as in the Issue in the instant Reference is confined to the said labourers.

3. That the petitioners had prayed for and obtained an adjournment of the hearing fixed on 1-9-75 to enable them to amicably settle the dispute out of the Tribunal. The petitioners accordingly met at a bipartite level at the Office of the first above-named Company on 1-9-75 and arrived at a Bipartite Settlement, whereby the demands, as made in this Union's Charter of Demands, dated 28th August 1975, have been amicably settled. A copy of the said Bipartite Settlement, dated 1-9-75, is annexed hereto, and is marked Annexure "A".

4. That in terms of Clauses 9 and 10 of the aforesaid Bipartite Settlement, dated 1-9-75, *Inter alia*, (i) this Union agreed to withdraw the claims for Bonus for the year 1973-74, pending before this Hon'ble Tribunal, under Reference No. 20 of 1975, and (ii) the parties agreed to jointly approach this Hon'ble Tribunal, for an Award of "Amicable Settlement".

The petitioners humbly pray that your Lordship would be graciously pleased to dispose of the instant Reference, on the basis that the demand for Bonus for the year 1973-74 stands withdrawn by the Union, and make an Award accordingly.

And, for this act of kindness, as in duty bound, the petitioners shall ever pray.

2-9-1975.

for and on behalf of
Calcutta Dock Workers Union
Sd/- Illegible,
General Secretary.

ANNEXURE "A"

SETTLEMENT IN FORM H (UNDER RULE 58)

Memorandum of settlement under section 18(1) OD Industrial Disputes Act 1947 between (1) Armen George & Co. (Pvt) Ltd., 35, Ezra Street, Calcutta-1, (2) Commercial Agencies Pvt. Ltd., 12-A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, (3) G & K Shipping Private Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 and (4) Calcutta Shipping Bureau, 11/1, DaCree Lane, Calcutta, and their handling workers represented by Calcutta Dock Workers' Union (HMS), 27-B, Circular Garden Reach Road, Kidderpore, Calcutta-23 on Bilateral Level on 1-9-1975.

PARTIES PRESENT

- (1) Representing the Handling Agents.—(1) Shri S. B. Singh, Director, Armen George & Co. (P) Ltd.
- (2) Shri H. P. Rudra, Director, Commercial Clearing Agencies Pvt. Ltd., (3) Shri S. K. Chatterjee, Director, G & K Shipping Pvt. Ltd. (4) Shri Minlr Mukherjee, Partner, Calcutta Shipping Bureau.
- (2) Representing the workmen.—Shri Bacha Prasad, General Secretary, Calcutta Dock Workers Union.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The General Secretary, Calcutta Dock Workers Union (HMS) vide his letter No. CDWU/495 dated 28th August, 1975 had submitted a charter of demands on behalf of the handling workers engaged in Docks and Godowns to the four Handling Agents. The demands were (1) Enhancement of daily rates, (2) Double wages when booked on Port Working Holidays, (3) Grant of Port Closed Holidays and (4) Bonus for the year 1974-75.

The labourers hitherto engaged by the above-named Handling Agents, on MINERALS & METAL TRADING CORPORATION OF INDIA (abbreviated "MMTC") of 8, India Exchange Place, Calcutta (a Government of India Undertaking)'s work, used to be so engaged through Labour Contractors, who used to be paid charges on a tonnage basis by the Handling Agents, and the Labour Contractors paid the labourers employed by them at mutually agreed daily rates.

The existing system of engagement of labour on MMTC work, through Labour Contractors, being no longer permissible, the labour force available for the aforesaid work, has decided on the elimination of the intermediaries, and on direct employment. Accordingly, the labour force has chalked out a plan for formation of Managing Committees from amongst the labourers themselves.

The parties met on 1-9-1975 at the office of Armen George & Company (Private) Limited at 35, Ezra Street, Calcutta-1 and after prolonged discussion the parties came to an amicable settlement on the following terms and condition.

TERMS :

It is agreed by and between the parties.

1. That the labourers will constitute two separate Pools, one for the Docks and the other for Godowns, respectively called the MMTC DOCK WORKERS POOL and the MMTC GODOWN WORKERS POOL, hereinafter referred to as "D. W. POOL" and "G. W. POOL".

2. That the D. W. POOL will have a strength of 100 labourers and the G. W. POOL will have a strength of 80 labourers.
3. That the two above-mentioned Pools will be run by two separate Managing Committees. The Managing Committee for the D. W. POOL will at present be formed with the following persons from among the labour force :
 1. Sri Ram Ashish Tewari.
 2. Sri Narasingh Murti.
 3. Md. Taiyab Hossain.
 4. Abul Hossain
 5. Md. Yakub.
 6. Amirullah.

The Managing Committee for the C. W. POOL will at present be formed with the following persons, from among the labour force :

1. Md. Jan.
2. Md. Anwar II.
3. Monirul Haque.
4. Rahamatullah.
5. Md. Kashim.

4. That the members of the two Managing Committees, shall be responsible for the engagement of labourers belonging to the Pool managed by the Managing Committee concerned. Such members shall be responsible for—

- (i) taking work orders from the Handling Agents;
- (ii) booking of labourers according to the requirements of the Handling Agents;
- (iii) raising bills on the Handling Agents and receiving payment from the Handling Agents.

Payments will be made by the Handling Agents (against bills submitted) to any two members of the Managing Committee in question, duly authorised in that behalf by the Calcutta Dock Workers' Union, which shall have power to regulate the functioning of the Managing Committees and to supervise their work.

5. The labourers will be paid their charges, by the Handling Agents, through the Managing Committees, and the charges will be collected, on behalf of the Managing Committees, by two of their respective members, authorised in this behalf. The distribution of the charges among the labourers shall be the responsibility of the Managing Committees. After having made payment of any bill raised by the D. W. POOL or by the G. W. POOL, as the case may be, the Handling Agents shall have no liability whatsoever, for fair and equitable distribution among the labourers.

6. The charges payable to the labourers will be as follows :—

(1) For loading	... Rs. 2.25 paise per tonne.
(2) For unloading & stocking	... Rs. 2.25 paise per tonne.
(3) For Weighment & stacking	... Rs. 2.25 paise per tonne.
(4) For removal & re-stacking	... Rs. 2.25 paise per tonne.
(5) Casual Labour	... Rs. 10/- per day of 8 hours

The above rates are deemed to include 25 paise per tonne in lieu of Bonus. As regards Casual Labour, the daily rate is nett.

7. That the labourers engaged shall under no circumstances, claim and/or be entitled to any Bonus, or any Compensation, or any Notice or any payment in lieu of Notice. They shall also not be entitled to any benefits now enjoyed or as may hereafter be enjoyed by the Handling Agents' own workmen/employees on their respective pay rolls.

8. That any labourer, sustaining any personal injury, in course of his work, will be entitled to medical treatment, at the cost of the Handling Agents concerned, under whom he may be serving at the time. He will also be entitled to an allowance of Rs. 2.50 paise per day for the number of days, he is unable to work, due to the injury. Payment will be made to the Managing Committee concerned.

9. Since as a gesture of goodwill the Handling Agents have agreed to give 25 Paise per tonne in lieu of Bonus from 1-4-1975, the Union agreed to withdraw the claim for Bonus for the year 1974-75. In view of amicable settlement on the demands placed by the Union, the Union agreed to withdraw the claims of Bonus for the year 1973-74, which is pending before the Central Government Industrial Tribunal under Reference No. 20 of 1975.

10. For this purpose the Handling Agents and the Union will jointly approach the learned Tribunal to give award of "Amicable Settlement".

11. This Settlement shall have retrospective effect from 1-4-1975, and shall remain in force and be binding on the parties hereto up to and inclusive of 31st March, 1977.

For the Union

For and on behalf of

CALCUTTA WORKERS UNION

Sd/- B. Prasad

General Secretary

For the Handling Agents

ARMFN GEORGE & CO. PRIVATE LTD.

Sd/- S. B. Singh

Director

COMMERCIAL CLEARING AGENCIES PRIVATE LTD

Sd/- H. P. Rudra

Director

WITNESS :

(1) Md. Taiyab Hussain For G & K Shipping Pvt. Ltd.,
Sd/- M. Taiyab. Sd/- S. K. Chatterjee

(2) Amirullah Director, Calcutta Shipping Bureau
Sd/- Amirullah

(3) Md. Jan Sd/- M. K. Mukherjee
Sd/- Md. Jan Partner.

(4) Manirul Haque
Sd/- Manirul Haque.

(5) Md. Kashim
Sd/- Md. Kashim.

Dated 1st September, 1975.

[No. L-32012/18/74-P&D/CMT/D-IV-(A)]

NAND LAL, Section Officer.

नई दिल्ली 3 सितम्बर, 1975

का० अ।-423।—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसरै इन्डियन ग्राटोरेशन कम्पनी, वी० बिकास एस्टेट, आर्य रोड के सामने, गोरे गांव पूर्व मुम्बई, जिसमें श्री निवास बिल्डिंग 333, मरवार बल्लभ भाई पटेल रोड, मुम्बई-4, स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से मन्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमत्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रीर कुट्टम पैण्टन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

श्रम. ग्रन्थ, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रधिनियम का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपलब्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एम० 35018 (4) 75-प० एफ० II]

आर० पी० नरुला, ग्राम पंचायत

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4231.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Electric Automation Company, V. Vikas Estate off Aarey Road, Goregaon East, Bombay, including its branch at Shree Niwas Buildings, 333, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S-35018(4)/75-PF. II]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई विली, 5 सितम्बर, 1975

का० आ० 4223.—हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अन्त (घ) के अनुसरण में श्री पी० माट्टू, पंचायत, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम और रोजगार विभाग को, श्री नालचन्द्र प्रार्थी के स्थान पर कर्मचारी बीमा राज्य निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया है;

ग्रन्थ, ग्रन्थ, कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की प्रधिसूचना मंथ्या का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, प्रथमतः—

उक्त प्रधिसूचना में “(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के अन्त (घ) के प्रधीन नामनिर्दिष्ट)” के शीर्षक नीचे मढ़ 11 के सामने वर्तमान प्रविधित के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधित रखी जायेगी, प्रथमतः—

“श्री पी० के० माट्टू,
पंचायत,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
शिमला।”

[फाईल संख्या य०-16012/8/75-एच०आई०]

New Delhi, the 5th September, 1975

S.O. 4232.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh, has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P. K. Mattoo, Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Labour and Employment Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in the place of Shri Lal Chand Prarthi;

78 GI/75—9.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading “(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)”, against item 11A, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri P. K. Mattoo,

Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Labour and Employment Department,
Simla.”

[File No. U-16012/8/75-HI]

का० आ० 4233.—आनंद प्रदेश राज्य सरकार ने, कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अन्त (घ) के अनुसरण में, श्री एम० आर० पाई, पंचायत, आनंद प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, आवास और नगरपालिका प्रशासन विभाग को श्री आर० विठ्ठल राव के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित किया है,

ग्रन्थ, ग्रन्थ, कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की प्रधिसूचना संख्या का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, प्रथमतः—

उक्त प्रधिसूचना में, “(धारा 4 के अन्त (घ) के प्रधीन राज्य नाम निर्देशित)” शीर्षक के प्रधीन भव्य 7 के सामने वर्तमान प्रविधित के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधित रखी जायेगी, प्रथमतः—

“श्री एम० आर० पाई०,

पंचायत, आनंद प्रदेश सरकार,

स्वास्थ्य, आवास और नगरपालिका प्रशासन विभाग,
हैदराबाद।”

[फाईल संख्या य०-16012(12)/75-एच०आई०]

S.O. 4233.—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri M. R. Pai, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Health, Housing and Municipal Administration Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in the place of Shri R. Vithal Rao;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading “(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)”, against item 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri M. R. Pai,

Secretary to the Government of Andhra Pradesh,
Health, Housing and Municipal Administration
Department, Hyderabad.”

[F. No. U-16012(12)/75-HI]

नई विली, ९ सितम्बर, १९७५

का० आ० ४२३४.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४) की धारा १ की उपधारा (३) द्वारा प्रवृत्त गणितों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार २८ सितम्बर, १९७५ को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय ४ (धारा ४४ और ४५ के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय ५ और ६ की धारा ७८ की उपधारा (१) और धारा ७७, ७८, ७९ और ८१ के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपरान्ध कर्तिक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होगे, अर्थात्:—

क्षेत्र	होबली	तालुक	जिला
महादेवपुरा	कृष्णराजापुरा	बगलौर	बगलौर
द्वीर द्याव नद्या		दक्षिण	
गोद			

[एम०-३८०१३/११/७३-एच० आई०]

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4234.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th September, 1975 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely:—

Area	Hobli	Taluk	District
Mahadevapura and Dyavasandra Village	Krishnarajapura	Bangalore South.	Bangalore

[No. S-38013/11/73-HI]

का० आ० ४२३५—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४) की धारा १ की उपधारा (३) द्वारा प्रवृत्त गणितों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार २८ सितम्बर, १९७५ को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय ४ (धारा ४४ और ४५ के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय ५ और ६ की धारा ७८ की उपधारा (१) और धारा ७७, ७८, ७९ और ८१ के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपरान्ध पाल्घ प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होगे, अर्थात्:—

विभाषापट्टनम जिला में गोपालापट्टनम, वेपाग्नदा और बैंकटापुरम के राजस्व प्रामो से बना और निम्नलिखित द्वारा परिचय देव।—

उत्तर (१) लक्ष्मी पुरम

(२) कृष्णराजापुरम

(३) पुरुशोपालपुरम

पूर्व (१) ग्रामी विवरम

(२) बुचितगंगुपालेम

दक्षिण (१) पुलाम्बोट्टा पालेम

(२) मिण्डी

(३) मुलागादा

पश्चिम (१) माराशा

(२) पोगालापालेम

(३) बीमानापल्ली।

[एम०-३८०१३/१२/७४-एच० आई०]

S.O. 4235.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th September, 1975, as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

The area comprising the revenue villages of Gopalapatnam, Vepagunta and Venkatapuram in Visakhapatnam District and bounded by:—

North	(1) Laxmipuram (2) Krishnarayapuram (3) Purushothapuram
East	(1) Adivivaram (2) Butchirajupalem
South	(1) Pulambotla Palem (2) Mundu (3) Mulagada
West	(1) Narava (2) Porlapalem (3) Cheemalapalli

[S-38013/12/74-HI].

नई विली, १० सितम्बर, १९७५

का० आ० ४२३६—यह, विहार राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४) की धारा ४ के छठ (ष) के अनुसरण में, श्री राम उपदेश मिह के स्थान पर श्री आई० सी० कुमार, सचिव, विहार सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, को कर्मचारी राज्य बीमा नियम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिश्चित किया है;

अतः, श्री, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४) की धारा १ के अनुसरण में, भारत सरकार के भूत्यूर्ध श्रम, रोजगार और मुनर्बास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० २७६३, तारीख २७ मई, १९७१ में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, “(राज्य सरकारों द्वारा धारा ४ के छठ (ष) के प्रधीन नामनिधिष्ट)” शीर्षक के नीचे मद ९ के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

“श्री आई० सी० कुमार,
सचिव, विहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना।”

[फाइल संख्या य०-१६०१२/११/७५-एच० आई०]

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4236.—Whereas the State Government of Bihar has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri I. C. Kuntar, Secretary to the Government of Bihar, Depart

ment of Labour and Employment to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Ram Updesh Singh ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 7th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 9, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri I. C. Kumar,
Secretary to the Government of Bihar,
Labour and Employment Department,
Patna".

[F. No. U-16012/11/75-HI]

का० आ० 4237.—यतः हरियाणा राज्य सरकार ने, कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (प) के अनुसरण में, कुमारी एम० सेठ के स्थान पर श्री पी० पी० केशीहन आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, अम और रोजगार विभाग, अण्डीगढ़ को, कर्मचारी राज्य बीमा नियम में उम राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनियुक्त किया है;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व अम और पुनर्वाय मंत्रालय (अम और रोजगार विभाग की अधिकृता का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित मंशोंप्रति करती है, पर्यात—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 4 के खण्ड (प) के प्रधीन राज्य गवर्नरों द्वारा नामनियुक्त" शीर्षक के अन्तर्गत, मद 11 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, पर्यात—

"श्री पी० पी० केशीहन,
आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार,
अम और रोजगार विभाग,
अण्डीगढ़"।

[मंज्या य०-16012(13)/75 एव०पार्ट]

8.O. 4237.—Whereas the State Government of Haryana has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P.P. Caprihan Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Miss M. Seth ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. P. Caprihan,
Commissioner and Secretary to Government of Haryana,

Labour and Employment Department,
Chandigarh".

[No. U-16012(13)/75-HI]

का० आ० 4238.—केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के डाक-तार बोर्ड, संचार मंत्रालय के मरकारी तारभण्डा, मुम्हई के कर्मचारियों को अन्य प्रकार से बैसी ही प्रमुखिया प्राप्त हैं, जिनकी कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रधीन अवस्था की गई है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3195 तारीख 25 नवम्बर, 1974 के प्रत्यक्षमें केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा नियम से परामर्श करने के पश्चात, उपर वर्णित कारबाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 15 जनवरी, 1975 से 14 जनवरी, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात्—

(1) उक्त कारबाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके द्वारान यह कारबाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के प्रधीन था, (जिसे इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्रक्षेप में और ऐसी विविषियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम (साधारण) विनियम, 1950 के प्रधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थीं।

(2) नियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 उपधारा (1) के प्रधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या नियम का कोई अन्य पवधारी जो इस नियम प्राधिकृत किया गया हो—

(1) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के प्रधीन थीं जो इसी विवरणी में दी गई विविषियों को मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अधिनियित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाप्रक्रिय रजिस्टर और अधिकृत एवं गए थे ; या

(3) यह अधिनियित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकी और अस्तु के रूप में दिए जाने आये उन फायदों को पाने के प्रबंध भी हक्कदार हैं जिनके प्रतिक्रस्त-स्वरूप इस अधिसूचना के प्रधीन छूट थीं जा रही है, या

(4) यह अधिनियित करने कि क्या उक्त अवधि के द्वारान, जब उक्त कारबाने के संबंध में अधिनियम के उपर्युक्त प्रवृत्त ये, ऐसे उपवर्धों का अनुपायन किया गया था, निम्नलिखित के लिए मालत होगा, अर्थात्—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक में अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसे सूचनाएँ दे, जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएँ ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारबाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारमालन कर रहा हो यह उपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पवधारी के समझ ऐसी लेखा बहियां और अन्य इस्ताबेजों

जो अक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदर्भ से संबंधित हों, को प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझे दैनी जानकारी जो वह आवश्यक समझे या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक और उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे अक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाये या जिसके बारे में उक्त नियोजक या अन्य पदधारी के पास वह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह अक्ति कर्मचारी है परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबाही या अन्य दस्तावेज को नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उत्पादना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वाधिक प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने का छूट की मंजूरी के लिए महानिदेशालय, कर्मचारी राज्य धीमा निगम का सिफारिश विसम्ब से प्राप्त हुई थी। तथापि वह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां जिनमें कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान को गई थी भ्रमी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वाधिक प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी अक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[स० एस० 38017/5/73-एच आई]

S.O. 4238.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government Telegraph Stores, Bombay, belonging to the Government of India in the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs Board are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3185 dated the 25th November, 1974, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th January, 1975 upto and inclusive of the 14th January, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employers continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. S-38017/5/73-HI]

मई विल्सो, 12 सिसम्बर, 1975

का० आ० 4239.—कर्मचारी राज्य धीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रत्येक अक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार (1) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला (2) विष्वेष्वरिया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संस्थालय, बंगलौर (3) प्रादेशिक अनुमधाम प्रयोगशाला, हैदराबाद (4) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान, मैमूर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 17 नवम्बर, 1974 से 16 नवम्बर, 1975 तक जिसमें यह विन भी सम्मिलित है, एक बर्ष की प्रवधि के लिए छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है अर्थात्—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जहां कर्मचारी नियोजित है एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाधिकार दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रतिविधाएँ प्राप्त करते रहेंगे जिनके बीच इस अधिसूचना में वी गई छूट के प्रवर्त दोनों की तारीख से पूर्व अभिवायों के प्राधार पर हकदार हो गए हों;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे आपिस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की आवत जिसके द्वारा यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है),

ऐसी विवरणियां ऐसे प्रैरूप में और ऐसी विशिष्टियों गहिरा देगा जो उस कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी चीज़ी ।

(5) निगम द्वारा, उक्त प्रधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राक्षिकृत किया गया हो—

- (1) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वीर गई किसी विवरणी में वीर गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या
- (2) यह प्रधिनियिकृत करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की भावन, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 हारा यथावेक्षित रजिस्टर और प्रभिलेख रखे गए थे ; या
- (3) यह प्रधिनियिकृत करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक नक्काश और वस्तु के रूप में दिए जाने थाए उन फायदों को पाने के अव भी हकदार हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस प्रधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है ; या
- (4) यह प्रधिनियिकृत करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में प्रधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त है, ऐसे उपबन्धों का अनुकालन किया गया था, निम्नसिद्धित के लिए भवत्ता होगा, प्रथम—

 - (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ने सूचनाएँ दें जो उपरोक्त या निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएँ ; या
 - (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के प्रधिनियां कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी लेये बहिरांग और अस्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, को प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझे, जैसी जानकारी दें ; या
 - (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके प्रभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाएँ या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विवाद फरने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या
 - (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेबाबही या अन्य दस्तावेज की नकल लेयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना ।

प्राक्षिकृत जापन

इस मामले में छूट को पूर्वांकी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने को छूट प्रदान करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा नियम की सिफारिश केवल जून, 1975 में ही प्राप्त हुई थी । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां, जिन में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वांकी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं जालेगी ।

[सं० एम 38017/13/74-एच आई]

ज० सी० सकैना, प्रबन्ध सचिव ।

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4239.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts (1) National Aeronautical Laboratory, Bangalore (2) Visvesvaria Industrial and Technological Museum, Bangalore. (3) Regional Research Laboratory, Hyderabad and (4) Central Food Technological Institute, Mysore from the operation of the said Act for a period of one year with effect from the 17th November, 1974, upto and inclusive of the 16th November, 1975.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations ; 1950 ;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received only in June, 1975. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. S. 38017(13)/74 HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई विल्ली 8 सितम्बर, 1975

का० आ० 4240.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैग्नीज की खानों में नियोजित कर्मकारों के उन प्रवर्गों को, जो इससे उपावच अनुसूची के स्तरम् 1 में विनिरिष्ट हैं, ऐसे मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जैसी कि वे उपरोक्त अनुसूची के स्तरम् 2 में तरसंबंधी प्रविलिंग में विनिरिष्ट हैं, नियत करने के लिए, की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, उन सभी शक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह सूचना भी वी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के अवधान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिरिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी आक्षेप या सुशाव आप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

मैग्नीज खान

मकुशल

(1) आया (2) बट्टलर (3) रखवाला (4) चौकीवार (5) कलीनर (6) ड्रैगर (7) मजदूर (8) लौडर (9) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (10) संदेशवाहक (11) नम्बर टेकर (12) कार्यालय परिचर (13) चपरासी (14) पिकर (पुरुष/स्त्री) (15) छटार्कार (16) छाइकश (पुरुष/स्त्री) (17) द्रिमर (18) डालीवाला (19) दूली द्विपर (20) जल वाहक (21) अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं आहे वे किसी भी नाम से जात हों।

5.80

प्रधंकुशल/मकुशल पर्यवेक्षी

- (1) बैंकमैन (2) बैंकर (3) रोकड़ गाड़ (4) बैंकर (5) रसोइया (6) धोबी (पुरुष/स्त्री) (7) कार्यालय (8) भ्रीजर (9) ग्राहंडर (10) हपोडिया (11) मदवगार (बड़ई, कूशर प्रवालक) (12) जमावार (13) खलासी (बुलडौजर प्राइ) (14) कक्ष प्रभासी (15) मेट/माली (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन अपेक्षित प्रमाण पद रहित) (16) लिपिकीय कर्मचारी जो मैट्रिकुलेट न हों (17) तेलवाला (18) प्लाइट मैन (19) सेम्पलर (20) भाष्टारक (21) अन्य प्रवर्ग जो अधंकुशल/मकुशल पर्यवेक्षी हैं आहे वे किसी भी नाम से जात हों।

7.25

कुशल

- (1) असेपर (2) चर्मकार (3) उत्सफोटक (शाट फायरर) (4) बहई (5) चार्जमैन (6) रसायनज (7) कम्पाऊंडर (8) शिशु परिचर (9) नक्षा नवीस (10) ड्रिलर (11) ड्राइवर (12) विजली मिस्ट्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) राजगीर (16) यांत्रिक (17) दार्मी (18) मिस्ट्री (19) सापेकार (20) प्रचालक (21) भोवर-सीयर (22) पेंटर (23) पार्सिप फिटर (24) पर्यवेक्षक (25) सर्वेक्षक (26) टीनकार (27) टिम्बरमैन (28) टर्नर (29) बैल्डर (30) वायरमैन (31) वर्क गरफार (32) अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं आहे वे किसी भी नाम से जात हों।

8.70

लिपिकीय

- (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) भाष्टार-पाल (5) प्रध्यापक (6) टाइम-कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं आहे वे किसी भी नाम से जात हों।

8.70

इस अधिसूचना के प्रयोगजन के लिए स्पष्टीकरण

1. प्रस्थापित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरे हैं जिनमें भाष्टारी वर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत पर किए गए प्रवायों, यदि कोई हों, का नक्शी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ऐकेश्वरों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. भठारह वर्ष से कम प्राप्य के या प्रसमर्थ अवक्षितयों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें उपर्युक्त अनुसूची में समुचित प्रवर्ग की उल्लिखित दरों का 70 प्रतिशत होंगी।

4. (क) अकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता का कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं,

(ख) अधंकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अंजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी 'आता है;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अधिक शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अंजित कुशलता

या मक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ?

5. जहां मनिदा/करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोगनार्थ न्यूनतम मजदूरी ममझी जाएंगी और लागू की जाएंगी ।

[सं० एस० 32019(10)/75-डल्यू० सी० (एम० डल्यू०)]

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 4240.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in manganese mines specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of period specified above will be considered by the Central Government.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Manganese Mines	
Unskilled :	
(1) Ayah, (2) Butler, (3) Care taker, (4) Chowkidar, (5) Cleaner, (6) Dresser, (7) Labourer, (8) Loader, (9) Mazdoor (Male/Female), (10) Messenger, (11) Number-taker, (12) Office Boy, (13) Peon, (14) Picker (Male/Female), (15) Sorter, (16) Sweeper Male/Female, (17) Trammer, (18) Trolleyman, (19) Trolley triper, (20) Water Carrier, (21) Other categories by whatever name called which are unskilled.	5.80
Semi-skilled/Unskilled Supervisory :	
(1) Bankman, (2) Brakesman, (3) Cash Guard, (4) Checker, (5) Cook, (6) Dhobi (Male/Female), (7) Fireman, (8) Greaser, (9) Grinder, (10) Hammerman, (11) Helper, (12) Carpenter, Crusher operator, (12) Jamadar, (13) Khalasi (Buldozer, etc.), (14) Lamp Room Incharge, (15) Mate/Mali (without competency certificate under MMR 1961), (16) Oilier, (17) Pointsman, (18) Sampler, (19) Storeman, (20) Other categories by whatever name called which are Semi-skilled/Unskilled Supervisory.	7.25
Skilled :	
(1) Asayer, (2) Black-smith, (3) Blaster (Shot firer), (4) Carpenter, (5) Charge-man, (6) Chemist,	

1	2
(7) Compounder, (8) Creche Attendant, (9) Draughtsman, (10) Driller, (11) Driver, (12) Electrician, (13) Fitter, (14) Foreman, (15) Mason, (16) Mechanic, (17) Midwife, (18) Mistry, (19) Moulder, (20) Operator, (21) Overseer, (22) Painter, (23) Pipe-Fitter, (24) Supervisor, (25) Surveyor, (26) Tin-smith, (27) Timberman, (28) Turner, (29) Welder, (30) Wireman, (31) Work-sarker, (32) Other categories by whatever name called which are skilled	8.70
Clerical :	
(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register-keeper, (4) Store-keeper, (5) Teacher (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical	8.70

EXPLANATIONS FOR THE PURPOSES OF THIS NOTIFICATION

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 8 years of age or for disabled persons shall be 70% of the rates payable to the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skills or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skills or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[S-32019(10)/75-WC(MW)]

नई दिल्ली, 9 सिनम्बर, 1975

का० आ० 4241.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार के पूर्व धर्म और रोजगार मंवालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1659 तारीख 27 जून, 1960 के साथ, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के बंद (III) के साथ, पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के गज्जों में स्थित अन्नक खानों में नियोजित कर्मकारों के लिए न्यूनतम

मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए तथा उक्त विनियिष्ट राज्यों से भिन्न राज्यों में स्थित अधिक द्वारों में नियंत्रित कर्मकारों के उन प्रवर्गों के, जो इससे उपरान्त सूची के स्तरमें 1 में विनियिष्ट हैं, देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की, जैसी कि वे उपरान्त प्रत्युत्तमी के स्तरमें 2 में तस्वीरधी प्रविष्टि में विनियिष्ट हैं, जिसके लिए की गई नियन्त्रित प्रस्थापनाओं को, उक्त अधिनियम की घारा 5 की उपचारा (1) के बाद (2) की अपेक्षानुमार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह सूचना भी भी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से तीन मास के अवधार के पश्चात विभार किया जाएगा।

उक्त विनियिष्ट अधिकार के अवधार के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी अक्षय या सुक्षम प्राप्त होंगे केवल यहां पर सरकार उन पर विभार करेगी।

न्यूनतम

कर्मचारियों की श्रेणियां

न्यूनतम

मजदूरी की
प्रतिविन दर

1

2

रु १०

मजदूरी

मजदूर (पुरुष और स्त्री) फलीन, सफाई परिष्वर, संदेश वाहक / कार्यालय परिष्वर, पहरेवार, खलासी, सहायक, पानीवाला, मददगार, भारवाहक, कुली, माली, कोई अन्य प्रवर्ग जो मजदूरी है, जाहे वे किसी भी नाम से जात हों

5.80

प्रधानमंत्री

हस्तियां, प्रधान कुली, अधिक काटने भाला—श्रेणी 2, छटाइकार, ड्रेसर—श्रेणी 2, गेंग कर्मकार, डिस्क कर्मकार, परिष्वर, रसोइया, विस्फोटक बाहक, गनमैन, वार्डिंग हैंजन ड्राइवर—श्रेणी 2, शीघ्रर, वेस्ट कटर, सहायक फिटर, कोई अन्य प्रवर्ग जो प्रधानमंत्री के हैं, जाहे वे किसी भी नाम से जात हों

7.25

कुशल

क्रिल, उत्स्फोटक, मिस्ट्री, अधिक काटने वाला—श्रेणी 1, बड़ी, लोहार डेसर श्रेणी 1, लनन मैट, हैंजन ड्राइवर, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्ट्री, सांचेकार, बैलर, वाहन ड्राइवर, राजगीर, वार्डिंग हैंजन ड्राइवर श्रेणी 1, फायर-मैन, शाट फायर, कम्प्रेसर ड्राइवर, यांविक, पम्प फैन ड्राइवर, ग्राउन्डर, सिरवार, लेथमैन, कोई अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं, जाहे वे किसी भी नाम से जात हों

8.70

लिपिकीय

लेक्षापाल, टक्क/प्राणुलिपिक, लिपिक कम्पाउन्डर, बाण्डरारक प्रभारी, परी प्रभारी, टाइपस्कीपर, रोकड़िया, प्राणुगृह परिष्वर, पर्यवेक्षी, कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय है, जाहे वे किसी भी नाम से जात हों

8.70

इस अधिसूचना के प्रयोगन के लिए स्पष्टीकरण

(1) प्रस्थापित मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं जिनमें प्राक्षारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के खियात

पर पिए गए प्रदायों, यदि कोई थों, का नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साधारण विभास के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें देक्षणार्थी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) जहां संविधान/करार आविष्ट पर आधारित मजदूरी की विधि-मान दरें अधिनियम के आधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोगनार्थ यूनतम मजदूरी समझी जाएंगी और दागू की जाएंगी।

(4) (क) अकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हों;

(ख) अधिकुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम शिक्षु के क्षण में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[एम० 32019(2)/72-डस्ट्यू० ई० (एम०-डस्ट्यू०)]

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4241.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and also read with the notification No. S.O. 1659 dated the 27th June, 1960 of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment for revising the minimum rates of wages for employees employed in Mica Mines situated in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan and fixing the minimum rates of wages for employees employed in mica mines situated in the States other than those referred to above as specified in column 2 of the schedule annexed thereto, payable to the categories of employees specified in the corresponding entries in column 1 of the said schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the Gazette of India.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the said period will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
1	2

UNSKILLED :

Male and Female Cleaner, Scavenger, Messenger/Office Boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Coolies Mali, any other categories by what soever name called which are of unskilled nature

5.80

1	2
R. S. P.	
SEMI SKILLED :	
Hamerman, Head Cooly, Mica cutter Grade-II Sorter, Dresser Grade II, Gauge Worker, Disc Worker, Attendant, Cook, Explosive Carrier, Gun Man, Winding Engine Driver Grade-II Shoarers Waste Cutter, Assistant fitter, any other categories, by what so ever name called, which are of semi-skilled nature.	7.25
SKILLED :	
Driller, Blaster, Mistry, Mica Cutters, Grade I Carpenter, Blacksmith, Dresser Grade-I, Mining Mate Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle Driver, Mason, Winding Engine Driver Gr. I, Fireman, Shot Firer Compressor Driver, Mechanic Pump Fan Driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by what so ever name called which are of skilled nature	8.70

CLERICAL :

Accountant, Typist/Steno Clerk, Compunder, Storekeeper/Incharge, Shift Incharge, Time Keeper, Cashier, Crecho Attendant, Supervisory, any other categories by what so ever name called which are of clerical nature.	8.70
--	------

Explanation.—For the purpose of this notification,—

(1) The minimum rates of wages proposed are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concession, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest,

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also;

(3) Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated as minimum wages;

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019(2)/72-WE(MW)]

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० अ० 4242.—लेन्ड्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी घण्टियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (I) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोक्साइट की जारी में नियोजित कर्मकारों के उन प्रवर्गों को जो इससे उपादान अनुसूची के स्तम्भ 1 में विविधिष्ट हैं, देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को जैसा कि वे उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तस्मान्दी प्रविष्टि में विविधिष्ट हैं, नियत करते के लिए की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को, उक्त प्रधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अवधानुसार, उन सभी व्यक्तियों

की जागकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है। यह मूलमा भी भी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से-तीन मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

अपर विनियिष्ट प्रधिति के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जो भी व्यापेय या सुनाव प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

मजदूरों की विमप्रतिदिन न्यूनतम दर

रु. पै०

बोक्साइट धारा

पर्वतकुशल

(1) एलीनर (2) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (3) लालक (4) कार्पालिय पर्लिय (5) लपराती (6) लिकर (पुरुष/स्त्री) (7) लाइकल (8) लोकीदार (9) पानी लाहक (10) प्रन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं, जाहे वे किसी भी नाम से जात हों।

5.80

पर्वतकुशल/प्रकुशल पर्वतकुशल

(1) सहायक ब्रिलर (2) बुलडोजर ल्यासी (3) लड्डे सहायक (4) कूशल प्रवालक सहायक (5) कैटील पर्लियर (6) माली (7) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्रमता प्रमाण पत्र रहित) (8) मुकद्दम (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्रमता प्रमाणपत्र रहित) (9) रीम्पलर (10) ट्रूल लार्पेनर (11) प्रन्य प्रवर्ग जो प्रकुशल पर्वतकुशल हैं, जाहे वे किसी नाम से जात हों।

7.25

कूशल

(1) लर्मेनर (2) उत्स्कोटक (शाट फायरर) (3) लड्डे (4) कूशल प्रवालक (5) परिसर (6) कम्पीसर ब्रिलर (7) ब्रिलर (8) ड्राइवर (9) मिस्ट्री (10) फिटर (11) यांत्रिक (12) मेट (एम० एम० नियम, 1961 के अधीन सक्रमता प्रमाणपत्र रहित) (13) लेस्टिलालित शावर प्रवालक (14) पम्प ड्राइवर (15) बिजली घोर पम्प हाउस प्रवालक (16) पम्प प्रवालक (17) पर्वतेक्षक (18) ट्रेक्टर प्रवालक (19) प्रन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं जाहे वे किसी भी नाम से जात हों।

8.70

लिपिकीय

(1) लिपिक (2) मूली (3) मालुलिपिक (4) टंकक (5) प्रन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं जाहे वे किसी भी नाम से जात हों।

8.70

इस प्रधिसूचना के प्रयोग के लिए स्पष्टीकरण :-

1. प्रस्थापित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह खत्ता, आवश्यक वस्तुओं के खिलाफ पर किए गए प्रवायों, मवि कोई हों, का नक्दी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें डेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के या प्रसवयन्त्र अवक्षितयों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें उत्तर्युक्त अनुयूची में समुचित प्रवर्ग की उत्तिक्षित दरों का प्रतिशत होगा।

4. (क) अकृशल कार्य वह कार्य है जिसमें कहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव अपेक्षित न करने वाली संधारण कियाएं समिलित हैं।

(घ) अर्धकृशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव में अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या क्षमता गम्भीरता है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यावरण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने के योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकृशल पर्यावरणी कार्य भी आता हैं;

(ग) कुशल कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य अनुभव में अवश्य के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के साध्यम से अर्जित कुशलता या क्षमता अपेक्षित है और जिनके पालन में स्वप्रेरणा और विकेत बुद्धि आवश्यक है।

5. जहां सेविया/करार आदि पर आधारित मजदूरी की विधमान दरे अधिनियम के अधीन अधियूचित दरों से उच्चतर है, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोगनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएगी और लागू की जाएगी।

[सं० एस-32019(11)/75-एक्स्यू०सी०/(एम० इक्स्य०)]

हस राज छाड़ा, उप मन्त्रिय

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4242.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 readwith clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in bauxite mines specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.	Rs. P.
(1)	(2)	
Bauxite Mines		
Unskilled :		
(1) Cleaner, (2) Mazdoor (Male/Female), (3) Miner, (4) Office Boy, (5) Peon, (6) Picker (Male/Female), (7) Sweeper, (8) Watchman, (9) Water Carrier, (10) Other categories by whatever name called which are unskilled.	5.80	

(1)	(2)	Rs. P.
Semi-skilled/Unskilled Supervisory :		7.25

(1) Assistant Driller, (2) Bull-Dozer Khalasi (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Gardener/ Mali, (7) Mate without competency certificate under MMR-1961, (8) Maccadum (without competency certificate under MMR-1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharpener, (11) Other Categories by whatever name called which are semi-skilled unskilled supervisory.	8.70
---	------

Skilled :

(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) Carpenter, (4) Crusher Operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller, (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Male (with competency certificate under MMR-1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendant, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Other categories by whatever name called which are skilled.	8.70
--	------

Clerical :

(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical	8.70
--	------

Explanations for the purposes of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age or for disabled persons shall be 70% of the rates payable to the appropriate category as specified in the schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skills or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skills or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S.32019(11)/75-WC(MW)]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० आ० 4243.—भारत सरकार के भूतपूर्व अम और पुनर्जीवन मंत्रालय (अम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संघ्या का० आ० 1698, तारीख 12 अप्रैल, 1972 द्वारा गठित शिमला में स्थित अम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है;

प्रत: अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री शमशेर मिहं कंवर को यथा पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का वीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या एस०-11025/19/75-डी ए]

एस० एस० सहस्रनामन्, उप सचिव

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4243.—Whereas, a vacancy has occurred in the office of the presiding officer of the Labour Court at Simla constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1698, dated the 12th April, 1972;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Shamsher Singh Kanwar as the presiding officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11025/19/75-DIA]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 मिशन्स्टर 1975

का०आ० 4244.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुभवण में, वर्ष 1975-76 के दौरान कोयला खान विभिन्न गृह और साधारण कल्याण निधि के साधारण कल्याण खाने में प्राप्तियों और उसमें से व्यय का निम्नलिखित प्राप्तकलन, वर्ष 1974-75 के लेखा विवरण सहित, तथा वर्ष 1974-75 के दौरान उक्त निधि के साधारण कल्याण खाने में से वित्तपोषित कार्यकलापों की रिपोर्ट, प्रकाशित करती है, अर्थात्:

भाग--I

1975-76 के दौरान प्राप्तियों और व्यय का प्राप्तकलन साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
रु०	रु०
4,12,24,400	3,18,90,000

भाग--II

वर्ष 1974-75 का लेखा-विवरण साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
1. 1-4-1974 को प्रारंभिक अतिशेष	
(--)	14,86,864
2. वर्ष के दौरान व्यय	3,10,99,209(क)
3. वर्ष के दौरान प्राप्ति	3,74,81,600
4. 31-3-1975 को अन्तिम अतिशेष	48,85,527
3,59,94,736	3,59,94,736

(क) इसमें कोयला खदानों के स्थानियों को ग्रौषधालय सेवाएं बताए रखने के लिए दिया गया 8209 रु० का 'उधार'।

टिप्पणी:—अपर लिखा ए गए आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि महालेखा-पाल, बिहार से अभी 1974-75 का लेखा बन्द नहीं किया है।

भाग--III

वर्ष 1974-75 के दौरान वित्तपोषण कार्यकलापों की रिपोर्ट

1. चिकित्सा सुविधाएँ :

(क) अस्पताल : तीम केन्द्रीय अस्पताल अर्थात् असनसोल और मानेन्ड्रगढ़ में एक-एक, और विभिन्न कोयला थेट्रों में स्थित 12 केन्द्रीय अस्पताल, कार्य करते रहे। असनाद, असनसोल और मानेन्ड्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की शैया संक्षय कमशः 300, 350 और 100 पी। चान्दा कोयला थेट्र में एक केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना के बारे में सक्रिय रूप से विचार जारी है। अस्पताल को बलारपुर में स्थापित करने के लिए अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है। तलचर कोयला थेट्र में राष्ट्रीय कोयला विकास नियम के अस्पताल में, निधि द्वारा उस कोयला थेट्र में एक केन्द्रीय अस्पताल की व्यवस्था के विकल्प के रूप में योग्यता तथा अनावर्ती मनुदान देते हुए एक विशेषजांड की व्यवस्था के बारे में सक्रिय रूप से विचार जारी है।

(ख) ग्रौषधालय :—मुम्मा कोयला थेट्र में एक एलोर्पैथिक स्थानीय ग्रौषधालय, भस्म कोयला थेट्र में एक चल विकित्या एक और विभिन्न कोयला थेट्रों में 29 ग्रौषुर्वेदिक ग्रौषधालय कार्य करते रहे। ग्रौषेवित ग्रौषुर्वेदिक ग्रौषधियों के विनियम के लिए स्थानीय कोयला थेट्र में पारार्डीह में स्थापित ग्रौषुर्वेदिक ग्रौषधालय भी कार्य करती रही।

(ग) कुटुम्ब कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र :—संगठन के प्रत्येक केन्द्रीय अस्पताल से संलग्न कुटुम्ब कल्याण केन्द्र कार्यरत रहा। इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा विभिन्न कोयला थेट्रों में पहले से स्थापित ऐसे केन्द्र ग्राहित महिला-स्वास्थ्य-परिवर्षकों के भारताधन में स्वतंत्र एकों के रूप में कार्य करते रहे। चान्दा कोयला थेट्र के कोयला खान कर्मकारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल, चान्दा से संलग्न ल्लाक बराबर काम करता रहा।

(घ) ग्रौषधालय सेवाओं को सुधारने के लिए विसीय सहायता :—कोयला खदान कर्मकारों और उनके ग्राहियों के फायदे के लिए कोयला खदानों में कोयला खदान प्रबन्ध तंत्रों की ग्रौषधालय सेवाओं को स्तरमान सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के विकार से सहायतार्थ अनुदान देने की स्कीम चालू रखी गई तथा कोयला खान प्रबन्धकों को इस वर्ष के दौरान कोयला खान के कर्मकारों के लिए ग्रौषधालय सेवाएं प्रदान करने के लिए 10.72 लाख रुपये (प्राकलित) की रकम दी गई। कोयला खदान स्थानियों को अपने कर्मकारों के फायदे के लिए अधिक ग्रौषधालय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विसीय सहायता देने की स्कीम भी चालू रखी गई। इस अवधि के दौरान 8,209.00 रु० की र.पि 'उधार' के रूप में दी गई।

(ङ) अयोग्यी उपाय :—शय पीड़ित कोयला खदान कर्मकारों "ग्रौर उनके ग्राहियों के हलाज के लिए संगठन के अपने यक्षमा अस्पतालों में 312 शैयाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्षमा ग्राहोग्याश्रमों में 61 शैयाएं ग्राहित रहीं। यक्षमा की गृहोपचर्या की स्कीम चालू रखी गई और इस स्कीम के प्रभाव इसाज करने वाले यथा रोगी को अनुसूची के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाना भी चालू रहा। उस प्रबन्ध के दौरान इस स्कीम पर 6.40 लाख रु० (प्राकलित) की राशि व्यय की गई।

(ज) परिवार नियोजन सेवाएँ :—कोयला खान अमिक कल्याण निवि के अस्पतालों में तथा उस प्रयोजन के लिए विभिन्न कोयला थेट्रों में खोली गई क्लीनिकों में परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त सलाह और निरोगी

का मुफ्त वितरण बराबर चलता रहा। कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए सहायक अनुदान के संबंध की स्कोम प्रभावशील रही आई। 11 परिवार नियोजन केन्द्र, जिनमें से घनबाद / कल्ला केन्द्रीय अस्पतालों में एक-एक और शेष 9 नियंत्रित के विभिन्न क्षेत्रों अस्पतालों में कार्य करते रहे।

(ल) पुनर्वासि:— घनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक के साथ संलग्न पुनर्वासि केन्द्र कार्य करते रहे। मध्य प्रदेश कोयला खेत में छिन्नबाड़ा स्थित पुनर्वासि केन्द्र कार्य करता रहा। परिवारी बंगाल में सिद्धार्थी में पुनर्वासि एवं रोगनिक्तालय आगम्भ करने का प्रश्न अभी भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ज) मन्य चिकित्सकीय कार्यकलाप: चिकित्सकीय और सोक स्वास्थ्य की दिशा में इस संस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं—केंसर, कोइला और मानसिक रोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, अनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त बैंक चलाना, खदान कर्मकारों को ऐनको और कूद्रिम दंतावली का मुफ्त प्रदाय, मलेरिया तथा फिलेरिया केन्द्रीय संचालन कार्य आदि, आदि।

2. शैक्षिक तथा आमोद-प्रमोद विधायक सुविधाएँ :

(क) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश में लाने वाले कुछ सुसंगत अंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(1) बहुउद्दीप संस्थान	61
(2) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	63
(3) महिला कल्याण केन्द्र	61
(4) पीपक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	147
(5) कोयला कर्मकारों के बच्चों की आवृत्तियाँ	546
(6) विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आवास	1
(7) अवकाश-नगृह	2

(झ) खेल और श्रीड़ा: कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और श्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1974-75 के दौरान विभिन्न खेलों और श्रीड़ाओं के आयोजन के लिए संगठन द्वारा 1,08,559 रु की रकम खर्च की गई।

(ग) मन्य क्रियाकलाप: इस संबंध में दो गई मध्य सुविधाओं में (1) शैक्षिक संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान, (2) कोयला खनिकों के आप्रितों को आवृत्ति (3) कोयला खनिकों के लिए श्रीड़ा और खेल-कूद की व्यवस्था, (4) फिल्मों का प्रदर्शन, (5) लानों में दुर्बंधनाओं में मरने वाले कोयला खदान कर्मकारों की परिनियंत्रण और विद्यालय जाने वाले बच्चों को विशेष सहायता की व्यवस्था आदि, हैं।

3. जल-प्रदाय स्कीम: इस वर्ष के दौरान 3,73,456 रु की रकम जल-प्रदाय स्कीमों पर खर्च की गई है। यह संगठन, जल-प्रदाय स्कीमों में विहित के अनुसार, व्यय के कुल खर्च के 50 प्रतिशत तक सहायतार्थ अनुदान देती रही। परिवारी बंगाल और बिहार राज्य सरकारें द्वारा निष्पातित, नियंत्रित, स्कीमें कार्यधीन हैं।

कूदों की खुराई:— अब तक पूरे किए गए कूदों की संख्या 259 है। रिपोर्ट से संबंधित प्रवधि के दौरान, विभिन्न कोयला खेतों में 8 न्युए खोदने की स्वीकृति दी गई थी।

4. सहकारी आन्दोलन: इस वर्ष कीई भी नए प्राइमरी स्टोर, सहकारी प्रवधि दोसायटी और थोक या केन्द्रीय सहकारी स्टोर नहीं खोले गए। पुनर्गीष्णात्री अन्धि के घन्त में कोयला खदानों के कर्मकारों के सहकारी

स्टोरों और प्रत्येक सोसाइटियों की संख्या 581 थी। इनमें 12 थोक या केन्द्रीय सहकारी स्टोर भी थे जो संगठन द्वारा पहले ही खोले गए थे।

[सं. जैड 16016/6/75-एम II]

बी० के० सम्पेता, उप सचिव

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O.4244—In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the general welfare account of the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund during the year 1975-76 together with a statement of the account for the year 1974-75 and a report on the activities financed during the year 1974-75 from the general welfare account of the said Fund, namely:—

PART-I

Estimates of Receipts and Expenditure during 1975-76

GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt	Expenditure
Rs. 4,12,24,400	Rs. 3,18,90,000

PART-II

Statement of Account for the year 1974-75

GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt	Expenditure
1. Opening balance as on 1-4-1974	(—)14,86,864
2. Expenditure during the year	3,10,99,209(a)
3. Receipt during the year	3,74,81,600
4. Closing balance as on 31-3-1975	48,95,527
	3,59,94,736
	3,59,94,736

(a) Includes Rs. 8,209 being 'Loan' to Colliery owners for maintenance of dispensary services.

N.B. The figures shown above are provisional as the account for 1974-75 has not yet been closed by the Accountant General, Bihar.

PART-III

Report on Activities financed during the year 1974-75

1. Medical Facilities :

(a) Hospitals : The 3 Central Hospitals, one each at Dhanbad, Asansol and Manendragarh and 12 Regional Hospitals situated in different coalfields continued to function. The bed strength of the Central Hospital at Dhanbad, Asansol and Manendragarh was 300, 350 and 100 respectively. The proposal for the establishment of a Regional Hospital in Chanda Coalfield remained under active consideration. The Hospital has finally been decided to be set up at Ballarpur. Provision of a specialised ward in the National Coal Development Corporation's Hospital in Talcher Coalfield by giving suitable recurring and non-recurring grant as an alternative to Fund's providing a Regional Hospital in that Coalfield remained under active consideration.

(b) Dispensaries : One Allopathic Static dispensary in Mugma Coalfield, one Mobile Medical Unit in Assam Coalfield and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields continued to function. The Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdhin in Jharia Coalfield to manufacture required Ayurvedic Medicine also continued to function.

(c) Family Welfare and Maternity and Chief Welfare Centres : A family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals of the Organisation remained in operation. Besides, 8 such Centres already established by the Organisation in various coalfield areas also continued to function as independent units under the charge of qualified Lady Health Visitors. For the benefit of the colliery workers in Chanda Coalfield, the block attached to the Government Hospital, Chanda continued to function.

(d) Financial Assistance for Improving Dispensary Services : With a view to encourage the colliery management for improving the standard of dispensaries at the collieries for the benefit of colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 10.72 lakhs (estimated) was paid to the colliery management during the year for providing medical facilities to the colliery workers. In order to encourage the colliery owners to provide more dispensary services for the benefit of their workers, the scheme of payment of financial assistance was also continued. A sum of Rs. 8,209.00 was paid as loan during the period.

(e) Anti T.B. Measures : For the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T.B. besides provision of 312 beds at the Organisation's own T.B. Hospitals, 61 beds remained reserved for them in different T.B. Sanatoria. The Scheme of Domiciliary T.B. treatment continued to function and payment of subsistence allowance to the T.B. patients undergoing treatment under the Scheme also continued to be made according to schedule. A sum of Rs. 6.40 lakhs (estimated) was incurred on this scheme during the period.

(f) Family Planning Services : Free advice on Family Planning continued to be given and contraceptives supplied free of cost at the coal Mines Labour Welfare Fund's Hospitals and at the clinics opened for the purpose in various coalfields. The scheme for the payment of grant-in-aid to the colliery owners for the Family Planning work continued to be in force. 11 Family Planning Centres one each at the Central Hospital Dhanbad/Kalla and the remaining 9 at the different Regional Hospitals of the Fund were in operation.

(g) Rehabilitation : The Rehabilitation Centres attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to function. The Rehabilitation Centre at Chhindwara in Madhya Pradesh Coalfield continued functioning. The question of commissioning the Rehabilitation-cum-Convalescent Home at Sidhabari in West Bengal Coalfield remained on its way.

(h) Other Medical Activities : Other important activities of the Organisation on the medical and public health sides were provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental cases, running of Blood Bank at the Central Hospitals Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures to the colliery workers, Malaria and Filaria Control Operation etc. etc.

2. Educational and Recreation Facilities :

(a) Some relevant statistics highlighting the important activities on this account are given below :—

(i) Multipurpose Institutes	61
(ii) Adult Education Centres	63
(iii) Women Welfare Centres	61
(iv) Feeder Adult Education Centres	147
(v) Scholarship to the children of Colliery Workers	546
(vi) Boarding Houses for school going children	1
(vii) Holiday Homes.	2

(b) Games and Sports : Games and Sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year 1974-75 for organising various games and sports, a sum of Rs. 108559/- was spent by the Organisation.

(c) Other Activities : Other important facilities provided in this connection comprise of (1) grant-in-aid to the Educational Institutions (2) scholarship to wards of coal miners (3) provision for games and sports amongst coal miners (4) exhibition of films (5) provision for financial assistance to the wives and school going children of colliery workers who died of accident in mines.

3. Water Supply Schemes :

During the year, a sum of Rs. 3,73,356/- has been spent on Water Supply Schemes. The Organisation continued to pay grant-in-aid as prescribed in the Water Supply Scheme upto 50% on the total cost of scrutinised expenditure to the colliery managements. Two integrated water supply schemes executed by the State Governments of West Bengal and Bihar partly financed by the Fund remained under execution.

Sinking of wells :

Total number of wells so far completed is 259. During the period under report, sanction was accorded to sinking of one well.

4. Co-operative Movement :

No new Primary Stores, Credit Co-operative Societies and Wholesale or Central Co-operative Stores were opened during the year. The total number of Co-operative Stores and Credit Societies of colliery workers at the end of the period under review stood at 581. These included 12 Wholesale or Central Co-operative Stores already opened and continued functioning for colliery workers.

[No. Z 16016/6/75-MII]

B. K. SAXENA, Dy. Secy.

